वार्षिक रिपोर्ट
2020–21

National Productivity Council

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

विषय सूची

अध्याय 1 – महानिदेशक की कलम से		4
अध्याय 2 – राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में		5
अध्याय 3 – एनपीसी की व्यावसायिक सेवाएं		11
अध्याय 4 – 2020–21 के दौरान एनपीसी गतिविधियों में एक अंतर्दृष्टि		18
4.1	वार्षिक गतिविधियां	18
4.2	निष्पादन हाइलाइट्स	19
4.3	नई पहलें	19
4.4	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन	25
4.5	एनपीसी द्वारा किए जा रहे कुछ बड़े कार्यों का सारांश इस प्रकार है:	30
4.6	माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एनपीसी की 49वीं जीसी बैठक	39
4.7	2020–21 के दौरान शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान और परामर्श परियोजनाओं की चयनित सूची	40
4.8	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चयनित सूची	44
अध्याय 5 – वार्षिक लेखा 2020–21		46

1

महानिदेशक की कलम से

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए औद्योगिक इंजीनियरिंग, कृषि–व्यवसाय, आर्थिक सेवाओं, गुणवत्ता प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए निरन्तर अग्रणी परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करती आ रही है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रथाओं की लगातार समीक्षा की जाती है कि हम सबसे अद्यतन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, सभी विनियमों को पूरा कर रहे हैं और उद्योग की भविष्य की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

हम अनुभवात्मक शिक्षण प्रणाली में विश्वास रखते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरे मनोयोग से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम अखिल भारतीय स्तर पर सीखने के ढेरों अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।

हम उद्योग पेशेवरों के इस तरह से सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं कि वे एक सार्थक और मूल्य–आधारित समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। हमारी टीम ज्ञान के प्रसार और उत्पादकता में सुधार के लिए असीम ऊर्जा और गहन प्रतिबद्धता का प्रर्दशन करती है। मैं ऐसे समर्पित, नवोन्मेषी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के साथ काम करके स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। मैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में अपने प्रत्येक दिन को नए साहसिक अनुभवों और सीख से परिपूर्ण पाता हूँ तथा अपने आयामों के निंरतर विस्तार के अवसर के रूप में देखता हूँ।

एनपीसी ने अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों आदि में सार्वजनिक सेवाओं की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता में वृद्धि की है।

मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अपनी अत्याधुनिक सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने हेतु अनेकानेक अवसर प्रदान कर पाएगा।

(एन.के.चांजी)
महानिदेशक

2

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 1958 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित, यह एक स्वायत्त, गैर–लाभकारी संगठन है, जिसमें तकनीकी और पेशेवर संस्थानों और अन्य हितों के अलावा, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों तथा सरकार का बराबर का प्रतिनिधित्व होता है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं, और सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। तालिका–1 एनपीसी की संगठनात्मक संरचना के बारे में विवरण प्रदान करती है।

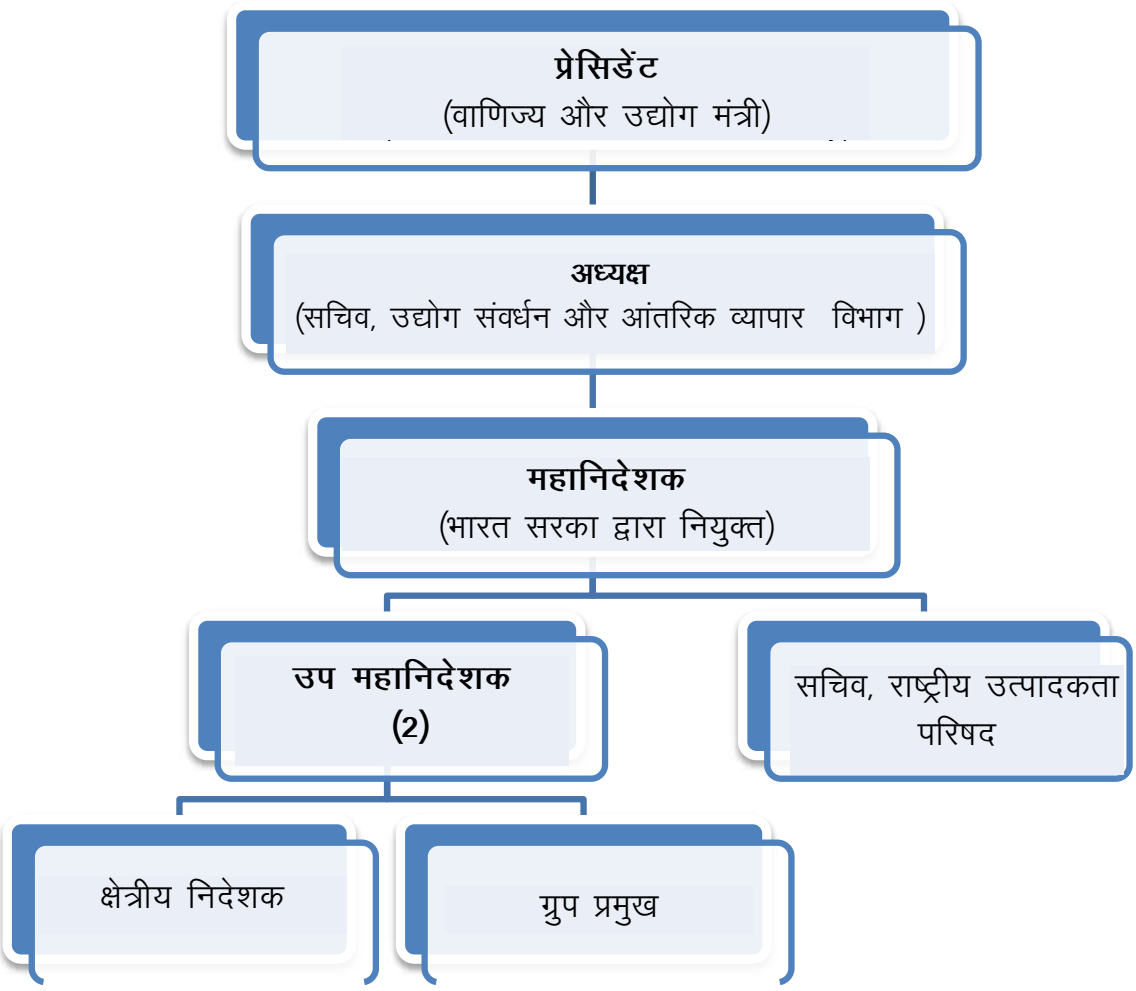

तालिका–1 एनपीसी की संगठनात्मक संरचना

महानिदेशक परिषद के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं। एनपीसी में लगभग 124 पूर्णकालिक पेशेवर/परामर्शदाता हैं, इसके अतिरिक्त बाहरी विशेषज्ञों और शिक्षकों की सेवाएं भी परियोजना–आधारित आवश्यकता अनुसार प्राप्त की जाती हैं। एनपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राज्यों की राजधानियों/औद्योगिक केंद्रों में स्थित हैं, तथा एक प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई में है, जैसा कि मानचित्र–1 में दर्शाया गया है।

एनपीसी की परिकल्पना (विजन), मिशन और उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

क. **परिकल्पना:** विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्पादकता में ज्ञान का मार्गदर्शक बनना।

ख. **मिशन:** उत्पादकता बढ़ाते हुए देश के सतत, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान करना।

ग. **उद्देश्य:**

i. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक द्विआयामी अड़चनों का समाधान करके समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सतत रूप से नवाचार के जरिए उत्पादकता को बढ़ावा देना।

ii. सरकार, व्यवसाय और समाज के बीच उत्पादकता, चेतना और संस्कृति का प्रचार करना।

iii. गुणक प्रभाव के लिए उन्नत उत्पादकता उपकरणों और तकनीकों के उत्पादन और अनुप्रयोग के माध्यम से मूल्यवर्धन को प्रदर्शित करना।

iv. गठबंधन और भागीदारी के माध्यम से जहां कहीं भी आवश्यक हो, प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के

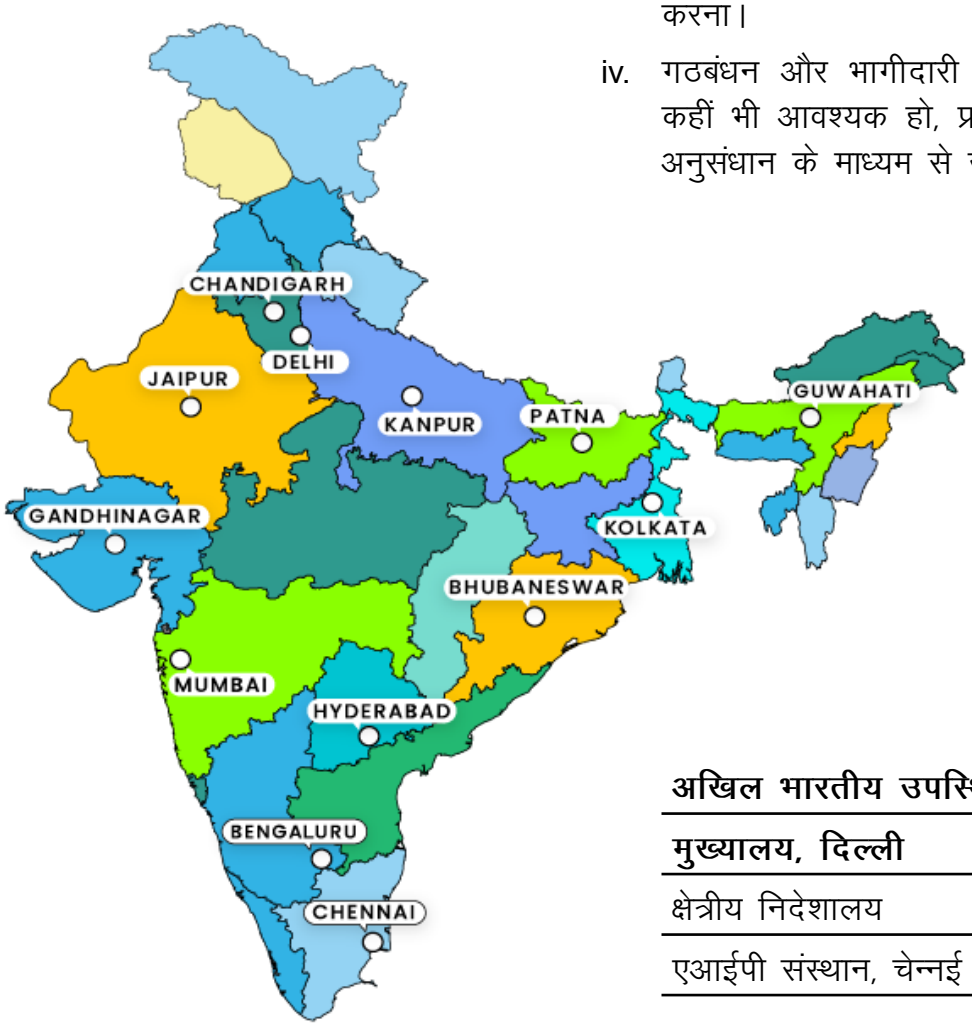

अखिल भारतीय उपस्थिति	
मुख्यालय, दिल्ली	1
क्षेत्रीय निदेशालय	12
एआईपी संस्थान, चेन्नई	1

लिए उद्योग, सेवाओं और कृषि क्षेत्रों के लिए पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में कार्य करना।

v. उत्पादकता गतिविधि की मजबूती हेतु सहयोगी नेटवर्किंग के लिए संस्थागत निर्माण और प्लेटफॉर्म विकसित करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

vi. उभरती प्रवृत्तियों पर नज़र रखने के दौरान उत्पादकता संबंधी साक्ष्य–आधारित नीतिगत सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करना।

vii. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, स्कीमों और हस्तक्षेपों के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण इकाई के रूप में कार्य करना।

viii. पुरस्कारों, संबद्धताओं, प्रमाणनों, प्रत्यायनों आदि के माध्यम से उत्पादकता चौंपियनों को मान्यता प्रदान करना।

ix. पारस्परिक आधार पर उत्पादकता के लाभों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायरे को बढ़ाना।

x. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता डेटा का भंडार होना।

xi. उत्पादकता निदान हेतु सभी क्षेत्रों और स्व–मूल्यांकन वेब–आधारित माप उपकरणों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता मानकों को तैयार करना।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ)

भारत सरकार 1961 से टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ), एक अंतर–सरकारी निकाय की संस्थापक सदस्य है। एनपीसी एपीओ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और उत्पादकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर सदस्य देशों को एपीओ द्वारा पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भारतीय भागीदारी के आयोजन की नोडल एजेंसी प्रभारी भी है। एनपीसी सदस्य देशों के प्रतिभागियों के लिए हर साल भारत में एपीओ कार्यक्रम आयोजित करता है।

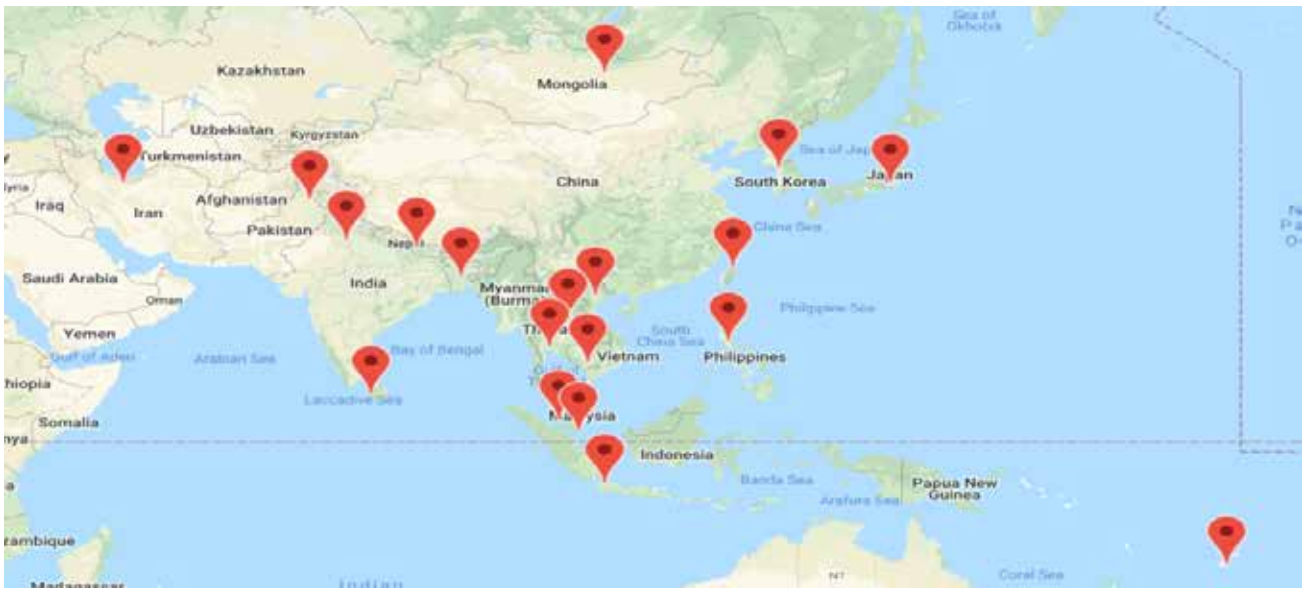

एपीओ सदस्य देश

नेतृत्व और मार्गदर्शन

अध्यक्ष एन.पी.सी.

श्री पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री

माननीय श्री पीयूष गोयल भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ ही वस्त्र मंत्रालय के मंत्री तथा राज्य सभा में सदन के नेता हैं।

वह भारत की संसद के उच्च सदन के सदस्य और राज्य सभा के नेता हैं। पहले वह रेल और कोयला मंत्री (2017–19) थे। उन्होंने 2018 और 2019 में दो बार वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। इससे पहले वह विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (2014 – 2017), और खान मंत्रालय (2016–17) के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे। श्री गोयल के कार्यकाल में भारतीय रेलवे ने 2018–19 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड प्राप्त किया है। यह व्यापक उपायों जैसे ब्राड गेज नेटवर्क से मानव रहित रेलवे क्रासिंग (यूएमएलसी) को समाप्त करने, सुरक्षित डिब्बों के उत्पादन आदि के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री गोयल ने दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली पहली स्वदेशी सेमी हाई–स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ का निरीक्षण किया।

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों ने भारत के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों का नेतृत्व किया, जिसमें देश के कुछ सबसे दूरस्थ और दुर्गम हिस्सों में लगभग 18,000 गैर–विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की तेजी से ट्रैकिंग, विद्युत क्षेत्र में सबसे व्यापक सुधार (उदय) का रोल आउट, ऊर्जा दक्षता के लिए दुनिया के सबसे बड़े एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम (उजाला) की सफलता और विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का व्यापक प्रसार शामिल है। अन्य उपलब्धियों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए कोयले की कमी को दूर करना और कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी ई–नीलामी का सफल संचालन शामिल है। उन्होंने 2018 में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में पथप्रदर्शक परिवर्तनों को मान्यता देने के लिए चौथा वार्षिक कार्नोट पुरस्कार भी प्राप्त किया।

श्री गोयल का शैक्षणिक रिकॉर्ड शानदार रहा है –अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय रैंक धारक चार्टर्ड एकाउंटेंट और मुंबई विश्वविद्यालय में विधि के द्वितीय रैंक धारक, श्री पीयूष गोयल एक प्रसिद्ध निवेश बैंकर रहे हैं और प्रबंधन रणनीति और विकास पर शीर्ष कॉर्पोरेट्स को सलाह देते रहे है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में भी कार्य किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2002 में नदियों को आपस में जोड़ने (इंटरलिंकिंग) के लिए टास्क फोर्स में भी नामित किया गया था।

नेतृत्व और मार्गदर्शन

श्री सोम प्रकाश, आईएएस (सेवानिवृत्त)

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री

माननीय श्री सोम प्रकाश, 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) अधिकारी हैं। उन्होंने 1972 में पंजाब राज्य योजना बोर्ड में एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद, वे पंजाब आबकारी विभाग में एक आबकारी और कराधान अधिकारी बने।

श्री सोम प्रकाश ने फरीदकोट, होशियारपुर और जालंधर के उपायुक्त के रूप में कार्य किया है और श्रम आयुक्त, पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पुडा) के मुख्य प्रशासक, पंजाब वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक जैसे पदों पर भी कार्य किया है। वे फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र (पंजाब) से दो बार सदस्य, विधान सभा (विधायक) भी रहे हैं। अब वे होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं।

नेतृत्व और मार्गदर्शन

अध्यक्ष एन.पी.सी.

श्री अनुराग जैन, आईएएस

सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

श्री अनुराग जैन, आईएएस (एम पी 1989) सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार और एनपीसी के पदेन अध्यक्ष हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

व्यावसायिक सेवाएं

3

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) किसी भी प्रकार की उत्पादकता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ही स्थान पर परामर्श, मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करती है।

क. **उत्पादकता संवर्धनः** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के स्थापना दिवस 12 फरवरी को देश भर में प्रत्येक वर्ष उत्पादकता दिवस और संपूर्ण माह को उत्पादकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ अवधारणा और उत्पादकता उपकरणों और तकनीकों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के प्रति सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित करना है। इस उत्पादकता माह के दौरान देश भर में सभी राज्यों को कवर करते हुए 62 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ख. **परामर्शः** सम्पूर्ण संगठनात्मक स्तर पर उत्पादकता, गुणवत्ता, लाभप्रदता और विकास में सुधार के लिए एनपीसी द्वारा व्यावसायिक परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एनपीसी निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रों, केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग संघों, उनके सदस्यों और अन्य ग्राहक समूहों के परामर्श के माध्यम से उत्पादकता कौशल का संवर्धन और प्रसार कर रही है। प्रति वर्ष 200 से अधिक परामर्श परियोजनाएं पूरी की जाती हैं।

ग. **अनुसंधानः** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता से संबंधित विषयों पर आंकड़े और सूचना एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए परियोजना आधार पर गतिविधि–आधारित अनुसंधान आयोजित करती है। इन विषयों में मौजूदा चुनौतियां और क्षेत्रों की उभरती आवश्यकताएं शामिल हैं।

घ. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः** एनपीसी की प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियां मुख्य रूप से मानव संसाधन विकसित करने पर केंद्रित हैं: ऐसे व्यक्ति जो भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता गतिविधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उद्योग और सेवा, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और स्थानीय / क्षेत्रीय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता प्रबंधन के मुद्दों की एक व्यापक श्रेणी को शामिल करते हैं। एनपीसी प्रतिवर्ष 10000 से अधिक अधिकारियों के कौशल को बढ़ाते हुए 300 से अधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। एनपीसी उभरते मुद्दों और निष्कर्षों पर ज्ञान प्रदान करने और इसके लिए प्रबंधन रणनीति पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय और सैक्टोरल सम्मेलनों का भी आयोजन करती है। यह कार्यालय उद्यमों, सरकारों और अन्य क्षेत्रों के लिए उत्पादकता/गुणवत्ता सुधार से संबंधित मामलों पर अध्ययन, अनुसंधान सर्वेक्षण, मूल्यांकन आदि का संचालन करता है।

ङ. **मॉनीटरिंग और मूल्यांकनः** एनपीसी उत्पादकता मूल्यांकन और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मॉनीटरिंग और मूल्यांकन (एम एंड ई) अध्ययन और विभिन्न सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं और योजनाओं के निष्पादन प्रबंधन, के साथ औद्योगिक प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित निजी क्षेत्र की पहलों में शामिल रही है। एनपीसी ने अपने विभिन्न प्रभागों जैसे आर्थिक सेवाओं, औद्योगिक इंजीनियरिंग/प्रक्रिया प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रबंधन, कृषि–व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं आदि के माध्यम से सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य एजेंसियों के लिए क्षेत्रों और उप

क्षेत्रों में कई प्रकार की परियोजनाएँ चलाई हैं। एनपीसी के पास जीआईएस आधारित एप्लीकेशन से संबंधित जीआईएस सॉफ्टवेयर्स के अलावा साधन हैं जो परियोजना प्रबंधन और योजना के लिए उपयोग किए जाते हैं और डेटा के अर्थमितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त नमूना तकनीक के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। एनपीसी ने सरकार की योजनाओं और अवसंरचना विकास परियोजनाओं सहित वास्तविक समय आधार पर मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए क्लाउड आधारित आईटी प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत करने के लिए और संस्थागत लिंकेज विकसित किया है।

च. **भर्ती**: एनपीसी विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षाएं आयोजित कर रही है जैसे ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स (सीजीपीडीटीएम), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसईएस, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट आदि। एनपीसी के पास भर्ती के लिए पूर्ण समाधान जैसे आवेदन प्रक्रिया, भुगतान गेटवे प्रदान करना, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन परीक्षा का संचालन, प्रश्न पत्र तैयार करना, मूल्यांकन, साक्षात्कार का संचालन आदि के मामले में विशेषज्ञता है। एनपीसी अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करती आ रही है और ट्रेड से संबंधित कौशल परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा भी संचालित करती है।

एनपीसी का उद्देश्य लागत प्रभावी, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया प्रदान करना है और निष्पक्ष, बेहद गोपनीय तथा निर्बाध ढंग से संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना है।

छ. **एआईपी चौन्नई**: डॉ.अंबेडकर उत्पादकता संस्थान एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें चेन्नई में कक्षाओं, छात्रावासों और सुसज्जित औद्योगिक ऊर्जा इकाइयों (उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्यरत) की सुविधाएं हैं। उपर्युक्त सीईटीईई एक उत्कृष्टता केंद्र है और यहां ऊर्जा दक्षता के लिए विभिन्न औद्योगिक उपकरण मौजूद हैं। एआईपी विभिन्न औद्योगिक ऊर्जा उपयोगिता उपकरणों से सुसज्जित है जो व्यावहारिक रूप से ऊर्जा दक्षता अवसरों और उद्योगों में लागू ऊर्जा संरक्षण तकनीकों के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रतिभागी स्वयं ही उपकरणों को संचालित कर सकते हैं और दक्षतापूर्ण संचालन प्रभाव को जानने के लिए ऑपरेटिंग मापदंडों में बदलाव, ऊर्जा बचत मोड को बदलने और निम्नलिखित के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन के लिए परीक्षण कार्य करते हैं:

- पंप प्रशिक्षण सुविधा
- कंप्रेसर प्रशिक्षण सुविधा
- फैन प्रशिक्षण सुविधा
- बॉयलर प्रशिक्षण सुविधा
- स्टीम ट्रैप प्रशिक्षण सुविधा
- ओपन बर्नर प्रशिक्षण सुविधा और
- काम्बुस्टन फर्नेस प्रशिक्षण सुविधा

एनपीसी की कार्यक्षेत्र विशिष्ट सेवाएँ

3.1 कृषि व्यवसाय सेवाएँ:

कृषि व्यवसाय समूह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए सूक्ष्म और वृहद दोनों स्तरों पर कृषि, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए परामर्श और जागरूकता पैदा करने में लगा हुआ है। इसका जोर स्थापनाओं और परियोजनाओं को लागत प्रभावी, लक्ष्य उन्मुखी, गतिशील सामाजिक–आर्थिक वातावरण के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए है ताकि सामाजिक आकांक्षाओं को प्राप्त कर सके।

कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में एनपीसी की ताकत निम्नलिखित में निहित हैं:

- विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों का आंकलन, मॉनीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन
- नीति निर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन
- ऊर्जा और ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण
- सहकारिता संवर्धन
- डाटा बेस का विकास
- फसल उत्पादकता उन्नयन
- कृषि व्यवसाय और फसलों की कटाई के बाद का प्रबंधन
- तकीनीक–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन
- खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और मुर्गी पालन प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादकता मापन और संवर्धन
- खाद्य और कृषि व्यवसाय में मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- प्रशिक्षण, कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन
- एफबीओ और वेयरहाउसों में खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा का आयोजन
- एशियन उत्पादकता संगठन के साथ मिल कर एक स्मार्ट कृषि हेतु उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की योजना

3.2. आर्थिक सेवाएं

एनपीसी का आर्थिक सेवा समूह प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सामाजिक घटकों की पहचान करने और इकाई, क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के निष्पादन का विश्लेषण करने के उद्देश्य से वृहद और उप–वृहद स्तर की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन करने में विशेषज्ञ है।

आर्थिक सेवा समूह ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में बहुत से तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए हैं। इन मूल्यांकनों ने स्कीमों में संशोधन करने तथा इन्हें और अधिक उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मूल्यांकन अध्ययनों के अलावा, आर्थिक सेवा समूह ने उत्पादकता पत्रिकाओं (त्रैमासिक) के चार विशेषांक जारी किए हैं। एनपीसी ने विश्व प्रतिस्पर्द्धा वार्षिकांक 2021 की तैयारी में आईएमडी स्विटजरलैंड को सहभागी संस्थान सेवाएं भी प्रदान की।

आर्थिक सेवा समूह ने एपीओ उत्पादकता डाटा बुक 2021 के आगामी अंक के प्रकाशन के लिए एशियन उत्पादकता संगठन (एपीओ) में राष्ट्रीय विशेषज्ञ सेवाएं भी प्रदान की।

प्रभाग में आर्थिक, सांख्यिकी, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की एक कोर टीम है।

कोर सक्षमताएं:

i. क्षेत्रीय / उद्योग / उत्पाद प्रोफाइल अध्ययन।

ii. बाजार संभावित मूल्यांकन।

iii. सामाजिक–आर्थिक प्रभाव अध्ययन।

iv. नीति फोकस / प्रभाव अध्ययन।

v. उत्पादकता डाटा–बेस विकास।

vi. उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन।

vii. सरकारी योजनाओं की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन।

viii. विपणन और उत्पाद संवर्धन अध्ययन।

3.3. उर्जा प्रबंधन

एनपीसी का ऊर्जा प्रबंधन (ईएम) प्रभाग 1964 से परामर्श / प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। एनपीसी में 30 ऊर्जा प्रबधंन पेशेवरों की कोर संस्था है, जिसमें लगभग 20 बीईई प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक शामिल हैं। इस प्रभाग की विशेषज्ञ सेवाओं के क्षेत्र नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. सभी प्रकार के उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों और स्थापना, विद्युत उत्पादन संयंत्रों, वितरण प्रणाली में ऊर्जा प्रबंधन और लेखा–परीक्षा।

ii. औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ मांग पक्ष प्रबंधन क्षमता।

iii. वरिष्ठ, मध्य और कर्मशाला स्तर के अधिकारियों के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नीतिगत पहलुओं को मजबूत करने और ऊर्जा संरक्षण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।

iv. क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से एसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन और संसाधन संरक्षण।

v. ऊर्जा दक्षता में एपीओ सदस्य देशों को तकनीकी विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान करना।

vi. डॉ. अंबेडकर उत्पादकता संस्थान, चेन्नई में क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र पर ऊर्जा दक्षता और भारत–जापान परियोजना में प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।

3.4. पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन समूह उत्पादकता सुधार के साथ अपशिष्ट कम करने और प्रदूषण रोकथाम पर केंद्रित है। पर्यावरण सेवाओं में मॉनीटरिंग और विश्लेषण, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों और संसाधन संरक्षण की डिजाइन शामिल हैं। 1985 में शुरू किए भारत–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग की सहायता से समूह ने पर्यावरण प्रबंधन में विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित की है।

समूह ने एसएमई और बड़े उद्योगों, केंद्रीय / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय / राज्य स्तर पर पर्यावरण और वन मंत्रालय और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 2500 से अधिक उद्यमों की सहायता की है। समूह एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) और सार्क सदस्य देशों के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवाओं में निम्न शामिल हैं:

i. क्लीनर उत्पादन।

ii. ठोस और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन।

iii. जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

iv. सीआईएस और क्षेत्रीय पर्यावरण योजना।

v. जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण।

vi. हरित उत्पादकता।

vii. पर्यावरण लेखा परीक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली।

3.5. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन समूह संगठनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए मानव संसाधनों की निरंतर वृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान की जाती हैं:

i. जनशक्ति योजना और युक्तीकरण।

ii. संगठन री–डिजाइन अध्ययन।

iii. मानव संसाधन नीति और मैनुअल समीक्षा अध्ययन।

iv. सक्षमता / कौशल मैपिंग / मूल्यांकन।

v. प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन और विश्लेषण ।

vi. पुनः तैनाती के लिए परामर्श और पुनः प्रशिक्षण।

vii. रोजगार / कर्मचारी / ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण।

viii. प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।

ix. निष्पादन प्रबंधन प्रणाली।

x. पूर्ण ऑफलाइन भर्ती समाधान।

xi. रोजगार विवरण / विशिष्ट समीक्षा और डिजाइनिंग।

xii. टीम वर्क और टीम प्रबंधन।

xiii. परिवर्तनकारी नेतृत्व और स्व–प्रेरणा।

xiv. संचार और प्रस्तुति कौशल।

xv. समस्या समाधान और निर्णय करना।

xvi. तनाव और समय प्रबंधन।

xvii. मनोवृत्ति परिवर्तन और कार्य संस्कृति

xviii. ज्ञान प्रबंधन।

xix. प्रभावी कार्यालय प्रबंधन।

xx. आरटीआई अधिनियम कार्यक्रम।

xxi. कार्यालय प्रक्रियाओं पर कार्यक्रम।

3.6. सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी समूह की मुख्य ताकत ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल की मज़बूत प्रणाली (सिस्टम) के साथ मिलकर उत्कृष्ट ज्ञान और कौशल–आधार बनाना है। मुख्य व्यवसाय के क्षेत्र परामर्श और प्रशिक्षण हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आईटी समूह विभिन्न संगठनों के लिए आईटी से संबंधित क्षेत्रों में कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल के साथ–साथ क्षेत्र विशेष के अनुसार ई–गवर्नेंस आईसीटी परियोजनाएं/ज्ञान प्रबंधन और वेब आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए कार्यनीतिक नीति और योजना मामले हेतु परामर्श सेवाओं संबंधी सेवाएं देती रही है।

आईटी समूह द्वारा दी जाने वाली परामर्श सेवाओं में निम्न शामिल हैं:

i. आईसीटी पहलों की व्यवसाय प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग और अनुपालन लेखा–परीक्षा

ii. ई–गवर्नेंस पहल मूल्यांकन और संवर्धन

iii. ज्ञान प्रबंधन कार्यान्वयन और मूल्यांकन

iv. आईसीटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं

v. संगठनात्मक आईसीटी नीति के लिए रणनीतिक योजना

vi. वेब आधारित एप्लीकेशन विकास

vii. आईसीटी में नवप्रवर्तन का संवर्धन और मूल्यांकन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, आईटी समूह प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की एप्लीकेशन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान करती है। नियमित अंतराल पर सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से बनाई गई प्रशिक्षण सेवाएं भी प्रदान करती है। आईटी समूह द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं में निम्न शामिल हैं:

i. ज्ञान और नवप्रवर्तन प्रबंधन

ii. आईसीटी रणनीतिक योजना

iii. सूचना जोखिम प्रबंधन और आईएसएमएस

iv. सरकारी क्षेत्र में कार्यालय प्रबंधन के लिए आईटी एप्लीकेशन

v. अग्रिम आईसीटी उपकरण और तकनीक

vi. आईसीटी के माध्यम से संगठनात्मक निष्पादन को बढ़ाना

3.7. औद्योगिक इंजीनियरिंग

औद्योगिक इंजीनियरिंग समूह उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया सुधार पहल पर ध्यान केंद्रित करता है। परामर्श, कार्यशाला और प्रशिक्षण के माध्यम से यह रचनात्मक रूप से उन घटकों पर अपने कौशल और अनुभव को लागू करता है जो संगठन के निष्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं और विकास और सफलता के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। संगठनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:

i. बेहतर पद्धति बेंचमार्किंग।

ii. प्रक्रिया और उत्पादकता सुधार अध्ययन।

iii. संगठनात्मक पुनर्गठन और जनशक्ति युक्तीकरण।

iv. लीन विनिर्माण।

v. उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ।

vi. सिक्स सिग्मा।

vii. आईएसओ 9001: 2015 और गुणवत्ता प्रबंधन।

viii. ईएफक्यूएम/एमबीएनक्यूए व्यवसाय उत्कृष्टता ढांचे पर आधारित मूल्यांकन।

ix. परियोजना प्रबंधन

x. समय और गति अध्ययन

विशेषज्ञता विकसित करने में, एनपीसी के औद्योगिक इंजीनियरिंग समूह ने प्रमुखता से निम्नलिखित संस्थानों के साथ मिलकर कार्य किया है:

i. जीटीजेड, जर्मनी

ii. फ्राउनहोफर का सूचना केंद्र बेंचमार्किंग, जर्मनी

iii. इन्टरफर्म तुलना केंद्र, यू.के.

iv. पीआईएमएस, यू.के.

v. अमेरिकी उत्पादकता और गुणवत्ता केंद्र, यू.एस.ए.

vi. जेरेट थोर इंटरनेशनल, यूएसए

vii. एशियाई उत्पादकता संगठन, टोक्यो।

viii. आईएलओ।

ix. यूएनडीपी।

x. एनआईटीआईई, मुंबई।

3.8. प्रौद्योगिकी प्रबंधन

प्रौद्योगिकी प्रबंधन सेवाओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वास्तविक परिसम्पत्ति उत्पादकता में सुधार करना है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान परामर्शी परियोजनाओं को निष्पादित करने और प्रदर्शन प्रदान करने के लिए नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

i. 5 एस कार्यान्वयन और प्रमाणन

ii. प्रौद्योगिकी मूल्यांकन अध्ययन

iii. कुल उत्पादक अनुरक्षण

iv. सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन और लेखा परीक्षा

v. रखरखाव प्रणाली

vi. स्थिति मॉनीटरिंग

vii. अनुरक्षण लेखा परीक्षा

viii. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तृतीय पक्षीय पारदर्शी लेखा परीक्षा

3.9 निरीक्षण प्रभाग

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा और कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में निरीक्षण और लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा आईएसओ 17020:2012 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता 14 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 13 अक्टूबर 2023 तक तीन साल की अवधि के लिए वैध है।

एनपीसी क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडी) और पैनल में शामिल खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षकों के साथ निरीक्षण प्रभाग (आईडी) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा) विनियम, 2018 के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (एफबीओ) के स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा करते हैं। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) नियम, 2017 के अनुसार डेयरी क्षेत्र, खाद्य भंडारण / गोदाम / शीत भंडारण और खाद्य परिवहन और गोदामों के निरीक्षण के लिए भारत सरकार (एफएसएसएआई)

निरीक्षण और लेखा परीक्षा गतिविधियों के अलावा, निरीक्षण प्रभाग खाद्य सुरक्षा, खाद्य मानक, खाद्य कानून, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण आयोजित करता है। एनपीसी एफएसएसएआई के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (एफओएसटीएसी) का एक प्रशिक्षण भागीदार भी है।

निरीक्षण प्रभाग द्वारा मार्च 2021 में आयोजित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम "खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) में नेतृत्व की भूमिका" विषय पर था।

इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में खाद्य और डेयरी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सुश्री जया खंडूरी, एफएसएसएआई की एक राष्ट्रीय एफओएसटीएसी ट्रेनर और एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ गुडस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज इंडिया द्वारा किया गया था।

2020–21 के दौरान प्रमुख एनपीसी गतिविधियों पर एक अंतर्दृष्टि

4

4.1 वार्षिक गतिविधियां

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का उत्सव

स्वतंत्रता दिवस 2020 पर शपथ लेते सभी कर्मचारी।

राष्ट्रीय एकता दिवस 2020 पर शपथ लेते सभी कर्मचारी

4.2 प्रदर्शन हाइलाइट्स

परियोजना, कार्यक्रम और प्रतिभागी

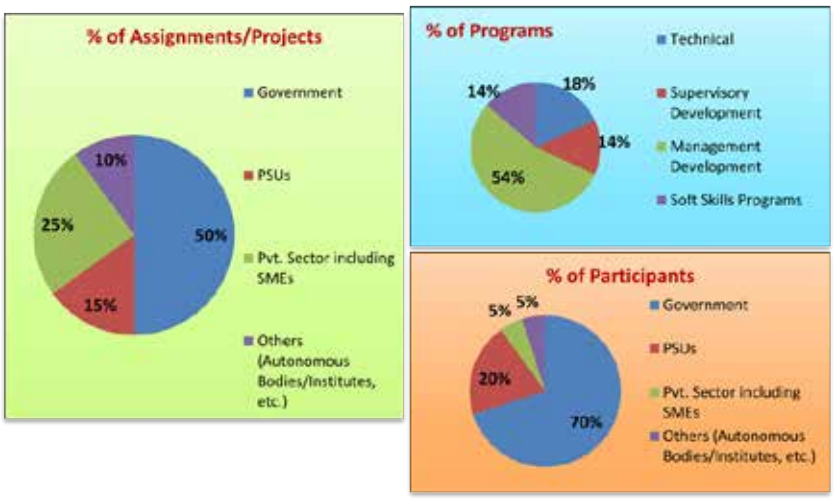

4.3 नई पहलें

I. एनपीसी की डिजिटल समूह सेवाएं

एनपीसी ने 2020–21 के दौरान पहली कोविड–19 महामारी अवधि के दौरान वेबिनार मोड के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई–लर्निंग मॉड्यूल के विकास के माध्यम से प्रशिक्षण सेवाओं को भौतिक मोड से डिजिटल मोड में सफलतापूर्वक बदल दिया है।

एनपीसी के आईटी समूह ने एनपीसी के विभिन्न समूहों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण और संपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों के प्रबंधन के लिए सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल सफलतापूर्वक विकसित किया है।

एनपीसी आईटीसी समूह ने एनपीसी के एनईजीडी एल एमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण के साथ–साथ ई–लर्निंग सामग्री विकास भी शुरू किया।

सफल परिणाम के परिणाम के रूप में, एनपीसी ऑनलाइन राजस्व उत्पन्न करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय और शैक्षणिक संस्थानों के साथ–साथ निजी क्षेत्र के संगठनों के 24000 से अधिक अधिकारियों के कुल ऑनलाइन पंजीकरण के साथ 1200 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई–लर्निंग कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम था। पहली कोविद 19 महामारी अवधि (वित्त वर्ष 2020–21) की डिजिटल सेवा वितरण की स्थापना अवधि के दौरान आनलाइन लगभग 70.25 लाख रुपये की आय हुई ।

i. **ई–लर्निंग**: अप्रैल 2019 से, एनपीसी ने अपना ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करके डिजिटल लर्निंग की दिशा में एक नई पहल की है। ई–लर्निंग पाठ्यक्रमों के अलावा, एनपीसी ने उच्च सामग्री गुणवत्ता वाले ऑनलाइन वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वितरित किए।

"ई–लर्निंग मॉड्यूल की चयनित सूची"

1. बैलेंस स्कोर कार्ड
2. लेखन कौशल को बढ़ाना
3. कार्यालय प्रक्रियाएं, नोटिंग और प्रारूपण की अंतर्दृष्टि
4. भविष्य सूचक विश्लेषण पर ई–लर्निंग कोर्स
5. कचरे से धन उत्पन्न करने पर ई–लर्निंग कोर्स
6. उत्पादकता में सुधार के लिए औद्योगिक इंजीनियरिंग टूल्स पर ई–लर्निंग कोर्स
7. आईएसओ–9001:2015 आईएसओ –14001:2015 और आईएसओ –450001:2018 मानक के अनुसार एकीकृत प्रबंधन

प्रणाली के प्रलेखन, कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए ई–लर्निंग पाठ्यक्रम

8. व्यापार उत्कृष्टता के लिए टीक्यूएम कार्यान्वयन पर ई–लर्निंग पाठ्यक्रम
9. सर्वेक्षकों के क्षमता निर्माण पर ई–लर्निंग मॉड्यूल

ii. वेबिनार / ऑनलाइन कार्यक्रम

एनपीसी ने विभिन्न विषयों पर 9 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और 53 वेबिनार आयोजित किए। मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिखाने के लिए

वेबिनार की चयनित सूची

1. कार्य अध्ययन और एर्गोनॉमिक्स
2. विनिर्माण में डिजिटलीकरण
3. विनिर्माण दक्षता में विश्लेषिकी की भूमिका
4. उच्च प्रदर्शन टीम (एचपीटी) विकसित करने पर वेबिनार
5. हिंदी राजभाषा: मजबूरी या आवश्यकता
6. मानव संसाधन नीति नियमावली पर वेबिनार
7. असफलताओं से निपटना
8. औद्योगिक डिजाइन, नवाचार और उद्यमिता
9. विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में उन्नत विश्लेषिकी अनुप्रयोग
10. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में "जीएफआर–2017 में महत्वपूर्ण संशोधन":
11. बिक्री और विपणन में डिजिटल और विश्लेषिकी हस्तक्षेप
12. मानव संसाधन के सामने आने वाली चुनौतियाँ (कोविड महामारी से पहले/पश्चात और उभरती चुनौतियाँ)
13. क्या आप अपना जीवंत स्टार्टअप या एमएसएमई शुरू करने पर विचार कर रहे हैं?
14. वर्चुअल टाइम्स में दलों का निर्माण
15. मध्यस्थता के जरिये विवाद समाधान
16. कोविड–19 महामारी: आत्म जागरूकता के लिए एक आंख खोलने वाली स्थिति
17. भारत में पीपीपी कार्यान्वयन, मुद्दे/चुनौतियां और अगली पीढ़ी की पीपीपी परियोजनाओं के लिए आगे का रास्ता
18. कार्यस्थल की उत्पादकता बढ़ाना: मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

II. जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा

जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के अनुसार, अधिसूचना एस.ओ. 3289(ई) दिनांक 24 सितंबर, 2020 के अनुसार, यह कहा गया है कि "धारा 4.1 (iii) 100 एम 3/डी से अधिक भूजल निकालने वाले सभी उद्योगों को वार्षिक जल लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता होगी। एनपीसी जल लेखा परीक्षा करने के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा अनिवार्य संगठन है। जल लेखा परीक्षक की सिफारिशों के कार्यान्वयन के आधार पर, ऐसे सभी उद्योगों को उचित साधनों के माध्यम से अगले तीन वर्षों में अपने भूजल उपयोग को कम से कम 20% तक कम करने की आवश्यकता है। एनपीसी जल लेखा परीक्षा अध्ययन में विशिष्ट जल उपयोग और संरक्षण, सुविधा का पूर्ण जल संतुलन, जल बचत के अवसर, सिफारिशों को लागू करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण, प्रक्रिया विवरण और आंकड़े, और आवश्यक निवेश शामिल हैं।

एनपीसी ऊर्जा ऑडिट अध्ययन भी करता है और इसमें 30 ऊर्जा प्रबंधन पेशेवरों की मुख्य ताकत है जिसमें लगभग 20 बीईई प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक शामिल हैं। एनपीसी सभी प्रकार के उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों और स्थापना, बिजली उत्पादन संयंत्रों और वितरण प्रणाली में ऊर्जा प्रबंधन और लेखा परीक्षा लेता है। एनपीसी ने 100 से अधिक जल लेखा परीक्षा अध्ययन और लगभग 20 ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययन किए।

"उद्योगों की सूची जहां जल लेखा परीक्षा की गई थी"

1. एपीएम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड भिवाड़ी, राजस्थान
2. आईटीसी राजपुताना, जयपुर, राजस्थान
3. मेट्सो इंडिया प्रा। लिमिटेड, अलवर,

राजस्थान

4. डायनेमिक फाइन पेपर मिल प्रा. लिमिटेड, कोटा, राजस्थान
5. स्पेशियलिटी सिलिका प्रा. लिमिटेड, अलवर, राजस्थान
6. इंडिया सीमेंट, बांसवाड़ा, राजस्थान
7. अल्ट्राटेक सीमेंट, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
8. अल्ट्राटेक सीमेंट, पिंडवाड़ा, राजस्थान
9. महेश एडिबल ऑयल, कोटा, राजस्थान

10. बांसवाड़ा सिंटेक्स, बांसवाड़ा

III. एनएबीसीबी द्वारा एनपीसी को निरीक्षण निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा और कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में निरीक्षण और लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा आईएसओ 17020:20 12 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता 14 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 13 अक्टूबर 2023 तक तीन साल की अवधि के लिए वैध है।

IV. कंपनी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कंपनी में ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गयाः वर्ष के दौरान कुल 18 कंपनी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, कुल 375 कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकार के संगठन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।

1. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए निवारक सतर्कता पर (7 नग) 2 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
2. सिडबी के लिए सचिवीय प्रभावशीलता बढ़ाने पर 6 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
3. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए सचिवीय प्रभावशीलता बढ़ाने पर 3 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए. सूचना का अधिकार अधिनियम पर 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम
5. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट (2 नग) के लिए वी.ओ. के लिए सेवा में स्थापना नियम, नोटिंग और प्रारूपण, आरक्षण नियम पर 6 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
6. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए निविदा प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधन पर. 2 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
7. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूआईईटी, हरियाणा के लिए गैर–शिक्षण कर्मचारियों की प्रबंधकीय क्षमता विकसित करने पर 3 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
8. गेल, जयपुर के लिए विद्युत सुरक्षा पहलुओं और आईई नियमों पर 2 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
9. आईएफसीआई, नई दिल्ली के लिए सार्वजनिक खरीद पर 2 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
10. यूपीसीएल, देहरादून के लिए निवारक सतर्कता और आरटीआई पर 2 दिन क्षमता निर्माण कार्यक्रम

V. एमपीसी में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन

एनपीसी ने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से एमएसएमई परियोजना में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन को बढ़ावा देने के तहत मेडक फार्मा क्लस्टर में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन शुरू किया है। पांच फार्मा इकाइयों का दौरा किया गया, अर्थात् पेलेट्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, वेगा लाइफ साइंसेज, श्री चौतन्य क्लोराइड्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रोमो लेबोरेटरीज और जेनसिंथ लेबोरेटरीज।

एनपीसी ने मेडक फार्मा क्लस्टर में चार ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की पहचान की है:

1. कंडेनसर ट्यूबों की ऑनलाइन ट्यूब सफाई, 2. मिस्ट कूलिंग सिस्टम, 3. कूलिंग टावर्स के लिए साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम और 4. इलेक्ट्रिक ड्राई स्क्रू वैक्यूम के साथ स्टीम वैक्यूम पंपों का प्रतिस्थापन पंप्स।

एनपीसी क्षेत्रीय निदेशालय, हैदराबाद ने एमएसएमई फार्मा उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों में ज्ञान का प्रसार करने के लिए बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बीडीएमए), हैदराबाद के सहयोग से 5 अक्टूबर 2021 को "मेडक फार्मा क्लस्टर में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन" पर एक आधे दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। विभिन्न फार्मा उद्योगों और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने आधे दिन की कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान विभिन्न एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए ईईएसएल और विरुपाक्ष ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर)

VI. ई–कनेक्ट

एनपीसी अपना इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र (मासिक) ईकनेक्ट नाम से प्रकाशित कर रहा है। एनपीसी अपने हितधारकों, ग्राहकों, अन्य सरकारी संस्थानों, अपने वेबिनार के प्रतिभागियों के साथ ई–कनेक्ट साझा करता है ताकि उन्हें एनपीसी गतिविधियों के बारे में अद्यतन रखा जा सके और उनके साथ निरंतर संबंध विकसित किया जा सके। ई–कनेक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशिष्ट और वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यकारियों को उत्पादकता मुद्दों और चुनौतियों के संबंध में ई–कनेक्ट के पहले पृष्ठ पर अपने मूल्यवान विचार/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना है। सभी इच्छुक पाठक https://www.npcindia.gov.in/NPC/User/econnect - पर ई–कनेक्ट का उपयोग कर सकते हैं

VII. भारत 4.0–डिजिटल तैयारी आकलन उपकरण

भारत 4.0–डिजिटल रेडीनेस टूल के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें उद्योग 4.0 के क्षेत्र में उद्योग (एस) / एसएमई (एस) की तैयारी का आकलन किया जाएगा। संगठन की प्रक्रियाओं की यथास्थिति का आकलन करने के लिए विनिर्माण इकाइयों में परिपक्वता मूल्यांकन के लिए भारत 4.0 मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यान्वयन परियोजनाओं को शुरू करने के संबंध में विस्तृत हस्तक्षेप का आधार बनेगा।

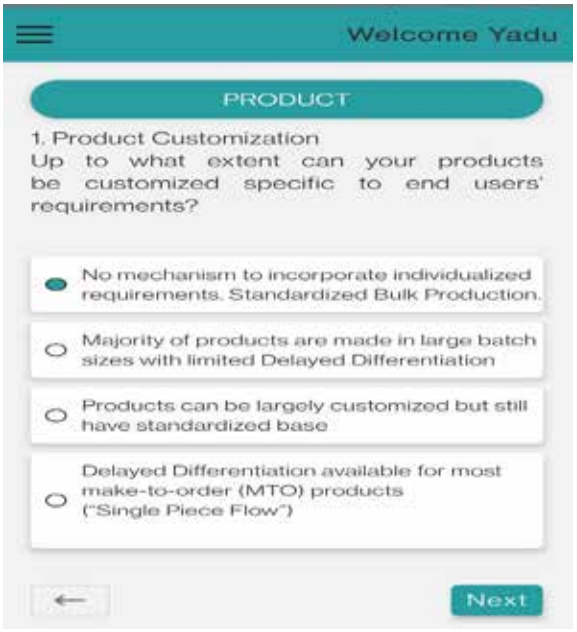

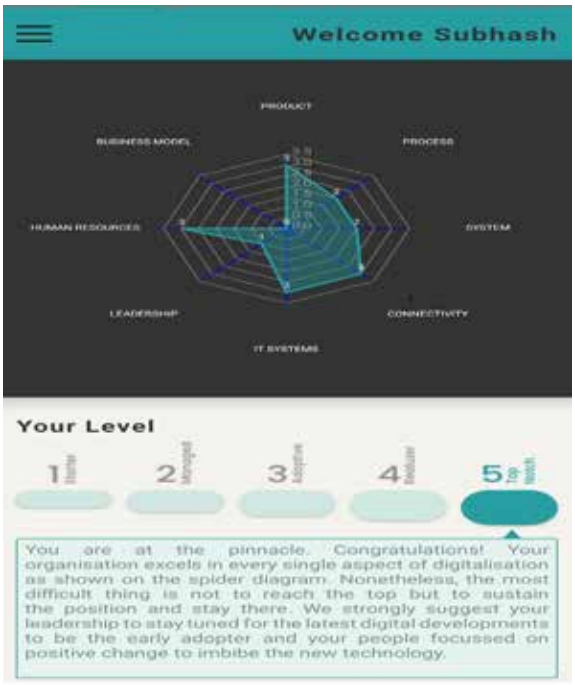

उपकरण का उपयोग उद्योग/एसएमई (एस) द्वारा स्मार्ट (स्टार्टर, प्रबंधित, अनुकूली, रियलाइज़र, टॉप–नोच) के संदर्भ में व्यक्त पांच परिपक्वता स्तरों के संदर्भ में संगठन की डिजिटल तैयारी के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।)

VIII. उद्योग पर अनुभव क्षेत्र 4.0

- एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी ने स्टूडियो के रूप में नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में उद्योग 4.0 पर अत्याधुनिक अनुभव क्षेत्र की स्थापना की है, जिसमें स्टोरीबोर्ड के डिजिटल डिस्प्ले, उपयोग के मामले आदि दीवारों पर हैं।
- अनुभव क्षेत्र में आईओटी/एआई/एआर–वीआर/सिमुलेशन के परिचालन प्रोटोटाइप भी स्थापित किए गए हैं। इनमें रोबोटिक आर्म, ग्राउंड क्लीयरेंस रोबोट, सर्विलांस रोबोट, 3डी प्रिंटर, एआर आधारित वेयरहाउस डिस्प्ले यूनिट, आईओटी के साथ इंडस्ट्री स्मार्ट एनर्जी मॉनिटर, एआई आधारित रोबोट, आईओटी के साथ ईसीजी/पल्स मॉनिटर सिस्टम, आईओटी, एआई आधारित वाहन डिटेक्शन, इमेज टू टेक्स्ट आदि शामिल हैं।
- अनुभव क्षेत्र का उद्देश्य एक स्पर्श और अनुभव का वातावरण प्रदान करना और उद्योग / अकादमिक/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों आदि के आगंतुकों के लिए उद्योग 4.0 और संबंधित प्रौद्योगिकी डोमेन की प्रमुख अवधारणाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना और तकनीकी जानकारी/जागरूकता और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

IX. भारत 4.0–डिजिटल तैयारी आकलन उपकरण (कॉफी टेबल संस्करण)

भारत 4.0–डिजिटल रेडीनेस असेसमेंट टूल (कॉफी टेबल वर्जन) की अवधारणा और विकास एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी द्वारा किया गया है। उपकरण का उपयोग उद्योग (ओं)/एसएमई (एस) द्वारा स्मार्ट (स्टार्टर, प्रबंधित, अनुकूली, रियलाइज़र, टॉप–नोच) के संदर्भ में व्यक्त पांच परिपक्वता स्तरों के संदर्भ में संगठन की डिजिटल तैयारी के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। यह अगले स्तर पर बदलने के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यकताओं/रणनीतियों को इंगित करते हुए एक समग्र मूल्यांकन भी प्रदान करता है। यह टूल उद्योग, आकार, प्रोफ़ाइल और परिपक्वता की परवाह किए बिना सभी कंपनियों पर लागू होता है। यह टूल एक डिजिटल प्रश्नावली फॉर्म का उपयोग करता है जिसे इच्छुक उपयोगकर्ता द्वारा भरा जाएगा। फॉर्म जमा करने के बाद उपयोगकर्ता को उसकी बी4.0–मूल्यांकन रिपोर्ट तुरंत उसके ईमेल पर प्राप्त होगी।

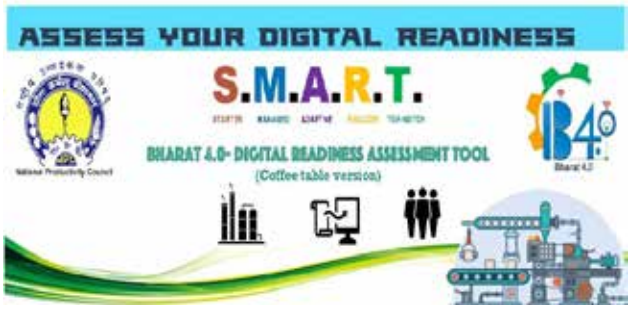

X. सक्षम 4.0–उद्योग 4.0 पर वर्चुअल इंटर्नशिप कार्यक्रम

एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी ने एनपीसी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 2500 से अधिक इंटर्न को प्रशिक्षित किया है। एलएमएस प्लेटफॉर्म निम्नलिखित डोमेन को कवर करते हुए प्रमुख तकनीकी विषयों पर वीडियो सीखने की पेशकश करता है:

1. उन्नत विनिर्माण प्रणाली और उसका अनुप्रयोग
2. विनिर्माण उत्कृष्टता प्राप्त करना अर्थात। लीन/एमएफसीए आदि।
3. उद्यमिता और नवाचार
4. औद्योगिक प्रक्रियाएं और उद्योग 4.0
5. कोविड 19 के बाद की दुनिया में नए बिजनेस मॉडल को अपनाना

4.4 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन

अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादकता की संस्कृति को फैलाने के लिए, एनपीसी ने अन्य संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग किया। एनपीसी ने परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहुंच में सुधार हेतु विभिन्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

1. तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, यूपी (19.06.2020) –

एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी ने भारत में विनिर्माण उद्योगों के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए सहयोगी कार्यक्रम करने के लिए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र उत्पादकता सुधार के लिए सरकार–अकादमिया–उद्योग लिंकेज बनाना भी है

भारत में विनिर्माण उद्योगों के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन पैदा करने के लिए उद्योग 4.0 के लिए आईटी पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओईः आईटी फॉर आई4.0) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोगी कार्यक्रम आयोजित करना। जागरूकता कार्यक्रम के अलावा दोनों संगठन अकादमी–उद्योग लिंकेज की दिशा में काम करेंगे।

इसका उद्देश्य नियमित आधार पर पूरे भारत में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/परामर्श कार्यों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता प्राप्त करना है।

2. **शारदा विश्वविद्यालय (24.06.2020)** –

एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी ने भारत में विनिर्माण उद्योगों के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए सहयोगी कार्यक्रम करने के लिए शारदा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र उत्पादकता सुधार के लिए सरकार–अकादमिया–उद्योग लिंकेज बनाना भी है।

भारत में विनिर्माण उद्योगों के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन पैदा करने के लिए उद्योग 4.0 के लिए आईटी पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओईः आईटी फॉर आई4.0) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साझा कार्यक्रम करना। जागरूकता कार्यक्रम के अलावा दोनों संगठन अकादमी–उद्योग लिंकेज की दिशा में काम करेंगे।

इसका उद्देश्य पूरे भारत में नियमित आधार पर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/परामर्श कार्यों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता करना है।

3. **भारत एसएमई फोरम (आईएसएफ) (7/1/2020)** –

एमएसएमई, स्टार्टअप और इच्छुक उद्यमियों के बीच उद्यमिता विकास और उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्रों में सहयोग और समझौता करना।

4. **ग्राफिक एरा मानित विश्वविद्यालय (9/23/2020)** –

उत्पादकता और स्वयं और मजदूरी – रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से कौशल और शिक्षा दोनों की ताकत को एकत्र करने के लिए पारस्परिक सहयोग के अवसरों की पहचान करना।

5. **भारतीय रबर विनिर्माता अनुसंधान एसोसिएशन (9/29/2020)** –

संगठनात्मक कामकाज के पुनर्गठन और प्रक्रिया में सुधार की दिशा में बातचीत के माध्यम से संगठनों के पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे का सहयोग करना।

6. **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद समुद्र विज्ञान (जनवरी 2020)** –

प्रस्तुत समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यावरण प्रबंधन, तटीय क्षेत्रों और समुदायों में जलवायु लचीलापन, समुद्र विज्ञान

डेटा विश्लेषण, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन और मॉडलिंग के क्षेत्र में दीर्घकालिक संयुक्त कार्य साझेदारी विकसित करना है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान के लिए उपचारात्मक और शमन उपायों की पहचान की जा सके और नीति अनुसंधान में योगदान दिया जा सके।

7. **ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड आटोमेशन (एआईसीआरए) (03.11.2020)** –

भारत में विनिर्माण उद्योग के बीच उद्योग 4.0 में बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यान्वयन हेतु आई.टी. उद्योग 4.0 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता (सीओई:आईटी फॉर आई 4.0) के केन्द्र के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक कार्य का निष्पादन करना है। जागरूकता कार्यक्रम के अलावा दोनों संगठन अकादमी–उद्योग लिंकेज की दिशा में काम करेंगे।

इसका उद्देश्य नियमित आधार पर पूरे भारत में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/परामर्श कार्यों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता करना है।

8. **असम स्टार्टअप– द नेस्ट (09.11.2020)** –

छात्रों/काम करने वाले पेशेवर/उद्यमियों/एसएमई की गुणवत्ता उन्नयन/क्षमताओं में वृद्धि के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम करना।

9. **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) (14.12.2020)** –

प्रस्तुत समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मुख्य रूप से एनर्जी थीम के तहत इंटरेटेड एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी से संबंधित सीएसआईआर के विकास और अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में एक सहयोगी तरीके से मिलकर काम करने के लिए सहमत होना है। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सीएसआईआर की क्षमता निर्माण में सहायता करना और आंतरिक रूप से सीएसआईआर की अन्य गतिविधियों के लिए विभिन्न ऊर्जा दक्षता से संबंधित परियोजनाओं का संयुक्त विकास और निष्पादकन करना है।

10. **भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान (16.12.2020)** –

कृषि व्यवसाय और बागान क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र के ग्राहकों (जैसे, छात्रों, पेशेवरों, व्यापार मालिकों, वस्तु बोर्ड और सरकार) को मूल्य वर्धित प्रबंधन इनपुट प्रदान करना।

11. **सीमेंट और निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद (एनसीसीबीएम) (15.01.2021)** –

दोनों संस्थान अर्थात एनसीसीबीएम और एनपीसी पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी अवसंरचना/प्रयोगशाला सुविधाओं, पुस्तकालय, और संस्थानों के स्वामित्व सॉफ्टवेयर और अन्य घरेलू विकास घटकों सहित सामग्री को एक दूसरे के साथ साझा करने की सुविधा प्रदान करेंगे। उपरोक्त साझाकरण तृतीय पक्ष अनुबंध की शर्तों, यदि कोई हो के अधीन होगा, तो वह केवल अनुसंधान के उद्देश्य के लिए लिए होगा।

12. **हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (20.01.2021)** –

उद्देश्य यह है कि भारत में विनिर्माण उद्योग के बीच उद्योग 4.0 में बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यान्वयन हेतु आई.टी. उद्योग 4.0 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता (सीओईरू आईटी फॉर आई 4.0) के केन्द्र के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक कार्य का निष्पादन करना है। जागरूकता कार्यक्रम के अलावा दोनों संगठन अकादमी–उद्योग लिंकेज की दिशा में काम करेंगे।

इसका उद्देश्य नियमित आधार पर पूरे भारत में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/परामर्श कार्यों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता करना है।

13. मंगलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (20.01.2021) –

उद्देश्य यह है कि भारत में विनिर्माण उद्योगके बीच उद्योग 4.0 में बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यान्वयन हेतु आई.टी. उद्योग 4.0 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता (सीओईः आईटी फॉर आई 4.0) के केन्द्र के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक कार्य का निष्पादन करना है । जागरूकता कार्यक्रम के अलावा दोनों संगठन अकादमी–उद्योग लिंकेज की दिशा में काम करेंगे।

इसका उद्देश्य नियमित आधार पर पूरे भारत में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/परामर्श कार्यों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता करना है।

14. मार्केट एक्ससेल डेटा मैट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड (05.02.2021) –

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मुख्य रूप से 36 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की सेवा में "मार्केट एक्ससेल डेटा मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड" परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) को शामिल करना है। पीएमसी,एनपीसी के साथ मिलकर गहनता से कार्य करेगा ताकि डब्यूजेपी नियम कानून इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार किया जा सके।

15. पीटीसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (15.03.2021) –

एनपीसी/पीटीसी संयुक्त रूप से समग्र परियोजना प्रबंधन और समन्वय, संसाधन प्रबंधन, वितरण योग्य और उद्योगों, यूटिलिटीज और अन्य सभी संबंधित हित धारकों के लिए जिम्मेदार होगा, हालांकि एनपीसी/पीटीसी द्वारा शुरू की जा रही प्रत्येक परियोजना या गतिविधि हेतु, परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय कार्यान्वयन और अन्य नियम और शर्तों सहित कार्य संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा।

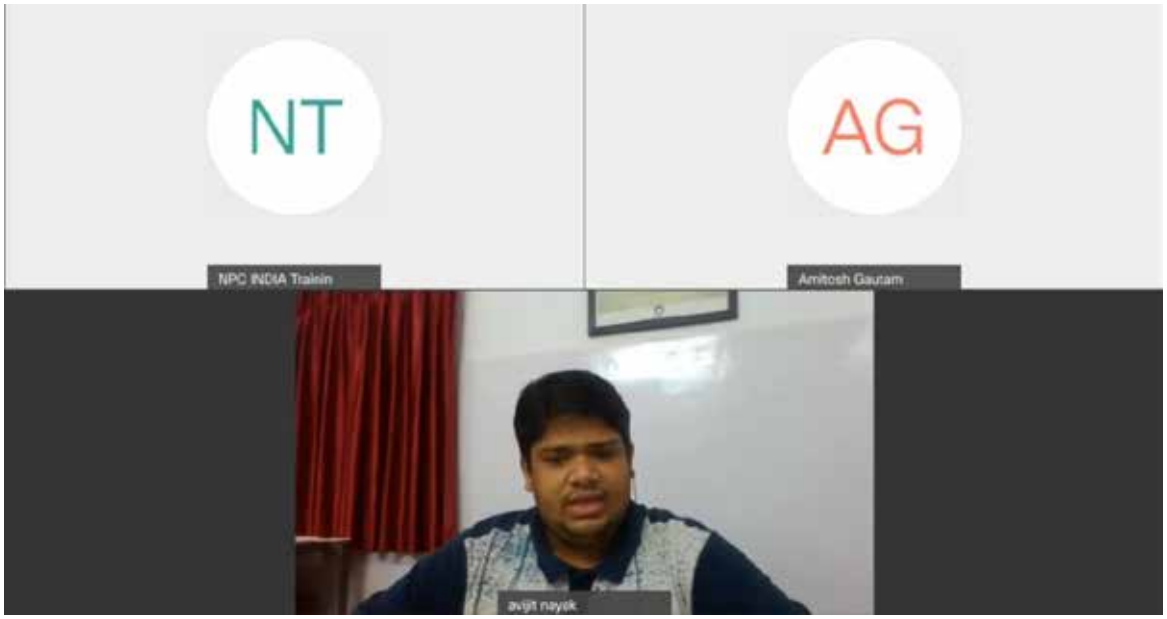

(एनटीपीसी, खारगोन में बाहय सुरक्षा लेखा परीक्षा)

(नाल्को क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में ऊर्जा लेखा परीक्षा और प्रबंधन पर एक दिवसीय सत्र)

16. **एनपीसी, आइकॉन ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के पर्यटन और खेल मंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए**

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और अवसर नेटवर्क (IKON) समूह के बीच उत्पादकता के क्षेत्रों में परियोजनाओं और प्रशिक्षण को एक साथ चलाने के लिए नोवोटेल, विशाखापत्तनम में एक मेगा कार्यक्रम में गांधी जयंती और गांधी स्मारक पुरस्कार के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और श्री एम श्रीनिवास राव, आंध्र प्रदेश के माननीय पर्यटन और खेल मंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया।

17. **श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

एचआरएम एंड सीओई ग्रुप, एनपीसी ने ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में विनिर्माण उद्योगों के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

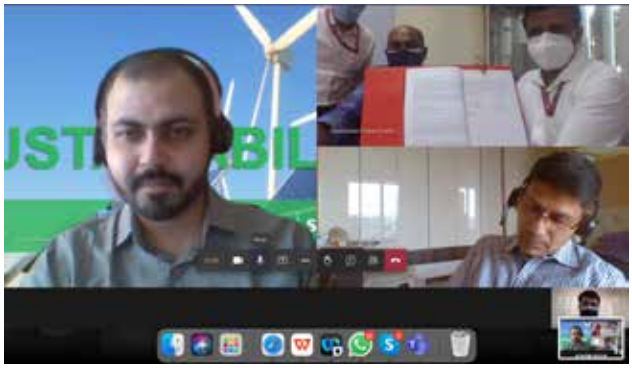

4.5 एनपीसी द्वारा किए जा रहे कुछ बड़े कार्यों का सारांश इस प्रकार है:

1. **डब्ल्यूबीपीसीबी के लिए भर्ती:**

एचआरएम ग्रुप ने 55,597 उम्मीदवारों के लिए पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए

पश्चिम बंगाल में बारह स्थानों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किया। सभी परीक्षा केंद्र नवीनतम कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि से लैस थे। परीक्षण सभी स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। असाइनमेंट का मूल्य 3.44 करोड़ रुपये प्लस जीएसटी था।

2. घरेलू और विदेशी पर्यटकों के दौरों/आगंतुकों के आंकड़ों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में नियुक्त किया है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभागों की क्षमता के निर्माण के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों और उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दौरे का अनुमान लगाया जा सके। अनुमान के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुरूप एक मानक पद्धति विकसित की जा रही है।

डेटा विभिन्न पर्यटक आकर्षणों, निवास की स्थिति/देशवार आगंतुकों की प्रोफाइल, उनकी आयु, लिंग, किए गए व्यय, पसंदीदा आवास आदि पर घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।

मंत्रालय द्वारा डेटा का उपयोग पर्यटन आकर्षणों पर विभिन्न नीतियों और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की योजना बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय पर्यटन की क्षमता को प्रदर्शित करने और पर्यटन मंत्रालय के विदेशी विपणन अभियानों की योजना बनाने में किया जा सकता है। यह डेटा उद्योग इकाइयों के लिए बाजार की अंतर्दृष्टि निकालने और नवीन उत्पादों और पैकेजों के साथ आने के लिए भी उपयोगी होगा।

डेटा प्राप्त करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा कैप्चर किया जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग स्वचालित होगी और एकीकृत डैशबोर्ड पर आउटपुट टेबल/पैरामीटर प्लॉट किए जाएंगे।

यह डैशबोर्ड विभिन्न पर्यटन विकास संकेतकों जैसे जिलेवार पर्यटक यात्राओं, कमरे में रहने, रोजगार, विदेशी मुद्रा आय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन, भारतीय राष्ट्रीय प्रस्थान पर डेटा के प्रसार में मदद करेगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के अनुरूप है। डैशबोर्ड राज्य के पर्यटन विभागों को उनके राज्यों के पर्यटन संकेतकों की निगरानी करने और उनकी नीतियों और पहलों को सही दिशा में योजना बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा।

3. टीएएनजीईडीसीओ के लिए जनशक्ति अनुकूलन अध्ययन

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने एआईपी चेन्नई को 287.60 लाख रुपये के मैनपावर ऑप्टिमाइजेशन स्टडी का काम सौंपा है। अध्ययन चेन्नई में एनपीसी के औद्योगिक इंजीनियरिंग सलाहकार द्वारा किया जा रहा है।

4. डीजीक्यूए के लिए संगठन अध्ययन और संवर्ग समीक्षा

एनपीसी ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए), रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के लिए लगभग 2 करोड़ मूल्य का 'संगठन अध्ययन और संवर्ग समीक्षा' आयोजित की है।

अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) नीतियां, प्रक्रिया और प्रथाएं वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप हैं और क्या डीजीक्यूए अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए उपयुक्त रूप से तैनात, संगठित, सुसज्जित और कर्मचारी हैं।

5. केंद्रीय भंडारण निगम के लिए अध्ययनः

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने दो प्रतिष्ठित असाइनमेंट नामतः "सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का संगठनात्मक अध्ययन" और "समूह सी और डी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) की समीक्षा और पुनः डिजाइनिंग" क्रमशः 89.68 लाख रुपये और 33.28 लाख रुपये मूल्य के असाइनमेंट के लिए सौंपा है।

संगठन अध्ययन असाइनमेंट में व्यापक संगठनात्मक विश्लेषण करने के लिए अध्ययन का कवरेज शामिल है जिसमें जनशक्ति, संगठनात्मक संरचना, संवर्ग समीक्षा और सिफारिशें, कार्मिक नीतियों की समीक्षा, योग्यता मानचित्रण और केंद्रीय भंडारण निगम के सीखने और विकास शामिल हैं और रिपोर्ट वर्तमान में सीडब्ल्यूसी प्रबंध द्वारा समीक्षा के अधीन है।

कुछ साइट विज़िट तस्वीरें निम्नानुसार रखी गई हैं:

कुछ साइट विज़िट तस्वीरें निम्नानुसार रखी गई हैं:

पीएलआईएस अध्ययन में खाद्यान्नों के गोदामों, एक्जिम और बंधुआ गोदामों आदि के लिए नमूना स्थल का दौरा शामिल किया गया था और सीडब्ल्यूसी के प्रबंधन द्वारा कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट की काफी सराहना की गई थी।

6. पर्यावरण मंजूरी के बाद निगरानी और अनुपालन ढांचे को मजबूत करना।

ईआईए अधिसूचना 1994 के बाद से पर्यावरण मंजूरी वाली सभी परियोजनाओं को छह–मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। ईआईए अधिसूचना 2006 में उद्योगों/परियोजनाओं की 39 श्रेणियां शामिल हैं जिन्हें पर्यावरण मंजूरी के बाद निगरानी की आवश्यकता होती है। 8,500 से अधिक श्रेणी ए परियोजना प्रस्तावक (पीपी) और 28,000 से अधिक श्रेणी बी पीपी हैं जिन्होंने ईसी प्राप्त किया है जिसके लिए पोस्ट ईसी निगरानी की आवश्यकता है।

निगरानी और अनुपालन को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में पीपी और एनजीटी के आदेशों को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण प्रबंधन और प्रदर्शन में सुधार के लिए पीपी की सहायता करने के लिए, एमओईएफ एंड सीसी ने एनपीसी को परियोजनाओं की ईसी के बाद की निगरानी के लिए एक व्यापक 3 स्तरीय ढांचा विकसित करने के लिए नियुक्त किया है जिसमें एक प्रमाणित पर्यावरण लेखा परीक्षकों (सीईए) और प्रमाणित पर्यावरण प्रबंधकों (सीईएम) के मंत्रालय की तकनीकी रूप से कुशल विस्तारित शाखा के रूप में सेवा करने के लिए और पीपी और अन्य सभी उद्योगों को उनकी पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा, प्रबंधन और सुधार करने में सहायता करने के लिए योजना शामिल है। एनपीसी ने जीआईजेड, एन ई ई आर आई, क्यूसी आई, अन्य हितधारकों और विषय विशेषज्ञों के साथ भागीदारी की है। ये प्रमाणित पेशेवर उद्योगों/पीपी को मामला दर मामला आधार पर पर्यावरणीय समस्याओं का ज्ञान और तकनीकी समाधान भी प्रदान करेंगे।

अत्यधिक कुशल तकनीकी रूप से मजबूत मेहनती लेखा परीक्षकों के इस समूह को उपयुक्त तंत्र के माध्यम से पहचाना, चयनित, उन्मुख/प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा।

7. उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समर्थित योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता मंचों को मजबूत करने, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन, कॉन्फोनेट, उपभोक्ता जागरूकता, राष्ट्रीय परीक्षण गृहों (एनटीएच), ब्यूरो को मजबूत करने सहित कई योजनाओं को लागू किया है। भारतीय मानक (बीआईएस) योजनाएं जैसे मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण और गोल्ड हॉलमार्किंग और परख केंद्रों की स्थापना, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के कानूनी माप विज्ञान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) और भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), रांची का सुदृढ़ीकरण , समय प्रसार योजना और मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी)।

उपरोक्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली को एक अध्ययन सौंपा है जिसमें प्रमुख संदर्भ जैसे प्राप्त धन का उचित उपयोग, भौतिक उपलब्धि– वित्तीय उपलब्धि, समय–सीमा का पालन और मानदंडों की पर्याप्तता।

अध्ययन के तहत, 12 राज्य आयोग, 36 जिला उपभोक्ता फोरम, 48 कॉन्फोनेट, 12 राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन, 44 गोल्ड हॉलमार्किंग और परख केंद्र, 12 माध्यमिक मानक प्रयोगशालाएं, 24 कार्य मानक प्रयोगशालाएं, 5 आरआरएसएल, आईआईएलएम रांची, 5 समय प्रसार केंद्र, 6 अध्ययन के तहत एनटीएच और 22 पीएमसी को शामिल किया गया। रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की गई थी और सिफारिशों के साथ इसे स्वीकार कर लिया गया है।

जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तरी सिक्किम

देहरादून में हॉलमार्किंग सेंटर नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद

नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन, कोलकाता

8. परियोजना के लिए आधारभूत अध्ययन "विदर्भ क्षेत्र के आदिवासी लोगों के किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए चावल परती में दलहन प्रौद्योगिकी का परिचय"

बेहतर आजीविका के लिए दालों और बिना कांटे का कैक्टस की क्षमता का दोहन करने के लिए "विदर्भ क्षेत्र के आदिवासी लोगों के किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए चावल परती में दलहन प्रौद्योगिकी का परिचय" पर महाराष्ट्र सरकार और आईसीएआरडीए द्वारा आदिवासी आबादी वाले नागपुर और अमरावती जिलों के किसानों की पोषण सुरक्षा के लिए एक सहयोगी पायलट परियोजना लागू की जा रही है।

एनपीसी ने परियोजना गतिविधियों के पूरा होने के बाद परियोजना के कार्यान्वयन के कारण प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक सूचना आधार प्रदान करने के उद्देश्य से आधारभूत अध्ययन किया था।

एनपीसी विदर्भ क्षेत्र के दो जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण करता है—नागपुर और अमरावती। नागपुर जिले में, रामटेक, कटोल, उमरेड, सावनेर, नरखेड़ और पशिवानी के 6 ब्लॉक और अमरावती में 5 ब्लॉक अर्थात धरनी, चिकलदरा, वरुद, अचलपुर और मुर्सी को बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए शामिल किया गया है। दोनों जिलों में कुल 617 किसान शामिल हैं।

अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट अनुमोदन के लिए पीएफसी को प्रस्तुत की गई है।

9. व्यापक जिला कृषि योजना तैयार करना

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को कृषि के 40 जिलों के लिए व्यापक जिला कृषि योजना (सीडीएपी) तैयार करने का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य जिले के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकताओं को आगे बढ़ाना है।

ये योजनाएँ जिले के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। सीडीएपी आरकेवीवाई – रफ्तार के तहत विभिन्न उप योजनाओं/परियोजनाओं को विकसित करने के लिए है।

सी–डीएपी के लिए परियोजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे फसल विकास, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विपणन और कटाई के बाद प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, विस्तार आदि आरकेवीवाई से वित्त पोषित किया जा सकता है और मौजूदा योजनाओं का सामान्य एकत्रीकरण नहीं होगा।

चित्रकूट में डीएपीयू बैठक की झलक

जौनपुर में डीएपीयू बैठक की झलक

मानिकपुर प्रखंड में बीएपीयू की बैठक

मानिकपुर प्रखंड में वीएपीयू की बैठक

बदलापुर प्रखंड में बीएपीयू की बैठक

आरा गांव में वीएपीयू की बैठक

10. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन।

यह मूल्यांकन अध्ययन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) की 7 विभिन्न योजनाओं को किस हद तक लागू किया गया है और योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं की पहचान के साथ–साथ क्षेत्र स्तर पर अपनाया गया है, इसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इन योजनाओं को निदान, उपचार विधियों और रोकथाम के लिए टीकों से संबंधित अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से लोगों तक आधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया थाय उत्पादों और प्रक्रियाओं में उनका अनुवाद करना और, संबंधित संगठनों के साथ तालमेल में, इन नवाचारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पेश करना।

योजनाओं की सभी किस्मों के प्रतिनिधि कवरेज और इसके वितरण के साथ विभिन्न मापदंडों के आधार पर योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया था । देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित विभिन्न नमूना संस्थानों से क्षेत्र स्तर के डेटा और सूचना संग्रह का अध्ययन।

अध्ययन ने ज्ञात होता है की तीन योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के समय की आवश्यकता को पूरा कर रही हैं। योजनाओं के उत्पादन और परिणाम को प्राप्त करने के लिए, अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में अधिक जोर देने, स्थापना कार्य की वास्तविक समय निगरानी प्रणाली के विकास के साथ–साथ प्रयोगशालाओं की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों और क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया था।

11. हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन

आईई समूह ने कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के कपड़ा आयुक्त द्वारा कार्यान्वित पावरलूम क्षेत्र की योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारत की। अध्ययन में 13 योजनाओं का यानी, सादे पावरलूम का इन–सीटू अपग्रेडेशन, ग्रुप वर्क शेड स्कीम (जीडब्ल्यूएस), कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी का मूल्यांकन शामिल है।), पावरलूम सर्विस सेंटर का ग्रांट–इन–एड / आधुनिकीकरण (जीआईए से पीएससी) और भी बहुत कुछ। एनपीसी ने 16 राज्यों में 6000 से अधिक पावरलूम लाभार्थियों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की है और उन योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव के बारे में जानकारी, प्रतिक्रिया, सुझाव एकत्र

किए हैं। विश्लेषण सिफारिश के साथ किया जाता है, सेवा वितरण में सुधार, योजनाओं की प्रभावशीलता के लिए सुझाव प्रदान किए जाते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों ने नीति निर्माताओं को योजना के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करने, सुझावों को लागू करने के लिए जानकारी प्रदान की।

12. मौजूदा सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन

औद्योगिक इंजीनियरिंग (आईई) समूह ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं में से एक, "मौजूदा सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन" का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अध्ययन के उद्देश्य में योजना का प्रदर्शन विश्लेषणय योजना की प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभावशीलता, इक्विटी और स्थिरता शामिल है। उल्लिखित उद्देश्यों का पता लगाने के लिए, विभिन्न हितधारकों/लाभार्थियों के साथ बातचीत की गई और प्रशिक्षुओं (197 संख्या), प्रशिक्षकों (87 संख्या), कार्यान्वयन संस्थानों यानी मॉडल आईटीआई (11 संख्या),

राज्य सरकारों से नोडल मंत्रालय और उद्योग भागीदार यानी आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) डेटा/सूचना मांगी गई। प्राथमिक/द्वितीयक डेटा और हितधारकों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के आधार परय योजना के वितरण में प्रभावशीलता में सुधार के लिए सिफारिशें और सुझाव दिए गए थे।

13. सिंगरौली मानव संसाधन सम्मेलन– श्रम 2021

सिंगरौली मानव संसाधन सम्मेलन, श्रम–2021, 17–18 नवंबर, 2021 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारत की ऊर्जा राजधानी में अपनी तरह का पहला सम्मेलन था। हिंडाल्को, रिलायंस पावर, एस्सार, एनटीपीसी, गेल, एसईसीएल आदि संगठनों के एचआर प्रमुखों ने 650 प्रतिभागियों के साथ इस मेगा इवेंट में भाग लिया। सम्मेलन का विषय औद्योगिक क्रांति 4.0रू पीपल मैट्रिक्स के माध्यम से प्रतिस्पर्धा था। प्रसिद्ध वक्ता श्री शिव खेड़ा, प्रोफेसर, लेखक, अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) टीवी राव, प्रोफेसर, लेखक, अध्यक्ष प्रबंधन सलाहकार, डॉ. संतोष भावे, निदेशक (पी एंड आईआर), भारत फोर्ज लिमिटेड, डॉ. प्रमोद सदरजोशी, प्रबंध पार्टनर, कॉर्नरस्टोन इंटरनेशनल ग्रुप, श्री संजीव लाहिरी, सीएचआरओ, जीआरपी लिमिटेड, डॉ दीपक देशपांडे उपाध्यक्ष और प्रमुख एचआर, टाटा बिजनेस एक्सीलेंस ग्रुप, श्री नीलाद्री भट्टाचार्जी पार्टनर, केपीएमजी और डॉ बी हेमंत कुमार राव, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद थे।

14. "जनशक्ति को भविष्य के लिए नियुक्त करना" विषय पर कार्यशाला

डॉ. बी. हेमंत कुमार राव, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने श्रोताओं को उप–विषय श्भविष्य के लिए कार्यबल को शामिल करना – एक कोचिंग संस्कृति को विकसित करना विषय पर ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित किया कि एक प्रशिक्षक एक सूत्रधार होता है, लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाने चाहिए और एक प्रशिक्षक की भूमिका क्या होती है। उन्होंने इस बिंदु पर भी विस्तार से बताया कि कोचिंग संस्कृति के साथ दृष्टि और मिशन का संरेखण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कोचिंग प्रक्रिया को

डिजाइन करने के लिए ग्रो मॉडल का सुझाव दिया जो लक्ष्य, वास्तविकता, विकल्प/बाधाओं और रैप अप/इच्छा को दर्शाता है।

15. कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के "संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं पर अध्ययन का संचालन"

कोच्चि में स्थित कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के 'संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं पर अध्ययन का संचालन' शीर्षक से एक असाइनमेंट शुरू किया, जिसका मूल्य 44 लाख रुपये + जीएसटी है। 2020–21 के अंत तक आरडी बैंगलोर ने इस असाइनमेंट के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट जमा कर दी थी।

(कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं पर अध्ययन आयोजित करना –डक्ट का फील्ड अध्ययन निरीक्षण)

4.6 माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एनपीसी की 49वीं जीसी बैठक

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में एनपीसी की 49वीं शासी परिषद की बैठक 27 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इसमें सरकार के सचिवों और संयुक्त सचिवों, उद्योग संघों के प्रमुखों, ट्रेड यूनियनों, भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुखों, यूनिलीवर, बीसीजी, फिक्की, सीआईआई, नैसकॉम, एफआईएसएम्ई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, केपीएमजी, एचएमएस, सीआईटीयू, बीएमएस, आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी और एलपीसी आदि सहित 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.7 2020–21 के दौरान शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान और परामर्श परियोजनाओं की चयनित सूची

एनपीसी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मूल्य वर्धित परामर्श प्रदान करता रहा है। संगठन इस तरह के अध्ययनों के साथ अपनी उत्पादकता में काफी हद तक वृद्धि करने में सक्षम रहा है।

1.	सभी जिलों के लिए तमिलनाडु में ई–अपशिष्ट वस्तु सूची पर राज्य स्तरीय परियोजना
2.	21वीं एनसीई – बीईई
3.	टीएएनजीईडीसीओ के लिए जनशक्ति अनुकूलन अध्ययन
4.	आईटीईसी के लिए अक्षय ऊर्जा में हस्तांतरण के लिए तकनीकी नीति
5.	कोच्चि में स्थित कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं पर अध्ययन
6.	कर्नाटक आवासीय शिक्षण संस्थान सोसाइटी (केआरईआईएस) के तहत आवासीय विद्यालयों में आरईसी–सीएसआर प्रायोजित परियोजनाओं का प्रभाव विश्लेषण अध्ययन
7.	कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (केएससीएसटी) के लिए श्कर्नाटक के 10 तालुकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आभासी कक्षा की स्थापनाश–परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन –
8.	इंटीग्रेटेड फूड पार्क लिमिटेड, तुमकुर जिला में विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा
9.	जेमिनी ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बीदर में जल लेखा अध्यन
10.	उड़ीसा खनन निगम, भुवनेश्वर के लौह अयस्क, क्रोमाइट अयस्क और बॉक्साइट अयस्क खानों की विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा
11.	एनटीपीसी– स्टील ऑथेरिटी आफ इंडिया लि. भिलाई, छत्तीसगढ़ के लिए जल संतुलन अध्ययन
12.	उड़ीसा खनन निगम, भुवनेश्वर में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन
13.	उड़ीसा खनन निगम, भुवनेश्वर में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के निर्वाह के लिए सहायता सेवाएं
14.	उड़ीस खनन निगम, भुवनेश्वर में एसए 8000 प्रणाली का कार्यान्वयन
15.	ओडिशा खनन निगम, भुवनेश्वर में एसए 8000 प्रणाली के निर्वाह के लिए सहायता सेवाएं
16.	श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ की एल.ई.एस.एस. योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन
17.	वर्ष 2020–21 में प्रोत्साहन योजना की समीक्षा व डिजाइन के लिए डीएमडब्ल्यू, पटियाला की 8 दुकानों में लगभग 1000 क्रियाकलापों के लिए समय अध्ययन पूरा
18.	पानीपत सीमेंट वर्क्स का जल लेखा परीक्षा
19.	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की श्सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माणश स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन।
20.	बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सों) अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटान लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) पर स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

21.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सरकार द्वारा मौजूदा सरकारी आईटीआई के मॉडल आईटीआई में उन्नयन का मूल्यांकन अध्ययन।
22.	"राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडी), भारत सरकार का मूल्यांकन अध्ययन।
23.	हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के कामकाज" पर मूल्यांकन अध्ययन
24.	एलिम्को (ए.एल.आई.एम.सी.ओ.) द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता और उपकरणों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
25.	तीन सुरक्षा मुद्रणालयों सोनीपत में दो व जालंधर में एक का निरीक्षण
26.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के लिए बैगिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में उत्पादकता सुधार अध्ययन।
27.	भरूच इको एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अंकलेश्वर और देश भर में फैली इसकी सहायक इकाइयों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन
28.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के लिए जनशक्ति अनुकूलन और संगठन पुनर्गठन का अध्ययन।
29.	एपीओ परियोजनाः क्षेत्रीय निदेशालय गांधीनगर ने एपीओ के 5 दिनों के प्रमाणित उत्पादकता पेशेवरों के पाठ्यक्रम का संचालन किया जिसमें 16 एपीओ सदस्य देशों के 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
30.	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) – यह परियोजना विद्युत वित्त निगम, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य वितरण कंपनियों के तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करना है।
31.	गुजरात में भेषज क्षेत्र में ऊर्जा और संसाधन प्रतिचित्रण अध्ययन
32.	मुंबई और सूरत में मेगा सीएफ़सी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
33.	अग्रणी टायर विनिर्माण कंपनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का निष्पादन मूल्यांकन
34.	एक प्रमुख तांबा विनिर्माण कंपनी के सुरक्षित भरावक्षेत्र के निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण
35.	सीजीडब्ल्यूए मानदंडों के अनुसार जल लेखा परीक्षा
	क. कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड, होजई, असम में जल लेखा परीक्षा
	ख. ट्रिनिटी फ्रक्टा प्राइवेट लिमिटेड, मंगलदाई में जललेखा परीक्षा
	ग. आईटीसी लिमिटेड, गुवाहाटी में जल लेखा परीक्षा
	घ. एचयूएल, तिनसुकिया में जल लेखा परीक्षा
	ङ. नीपको लिमिटेड में जल लेखा परीक्षा

	च. इको टेक पेपर्स, गुवाहाटी में जल लेखा परीक्षा
36.	एएमडीसी – कोयला निष्कर्षण परियोजनाओं की लागत का आकलन – असम सरकार
37.	उद्योग भवन, असम में आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन
38.	एनएसकेएफडीसी योजना का प्रभाव आकलन
39.	एलिम्को योजना का प्रभाव मूल्यांकन
40.	मौजूदा आईटीआई के आधुनिकीकरण के उन्नयन का प्रभाव मूल्यांकन
41.	एनएपीएस योजना का प्रभाव मूल्यांकन
42.	एमआईआईयूएस योजना निगरानी
43.	फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का प्रभाव– यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो)
44.	महान एल्युमिनियम, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मध्य प्रदेश की अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा
45.	आदित्य एल्युमिनियम, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संबलपुर उड़ीसा की अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा
46.	हिम्मतसिंगका लिनेन लिमिटेड, हासन, कर्नाटक का ऊर्जा लेखा परीक्षा।
47.	मार्की मंगली–I कोयला खान, टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र का जल लेखा परीक्षा।
48.	दक्षिण मध्य रेलवे, कैरिज वर्कशॉप, लल्लागुडा का ऊजा परीक्षा
49.	मेडक फार्मास्युटिकल क्लस्टर, तेलंगाना में पीएमसी कार्य निष्पादित।
50.	फार्मा क्षेत्र के लिए भारत में एमएसएमई समूहों की ऊर्जा और संसाधन प्रतिचित्रण
51.	असाइनमेंट के बारे में प्रस्तावनारू एनआईआईएमएस में ऊर्जा लेखा परीक्षा और संरक्षण अध्ययन।
52.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, अंता, राजस्थान के लिए जल मूल्यांकन अध्ययन।
53.	एनटीपीसी टांडा में जल संतुलन लेखा परीक्षा
54.	जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर देहात, उ.प्र. में मौजूदा गैर–परिचालन सीईटीपी और इसकी वाहन प्रणाली के उन्नयन के लिए तकनीकी आदानों पर अध्ययन,
55.	कोल इंडिया लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों के लिए तीन एसओआर अध्ययन किए गए।
	• महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
	• सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
	• नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
56.	जल लेखा परीक्षा अध्ययन
	1. विष्णु शुगर मिल, गोपालगंज
	2. भारत चीनी मिल, सिधवालिया

	3. एचआईएल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, जसीडीह, देवघर
	4. नई स्वदेशी चीनी मिल नरकटियागंज
	5. नई स्वदेशी चीनी मिल नरकटियागंज (डिस्टिलरी)
	6. हसनपुर चीनी मिल, हसनपुर रोड, समस्तीपुर
	7. मैश एग्रो फूड लिमिटेड किसानगंज
	8. हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (इथेनॉल इकाई)
	9. हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड (इथेनॉल यूनिट)
	10. अल–समीर एक्सपोर्ट्स प्रा0 लिमिटेड फोर्ब्सगंज, बिहार
	11. आईटीसी लिमिटेड डेयरी प्लांट, मुंगेर
	12. स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड, हॉट रोलिंग मिल, झारखंड
	13. भारतीय रिजर्व बैंक पटना
57.	उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समर्थित योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन
58.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के लिए जनशक्ति मूल्यांकन, जनशक्ति योजना और संगठन संरचना का विश्लेषण
59.	सूखे क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लिए षविदर्भ क्षेत्र के आदिवासी लोगों के किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए परती चावल में दाल प्रौद्योगिकी का परिचय परियोजना के लिए अध्ययन"
60.	कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए व्यापक जिला कृषि योजना की तैयारी।
61.	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के लिए प्याज और टमाटर के थोक और खुदरा बाजार के मूल्य के बीच अंतर पर अध्ययन
62.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए बेहतर खेती और उन्नम रेटिंग अभ्यास (आईसीएआरई) पर पायलट परियोजना का मूल्यांकन
63.	उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (यूसीडीएफ लिमिटेड) के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का प्रभाव मूल्यांकन
64.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन।
65.	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी पर्यटकों के दौरों/आगंतुकों के आंकड़ों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण
66.	पावरलूम क्षेत्र की योजनाओं के निष्पादन का आंकलन
67.	मौजूदा सरकारी आईटीआई का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन
68.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर में कलपुर्जो का अध्ययन
69.	आईओसीएल लखनऊ के लिए 5एस लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन

4.8 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चयनित सूची

एनपीसी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न ऑनलाइनध्ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम
1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए अक्षय ऊर्जा में स्थानांतरण के लिए तकनीकी, नीतिगत उपकरण और रूपरेखा" जो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ई–आईटीईसी) द्वारा प्रायोजित थी।
2.	पर्यावरण निगरानी – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रयोगशाला में प्रदूषण, एएक्यूएम, ढेर और विभिन्न पर्यावरणीय मानकों जैसे वायु, पानी और शोर के परीक्षण का नमूना संग्रह
3.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दक्षिणी क्षेत्र पाइपलाइनस (एसआरपीएल) के लिए 22–23 फरवरी, 2021 के दौरान एआईपी में उत्पादकता के लिए सात क्यूसी टूल्स आयोजित किए गए थे।
4.	सार्वजनिक उद्यम विभाग, कर्नाटक सरकार के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम,
	• उत्पादकता में सुधार के लिए लीन विनिर्माण जागरूकता
	• विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा लेखा परीक्षा और संरक्षण
	• एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001–14001–45001) जागरूकता और कार्यान्वयन
	• निष्पादन प्रबंधन
5.	आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001 और आईएसओ 50001 पर आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
6.	आईसीएफ, चेन्नई के लिए विफलता प्रणाली प्रभाव विश्लेषण (फेमा) पर ऑनलाइन इन–हाउस प्रशिक्षण
7.	ईपीएफओ, कोलकाता के लिए पीएध्पीएस की प्रभावशीलता में सुधार पर ऑनलाइन इन–हाउस प्रशिक्षण
8.	एनपीसीआईएल, मुंबई के लिए सेवानिवृत्ति योजना पर तीन ऑनलाइन इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम
9.	ईआईसी और एसडीए, भुवनेश्वर द्वारा प्रायोजित राज्य के ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों पर तीन ऑनलाइन इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम
10.	ईआईसी–ई–सह–पीसीईआई और एसडीए (ओ), भुवनेश्वर के लिए उड़ीसा और ईसी दिवस 2020 के ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा पेशेवरों के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी
11.	पीजीसीआईएल, भुवनेश्वर में परिवर्तन के लिए प्रभावी ढंग से अनुकूलन और प्रतिक्रिया पर ऑनलाइन इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम
12.	ईआईसी–ई–सह–पीसीईआई और एसडीए (ओ), बीबीएसआर और एनटीपीसी, कनिहा, अंगुल के लिए 5 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
13.	एनटीपीसी, सीपत, छत्तीसगढ़ के लिए 5 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम
14.	संघर्ष समाधान और वित्तीय प्रबंधन
15.	मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, प्रबंधन विकास संस्थान, बिलासपुर के लिए "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें" कार्यशाला
16.	डिब्रूगढ़, असम में मुख्य बॉयलर निरीक्षक, के सहयोग से राज्य स्तरीय बॉयलर कार्यशाला
17.	नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) के तहत हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएस एंड एसबी) के कर्मचारियों के लिए ऊर्जा दक्षता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
18.	संभावित ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों– बीईई का एन.सी.ई. के लिए ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला –
19.	टी.एस.आर.ई.डी.सी.ओ. प्रायोजित ऊर्जा संरक्षण सप्ताह समारोह – 2020
20.	"पेशेवरों के लिए औद्योगिक जल उपचार" पर ई–प्रमाणन पाठ्यक्रम
21.	औद्योगिक सुरक्षा पर एक महीने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम
22.	जी.आई.जेड. एम.एस.एम.ई ईनों प्रोजेक्ट के तहत मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला
23.	ई–सेल, टी.आई.एस.एस. मुंबई के लिए उन्नत एक्सेल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण
24.	आईओसीएल के विभिन्न स्थानों पर 5एस प्रशिक्षण

हरित सरिस एंड संस
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवामें

सदस्यगण,
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद,
5-6 संस्थागत क्षेत्र,
लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003

अभिमत

हमने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश सहित 31 मार्च, 2021 तक के तुलन-पत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता शामिल है।

इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र तथा आय और व्यय खाते परिषद द्वारा रखी गई खाता बही से सहमत हैं।

हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते अनुबंध 1 मे दी गई टिप्पणियों तथा आय और व्यय परिसंपत्तियों और देयताओं तथा लेखा नीतियों और टिप्पणियों के साथ पठित उनके परिणामी प्रभाव के अधीन एक सही और निष्पक्ष विचार देते हैं.

i. 31 मार्च 2021 को परिषद के कार्यों के विवरण के मामले में तथा
ii. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए परिषद की आय से अधिक व्यय के आधिक्य आय और व्यय खाते के मामले में ।

अभिमत के लिए आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार आयोजित की थी। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षण की जिम्मेदारियों में मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार इकाई से स्वतंत्र हैं जो हमारे वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के आधार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन से आरोपितों की ज़िम्मेदारियां

प्रबंधन भारत के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है और ऐसा आंतरिक नियंत्रण जैसा प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है जो गलत सामग्री, चाहे कपट पूर्ण या त्रुटिपूर्ण हो, से मुक्त है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक लाभकारी प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की परिषद की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, लाभकारी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के चल रहे लाभकारी प्रतिष्ठान का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो समाज को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

जिन लोगों पर शासन का आरोप लगाया गया है, वे परिषद की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से वस्तुगत गलत, चाहे कपट पूर्ण या त्रुटि पूर्ण हो, से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि लेखाकरण संबंधी मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा वस्तुगत गलत होने का पता लगा लेगी, यदि यह मौजूद है। गलतियां, कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि वस्तुगत गलती, यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक तौर पर होती है, तो वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है।

कृते **हरित सरिस एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 014584N

सनदी लेखाकार हरित कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता संख्या: 094269

दिनांक: 30/11/2021
स्थानः दिल्ली
यूडीआईएनः

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के खातों पर हमारी रिपोर्ट के लिए उल्लिखित अनुबंध 1

1. स्थायी परिसम्पत्ति: -

i) मुख्यालय में स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर दो भागों अर्थात दिनांक 17-10-2005 से पूर्व एक तथा संशोधित जीआर फार्मेट में 17-10-2005 से पश्चात दूसरा उपलब्ध हैं। कुछेक स्थायी परिसम्पत्तियों का पूर्ववर्ती वर्षों में निपटान कर दिया गया लेकिन बिक्री आगम को बेची गई परिसम्पत्ति की लागत में उसे जोड़ने के बजाय आय एवं व्यय लेखा में प्राप्तियां मानी गई और तथापि उन परिसम्पत्तियों के अंकित शेष को बट्टेखाते में डालने से सकल और निवल ब्लॉकों में थोड़ा अंतर हो सकता है जिसे उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। वर्ष के दौरान इस संबंध में परिषद द्वारा कोई समायोजन नहीं किया गया।

ii) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक और बही रिकॉर्ड के बीच, मुख्यालय और किसी भी आरडी की स्थायी पारिसम्पत्ति का कोई मिलान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्ति की कमी / त्याग / गैर-कार्यकरण के कारण यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो, तो वह पता लगाने योग्य नहीं है, जिसका दिनांक 31.03.2021 को परिषद के लाभ और कार्य विवरण पर प्रभाव हो सकता है।

2. विविध देनदार: -

i) प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देनदार के शेष की प्राप्ति की पुष्टि नहीं की है।

ii) विविध देनदारों को 31-3-2021 के अनुसार 624.50 लाख रु. (पीवाई- 383.94 लाख रु.) बकाया है, जिसमें 3 वर्ष से अधिक का 173.11 लाख रु. (पीवाई- 138.94 लाख रु.) बही डेविट बकाया शामिल है, जिसके लिए परिषद ने 31.03.2021 को 173.11 लाख रु. के संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया है।

iii) लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31-3-2021 के अनुसार 73,31,326 / - रुपये की गैर मान्य प्राप्तियां विभिन्न पार्टियों से परिषद के बचत बैंक खाते में असमायोजित है । उपरोक्त राशि में से रु. 22,03,897/- वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित है। पहचान के अभाव में, उपरोक्त राशि को जीएसटी रिटर्न में देनदारों से प्राप्त अग्रिम रूप में दिखाया गया है और पार्टियों की पहचान / समाधान के बिना अपनी स्वयं की निधि से जीएसटी का 18% की दर से भुगतान किया। हमारी राय में, उपरोक्त

राशि विभिन्न अप्रदत्त देनदारों से प्राप्त हो सकती है। पहचान के अभाव में, 31.03.2021 को बकाया देनदार उस सीमा तक बढ़चढ़कर हो सकते हैं।

3. परियोजनाएं: -

i) परियोजना धनराशि की प्राप्ति पर, परिषद उस पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करती है और परियोजना के लिए खर्च के रूप में रिकॉर्ड करती है।

ii) परिषद परियोजनाओं के प्रायोजकों से धन की मांग करने के लिए 'प्रायोजित परियोजनाओं के लिए बिल' जारी करती है । इन बिलों पर 18% की दर से जीएसटी बुक और भुगतान किया जाता है, हालांकि ये केवल मांग पत्र हैं। जीएसटी की यह राशि परियोजना / प्रस्तावित परियोजना के लिए व्यय के रूप में मानी जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अनुरोध पर धनराशि बिल्कुल प्राप्त नहीं की गयी है। इससे जीएसटी का अनावश्यक भुगतान होता है और परियोजना से संबंधित व्यय में वृद्धि होती है। इसके अलावा, इन प्राप्तियों को संबंधित परामर्श आय की अनिश्चितता के कारण जीएसटी रिटर्न में बी 2 सी बिक्री के रूप में दिखाया जाता है।

iii) लेखा परीक्षा के दौरान हमने देखा कि परिषद द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र परियोजना से संबंधित व्यय के सकल आंकड़े दर्शाता है। प्राप्त परियोजना धनराशि से बचत खाते में अर्जित ब्याज आय का खुलासा परिषद द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है।

iv) परिषद परियोजना के लिए किए व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रही है। परियोजना पर हुए व्यय को आईटीसी की सीमा में कम करने की आवश्यकता है। इसके चलते जीएसटी का अधिक भुगतान और परियोजनाओं से संबंधित व्यय की अधिक बुकिंग हुई। इसके फलस्वरूप परियोजनाओं के प्रायोजकों को हानि होती है।

v) वर्ष 2020-21 के दौरान 31-03-2021 को विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजना खातों में वसूली के लिए लंबित डेबिट शेष का कुल योग 14.35 लाख रु. (पीवाई- 12.09 लाख रु.) और 31-03-2021 को विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजना खातों में क्रेडिट शेष कुल मिलाकर 628.03 लाख रु. (पीवाई- 465.07 लाख रु.) है। वसूली / रिफंड की संभावना के आधार पर इनकी समीक्षा और उनका प्रावधान / समायोजित करने की आवश्यकता है।

4. ऋण और अग्रिम

i) परिषद के पास कर्मचारियों के खर्च के लिए दी गई अग्रिम राशि 10,22,359/ - रुपये का शेष बकाया है, जो 31.03.2021 के अनुसार असमायोजित बनी हुई है। परिषद की आय कर्मचारियों के अनपेक्षित खर्चों की सीमा से अधिक बताई है। हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि कर्मचारियों द्वारा इच्छित उद्देश्यों के लिए किस सीमा तक इन अग्रिमों का उपयोग किया गया है।

ii) परिषद के पास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं को भुगतान की गई सुरक्षा / जमा बयाना राशि के लिए 43,88,483 / - रुपये का शेष बकाया है। कई उदाहरणों में परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन जमा अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। परिषद को इसे प्रदत्त सुरक्षा धनराशि का उचित रूप से समाधान करने और रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

5. नकद और बैंक शेष

यह देखा गया है कि परिषद द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक में बनाए रखे गए प्रतिधारण बैंक खाता संख्या 091601000037555 का समाधान नहीं किया गया है। बैंक प्रमाणपत्र के अनुसार खाता शेष राशि 99,313 / - रुपये है, हालांकि बही शेष 6,97,744 / - रुपये है। इस प्रकार, 5,98,431 / - रुपये का अंतर है। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के साथ-साथ देनदारियों का अधिमूल्यन होता है।

6. आयकर वापसी (रिफंड): -

यह देखा गया है कि आयकर विभाग से 4 वर्ष से अधिक के लिए प्राप्त किए गए लंबित आयकर रिफंड वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2014-15 तक 84.35 लाख रु. हैं।

7. टीडीएस का गैर-समाधान

9,61,628 / - रु. का टीडीएस क्रेडिट का वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म 26 एएस की तुलना में लेखा बही में अधिक बुक हुआ है। इसके अलावा 9,14,020 / - रु. की टीडीएस राशि है जिसको पहचान न होने के चलते खाता बहियों में दर्ज नहीं किया है।

8. वस्तु और सेवा कर

i) खाता बही आधिक्य और जीएसटीआर-1 के अनुसार आउटपुट का समाधान अंतर दर्शाता है। (अनुसूची 'क' के रूप में संलग्न) परिषद को ब्याज / दंड से बचने के लिए इसके उचित समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

ii) खाता बही और जीएसटीआर 3बी के अनुसार आउटपुट का समाधान अंतर अन्तर दर्शाता है। (अनुसूची 'ख' के रूप में संलग्न) परिषद को ब्याज / दंड से बचने के लिए इसके उचित समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

iii) जीएसटीआर 3बी के अनुसार प्राप्त और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का समाधान और जीएसटीआर-2ए में परिलक्षित अन्तर (अनुसूची 'ग' के रूप में संलग्न) दर्शाता है। परिषद को ब्याज / दंड से बचने के लिए इसके उचित समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

iv) यह पाया गया है कि जीएसटीआर-2ए में कुछ प्रविष्टियां हैं, लेकिन उन खाता बहियों में नहीं हैं, जिनके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि होगी और ब्याज और दंड की ओर आकर्षित हो सकते हैं। परिषद की खाता बहियों के अनुसार और पोर्टल पर दर्शाए गए फॉर्म जीएसटीआर-2ए के अनुसार इनपुट समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

v) जीएसटी टीडीएस को उचित रूप से नहीं काटा गया है और परिषद द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया है। उसको प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है और उसी के लिए देनदारियों को बुक किया गया है। इन देनदारियों के लिए जीएसटीआर-7 को परिषद द्वारा फाइल किए जाने की आवश्यकता है।

vi) निम्नलिखित टीडीएस पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसके लिए देनदारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है:

शाखा	देनदार	सी जी एस टी (टीडीएस)	एस जी एस टी (टीडीएस)	आई जी एस टी (टीडीएस)
चेन्नई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-	-	21060
कानपुर	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	6000

मुख्यालय	खादी और ग्रामोद्योग आयोग-आईटी			16320
मुख्यालय	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	7200	7200	-
मुख्यालय	खान मंत्रालय	500	500	

इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में पोर्टल पर दर्शाए गए जीएसटी टीडीएस को चालू वित्तीय वर्ष में कम दर्ज किया गया है/ दर्ज नहीं किया गया है।

शाखा	देनदार	सी जी एस टी (टीडीएस)	एस जी एस टी (टीडीएस)	आई जी एस टी (टीडीएस)
चेन्नई	तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	9975	9975	-
कानपुर	कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी	2975	2975	-
जयपुर	डब्ल्यूडीआरए	-	-	6355.92
मुख्यालय	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	2070	2070	-
मुख्यालय	जीवन विज्ञान संस्थान			7078
मुख्यालय	आयकर निदेशालय एचआरडी	225	225	-

vii) ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दाखिल GSTR-9 और 9C, बहीखाते और रिटर्न (अनुसूची 'डी' के रूप में संलग्न) के अनुसार टर्नओवर और टैक्स में अंतर दिखाता है। परिषद को किसी भी बंधन से बचने के लिए इसे ठीक से समेटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

viii) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि परिषद ने सुरक्षा सेवाएं प्राप्त की हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हैं और बिल पर जीएसटी सहित सेवा प्रदाता को भुगतान किया है और इसके लिए आईटीसी का लाभ उठाया है। इसके अलावा परिषद ने ऐसी सुरक्षा सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान किया है और आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर के लिए इनपुट का लाभ उठाया है। इससे जीएसटी का अनावश्यक भुगतान होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है।

9. टीडीएस विवरणों में चूक

i) ऑनलाइन वेबसाइट के अनुसार, 2007-08 से 2020-21 तक के वित्त वर्षों के लिए 10,94,420 / - रुपये की टीडीएस चूक है। परिषद द्वारा उक्त चूक को दंड और ब्याज से बचने के लिए सुधारा जाना चाहिए। इन चूकों के आरडी वार अंतःशेष निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	विगत तीन वर्ष	पूर्व वर्षों
1.	मुख्यालय	20,060	5,76,080
2.	चेन्नई	3,450	65,230
3.	मुम्बई	25,930	25,020
4.	कोलकाता	2,54,740	37,520
5.	गांधीनगर	8,360	660
6.	जयपुर	2,010	5,550
7.	बैंगलोर	-	16,570
8.	कानपुर	3,430	2,510
9.	गुवाहाटी	200	-
10.	भुवनेश्वर	4,370	33,510
11.	चंडीगढ़	30	4,620
12.	हैदराबाद	4,570	-
	कुल	**3,27,150**	**7,67,270**

ii) लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि प्रपत्र 16 में दर्शाए गए वेतन और विभिन्न शाखाओं में पुस्तकों के अनुसार वेतन में अंतर है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, परिषद के विभिन्न वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को 2,30,47,408/- रुपये की एकमुश्त वेतन वृद्धि के बकाया का भुगतान किया गया है। इस राशि पर कर का भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 की आय मानकर किया जाता है। हालांकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के तहत राहत के लिए गणना प्रदान नहीं की गई है और इसके लिए कर्मचारियों को फॉर्म 16 में लाभ नहीं दिया गया है।

10. ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण:

i) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सृजित अवकाश नकदीकरण के आस्थगित राजस्व व्यय की शेष राशि 6,45,46,582/-, जिसे अगले 4 वर्षों में समान रूप से बट्टे खाते में डालना था, को चालू वर्ष में पूर्णतः बट्टे खाते में डाल दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए 2,74,62,054 रुपये का और प्रावधान किया गया है।

ii) वर्तमान देनदारियों में दिनांक 11.08.2020 के अनुसार डा. पी.वी. सभरवाल के एक्यूरियल सर्टिफिकेट के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को 1270.99 लाख रु. (पीवाई- 1,460.18 लाख रु.) की ग्रेच्युटी देनदारियों के लिए प्रावधान शामिल हैं। परिषद ने न तो ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कोई बीमा पॉलिसी ली है और न ही कोई अनुमोदित ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाया है, लेकिन ग्रेच्युटी देनदारियों के लिए आईओबी में पड़े 621.16 लाख रु. (पीवाई- 575.99 लाख रु.) के लिए एफडीआर उद्दिष्ट किया गया हैं। हमारी राय में, ग्रेच्युटी देयता के खाते में देयता के लिए समान राशि उद्दिष्ट की जानी चाहिए और निवेश के लिए रखी जानी चाहिए।

11. ग्राहकों / पार्टियों से अग्रिम:

विभिन्न देनदारों से अग्रिम रूप में प्राप्त की जा रही 1,15,63,774/- / - रु. की राशि शेष है। हम देनदार से किसी भी पुष्टि के अभाव में इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, चाहे इन राशियों को विभिन्न देनदारों के बकाया शेष के लिए समायोजित किया जा सकता है।

12. अन्य वर्तमान देनदारियाँ:

परिषद विभिन्न पार्टियों से सुरक्षा जमा प्राप्त करती है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेष निम्नलिखित है। परिषद ने न तो किसी रजिस्टर का रखरखाव किया है और न ही सुरक्षा राशि के लिए कोई समाधान किया है।

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	मुख्यालय	56,10,941
2	चेन्नई	8,04,443
	कुल	64,15,384

13. आंतरिक लेखापरीक्षा

लेखा परीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान यह देखा गया कि परिषद के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं हैं। हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, जो आंतरिक नियंत्रण का एक अभिन्न अंग है, को मजबूत करने और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

14. पुष्टि

31.03.2021 को विविध देनदार, विविध लेनदार, अग्रिम वसूली, अग्रिम देय, सुरक्षा जमा / के साथ देय / विभिन्न एजेंसियों / पार्टियों आदि के शेष की पुष्टि और समाधान के अधीन हैं जो 31.03.2021 को परिषद की लाभप्रदता और कार्य की स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं।

कृते **हरित सरिस एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 014584N

सनदी लेखाकार हरित कुमार गर्ग
साझेदार
सदस्यता संख्या: 094269

दिनांक: 30.11.2021
स्थानः दिल्ली
यूडीआईएनः

अनुसूची 'क'

जीएसटीआर 1 और बहियों के अनुसार आउटपुट कर का मिलान

मुख्यालय (07AAATN0402F1Z8)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	16,53,58,043.31	83,04,816.67	1,03,08,579.75	1,03,08,579.75	2,89,21,976.17
कम: वित वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	6,54,095.00	1,17,737.10			1,17,737.10
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	16,47,03,948.31	81,87,079.57	1,03,08,579.75	1,03,08,579.75	2,88,04,239.07
बहियों के अनुसार बिक्री	12,48,29,121.71	60,70,803.18	41,45,433.13	41,45,433.13	1,43,61,669.44
अंतर	3,98,74,826.60	21,16,276.39	61,63,146.62	61,63,146.62	1,44,42,569.63

ए आई पी (33AAATN0402F1ZD)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	1,91,69,107.00	21,25,983.10	6,60,158.36	6,60,158.36	34,46,299.82
बहियों के अनुसार बिक्री	1,91,51,931.00	21,22,385.00	6,60,396.50	6,60,396.50	34,43,178.00
अंतर	17,176.00	3,598.10	(238.14)	(238.14)	3,121.82

गुवाहाटी (18AAATN0402F1Z5)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	45,74,550.50	1,68,480.90	3,27,469.10	3,27,469.10	8,23,419.10
कम: वित वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	45,455.00	8,181.90			8,181.90
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	45,29,095.50	1,60,299.00	3,27,469.10	3,27,469.10	8,15,237.20
बहियों के अनुसार बिक्री	45,49,666.50	1,60,299.00	3,29,321.80	3,29,321.80	8,18,942.60
अंतर	(20,571.00)	-	(1,852.70)	(1,852.70)	(3,705.40)

कोलकाता (19AAATN0402F1Z3)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	67,77,580.95	8,04,324.42	2,07,820.08	2,07,820.08	12,19,964.58
कम: वित वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	67,77,580.95	8,04,324.42	2,07,820.08	2,07,820.08	12,19,964.58
बहियों के अनुसार बिक्री	71,37,289.24	8,69,073.60	2,07,820.08	2,07,820.08	12,84,713.76
अंतर	(3,59,708.29)	(64,749.18)	-	-	(64,749.18)

मुंबई (27AAATN0402F1Z6)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	1,15,14,639.00	1,75,500.00	9,48,567.53	9,48,567.53	20,72,635.06
कम: वित वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	4,71,610.00		42,444.90	42,444.90	84,889.80
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	1,10,43,029.00	1,75,500.00	9,06,122.63	9,06,122.63	19,87,745.26
बहियों के अनुसार बिक्री	1,10,35,528.60	1,75,500.00	9,05,449.50	9,05,449.50	19,86,399.00
अंतर	7,500.40	-	673.13	673.13	1,346.26

चंडीगढ (04AAATN0402F1ZE)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	51,88,724.00	4,36,531.68	2,40,079.32	2,40,079.32	9,16,690.32
कम: वित वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	7,54,651.00	1,35,837.18			1,35,837.18
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	44,34,073.00	3,00,694.50	2,40,079.32	2,40,079.32	7,80,853.14
बहियों के अनुसार बिक्री	42,09,326.00	3,00,695.00	2,40,160.50	2,40,160.50	7,81,016.00
अंतर	2,24,747.00	(0.50)	(81.18)	(81.18)	(162.86)

गांधीनगर (24AAATN0402F1ZC)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	1,47,04,751.50	4,68,039.15	10,89,408.06	10,89,408.06	26,46,855.27
कम: वित वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	1,47,04,751.50	4,68,039.15	10,89,408.06	10,89,408.06	26,46,855.27
बहियों के अनुसार बिक्री	1,47,25,164.14	4,47,158.50	11,01,684.00	11,01,684.00	26,50,526.50
अंतर	(20,412.64)	20,880.65	(12,275.94)	(12,275.94)	(3,671.23)

जयपुर (08AAATN0402F1Z6)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	50,35,413.67	4,47,131.31	2,18,992.76	2,18,992.76	8,85,116.83
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	50,35,413.67	4,47,131.31	2,18,992.76	2,18,992.76	8,85,116.83
बहियों के अनुसार बिक्री	50,49,112.83	4,47,131.18	2,20,225.68	2,20,225.68	8,87,582.54
अंतर	(13,699.16)	0.13	(1,232.92)	(1,232.92)	(2,465.71)

हैदराबाद (36AAATN0402F1Z7)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	81,00,554.06	6,48,723.08	3,96,275.30	3,96,275.30	14,41,273.68
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	81,00,554.06	6,48,723.08	3,96,275.30	3,96,275.30	14,41,273.68
बहियों के अनुसार बिक्री	81,00,554.06	6,48,724.60	3,96,278.52	3,96,278.52	14,41,281.64
अंतर	-	(1.52)	(3.22)	(3.22)	(7.96)

भुवनेश्वर (21AAATN0402F3ZG)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	1,11,54,557.69	6,37,845.42	6,82,750.62	6,82,750.62	20,03,346.66
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	1,11,54,557.69	6,37,845.42	6,82,750.62	6,82,750.62	20,03,346.66
बहियों के अनुसार बिक्री	1,09,84,506.00	6,07,262.00	6,82,770.00	6,82,770.00	19,72,802.00
अंतर	1,70,051.69	30,583.42	(19.38)	(19.38)	30,544.66

बैंगलोर (29AAATN0402F1Z2)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	32,69,899.15	3,98,617.17	94,982.34	94,982.34	5,88,581.85
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	32,69,899.15	3,98,617.17	94,982.34	94,982.34	5,88,581.85
बहियों के अनुसार बिक्री	32,70,499.15	3,98,617.18	95,036.33	95,036.33	5,88,689.84
अंतर	(600.00)	(0.01)	(53.99)	(53.99)	(107.99)

कानपुर (09AAATN0402F1Z4)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	51,19,653.00	1,83,985.83	3,68,775.86	3,68,775.86	9,21,537.55
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	-	-	-	-	-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	51,19,653.00	1,83,985.83	3,68,775.86	3,68,775.86	9,21,537.55
बहियों के अनुसार बिक्री	50,87,902.08	1,83,985.84	3,65,918.23	3,65,918.23	9,15,822.30
बहियों के अनुसार अचल संपतियों की बिक्री	33,815.00	-	3,043.35	3,043.35	6,086.70
अंतर	(2,064.08)	(0.01)	(185.72)	(185.72)	(371.45)

पटना (10AAATN0402F2ZK)

विवरण	कर योग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-1 के अनुसार बिक्री	77,85,751.57	9,54,754.74	2,23,340.27	2,23,340.27	14,01,435.28
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-1 के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	77,85,751.57	9,54,754.74	2,23,340.27	2,23,340.27	14,01,435.28
बहियों के अनुसार बिक्री	77,85,556.57	9,55,390.86	2,23,004.66	2,23,004.66	14,01,400.18
बहियों के अनुसार अचल संपतियों की बिक्री	3,729.00		335.61	335.61	671.22
अंतर	(3,534.00)	(636.12)	(0.00)	(0.00)	(636.12)

अनुसूची 'ख'

जीएसटीआर 3 बी और बहियों के अनुसार आउटपुट कर का मिलान

मुख्यालय (07AAATN0402F1Z8)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	15,61,78,577.00	82,62,047.38	95,03,813.00	95,03,813.00	2,72,69,673.38
बहियों के अनुसार बिक्री	12,48,29,121.71	60,70,803.18	41,45,433.13	41,45,433.13	1,43,61,669.44
अंतर	3,13,49,455.29	21,91,244.20	53,58,379.87	53,58,379.87	1,29,08,003.94

ए आई पी (33AAATN0402F1ZD)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	1,91,69,107.00	21,25,983.60	6,60,158.36	6,60,158.36	34,46,300.32
बहियों के अनुसार बिक्री	1,91,51,931.00	21,22,385.00	6,60,396.50	6,60,396.50	34,43,178.00
अंतर	17,176.00	3,598.60	(238.14)	(238.14)	3,122.32

गुवाहाटी (18AAATN0402F1Z5)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	45,74,550.50	1,68,481.00	3,27,468.99	3,27,468.99	8,23,418.98
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	45,455.00	8,182.00			8,182.00
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	45,29,095.50	1,60,299.00	3,27,468.99	3,27,468.99	8,15,236.98
बहियों के अनुसार बिक्री	45,49,666.50	1,60,299.00	3,29,321.80	3,29,321.80	8,18,942.60
अंतर	(20,571.00)	-	(1,852.81)	(1,852.81)	(3,705.62)

कोलकाता (19AAATN0402F1Z3)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	67,77,580.95	8,04,324.06	2,07,820.08	2,07,820.08	12,19,964.22
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	67,77,580.95	8,04,324.06	2,07,820.08	2,07,820.08	12,19,964.22
बहियों के अनुसार बिक्री	71,37,289.24	8,69,073.60	2,07,820.08	2,07,820.08	12,84,713.76
अंतर	(3,59,708.29)	(64,749.54)	-	-	(64,749.54)

मुंबई (27AAATN0402F1Z6)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	1,10,36,068.60	1,75,500.00	9,05,449.17	9,05,449.17	19,86,398.34
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	1,10,36,068.60	1,75,500.00	9,05,449.17	9,05,449.17	19,86,398.34
बहियों के अनुसार बिक्री	1,10,35,528.60	1,75,500.00	9,05,449.50	9,05,449.50	19,86,399.00
अंतर	540.00	-	(0.33)	(0.33)	(0.66)

चंडीगढ (04AAATN0402F1ZE)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	51,88,724.00	4,36,532.00	2,40,079.32	2,40,079.32	9,16,690.64
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	7,54,651.00	1,35,837.18			1,35,837.18
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	44,34,073.00	3,00,694.82	2,40,079.32	2,40,079.32	7,80,853.46
बहियों के अनुसार बिक्री	42,09,326.00	3,00,695.00	2,40,160.50	2,40,160.50	7,81,016.00
अंतर	2,24,747.00	(0.18)	(81.18)	(81.18)	(162.54)

गांधीनगर (24AAATN0402F1ZC)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	1,47,04,751.50	4,47,159.15	10,99,848.06	10,99,848.06	26,46,855.27
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित्त वर्ष 2020-21)	1,47,04,751.50	4,47,159.15	10,99,848.06	10,99,848.06	26,46,855.27
बहियों के अनुसार बिक्री	1,47,25,164.14	4,47,158.50	11,01,684.00	11,01,684.00	26,50,526.50
अंतर	(20,412.64)	0.65	(1,835.94)	(1,835.94)	(3,671.23)

जयपुर (08AAATN0402F1Z6)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	50,35,413.67	4,47,131.18	2,18,992.76	2,18,992.76	8,85,116.70
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	50,35,413.67	4,47,131.18	2,18,992.76	2,18,992.76	8,85,116.70
बहियों के अनुसार बिक्री	50,49,112.83	4,47,131.18	2,20,225.68	2,20,225.68	8,87,582.54
अंतर	(13,699.16)	-	(1,232.92)	(1,232.92)	(2,465.84)

हैदराबाद (36AAATN0402F1Z7)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर 3 बी के अनुसार बिक्री	81,00,554.06	6,48,724.60	3,96,278.52	3,96,278.52	14,41,281.64
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	81,00,554.06	6,48,724.60	3,96,278.52	3,96,278.52	14,41,281.64
बहियों के अनुसार बिक्री	81,00,554.06	648724.6	3,96,278.52	3,96,278.52	14,41,281.64
अंतर	-	-	-	-	-

भुवनेश्वर (21AAATN0402F3ZG)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	1,09,84,456.00	6,07,262.00	6,82,770.00	6,82,770.00	19,72,802.00
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	1,09,84,456.00	6,07,262.00	6,82,770.00	6,82,770.00	19,72,802.00
बहियों के अनुसार बिक्री	1,09,84,506.00	6,07,262.00	6,82,770.00	6,82,770.00	19,72,802.00
अंतर	(50.00)	-	-	-	-

बैंगलोर (29AAATN0402F1Z2)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	32,69,899.15	3,98,617.66	94,982.80	94,982.80	5,88,583.26
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री					-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	32,69,899.15	3,98,617.66	94,982.80	94,982.80	5,88,583.26
बहियों के अनुसार बिक्री	32,70,499.15	3,98,617.18	95,036.33	95,036.33	5,88,689.84
अंतर	(600.00)	0.48	(53.53)	(53.53)	(106.58)

कानपुर (09AAATN0402F1Z4)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	51,19,653.00	1,83,986.18	3,68,775.80	3,68,775.80	9,21,537.78
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	-	-	-	-	-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	51,19,653.00	1,83,986.18	3,68,775.80	3,68,775.80	9,21,537.78
बहियों के अनुसार बिक्री	51,21,717.08	1,83,985.84	3,68,961.58	3,68,961.58	9,21,909.00
अंतर	(2,064.08)	0.34	(185.78)	(185.78)	(371.22)

पटना (10AAATN0402F2ZK)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार बिक्री	77,85,751.57	9,54,754.74	2,23,340.27	2,23,340.27	14,01,435.28
कम: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिक्री	-	-	-	-	-
जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कुल बिक्री (वित वर्ष 2020-21)	77,85,751.57	9,54,754.74	2,23,340.27	2,23,340.27	14,01,435.28
बहियों के अनुसार बिक्री	77,89,285.57	9,55,390.86	2,23,340.27	2,23,340.27	14,02,071.40
अंतर	(3,534.00)	(636.12)	-	-	(636.12)

अनुसूची 'ग'

जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-2A के अनुसार इनपुट कर का मिलान

पटना (10AAATN0402F2ZK)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	1,12,485.98	26,045.71	26,045.71	1,64,577.40
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	1,13,287.45	36,491.27	36,491.27	1,86,269.99
अंतर	(801.47)	(10,445.56)	(10,445.56)	(21,692.59)

चंडीगढ़ (04AAATN0402F1ZE)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	10,556.00	92,547.34	92,547.34	1,95,650.68
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	2,994.76	80,083.95	80,083.95	1,63,162.66
अंतर	7,561.24	12,463.39	12,463.39	32,488.02

हैदराबाद (36AAATN0402F1Z7)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	1,61,863.00	1,81,839.00	1,81,839.00	5,25,541.00
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	2,50,265.94	1,89,033.93	1,89,033.93	6,28,333.80
अंतर	(88,402.94)	(7,194.93)	(7,194.93)	(1,02,792.80)

मुख्यालय (07AAATN0402F1Z8)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	5,85,419.00	15,99,993.00	15,99,993.00	37,85,405.00
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	18,13,356.23	17,11,175.66	17,11,175.66	52,35,707.55
अंतर	(12,27,937.23)	(1,11,182.66)	(1,11,182.66)	(14,50,302.55)

बैंगलोर (29AAATN0402F1Z2)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	14,280.00	1,29,129.46	1,24,774.50	2,68,183.96
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	18,997.15	1,12,553.81	1,12,553.81	2,44,104.77
अंतर	(4,717.15)	16,575.65	12,220.69	24,079.19

जयपुर (08AAATN0402F1Z6)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	35,757.00	15,138.86	15,138.86	66,034.72
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	70,065.00	16,142.76	16,142.76	1,02,350.52
अंतर	(34,308.00)	(1,003.90)	(1,003.90)	(36,315.80)

कानपुर (09AAATN0402F1Z4)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	22,744.08	38,650.22	38,650.22	1,00,044.52
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	56,619.95	48,760.99	48,760.99	1,54,141.93
अंतर	(33,875.87)	(10,110.77)	(10,110.77)	(54,097.41)

कोलकाता (19AAATN0402F1Z3)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया		12,740.09	12,740.09	25,480.18
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित		16,288.73	16,288.73	32,577.46
अंतर	-	(3,548.64)	(3,548.64)	(7,097.28)

मुंबई (27AAATN0402F1Z6)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	1,37,470.00	55,127.47	55,127.47	2,47,724.94
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	1,37,470.98	58,622.18	58,622.18	2,54,715.34
अंतर	(0.98)	(3,494.71)	(3,494.71)	(6,990.40)

भुवनेश्वर (21AAATN0402F3ZG)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	1,65,742.84	48,888.61	48,888.61	2,63,520.06
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	3,18,104.32	32,480.24	32,480.24	3,83,064.80
अंतर	(1,52,361.48)	16,408.37	16,408.37	(1,19,544.74)

गुवाहाटी (18AAATN0402F1Z5)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	15,628.00	1,028.00	1,028.00	17,684.00
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	28,674.43	18,902.91	18,902.91	66,480.25
अंतर	(13,046.43)	(17,874.91)	(17,874.91)	(48,796.25)

गांधीनगर (24AAATN0402F1ZC)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	12,998.00	2,26,214.61	2,26,214.61	4,65,427.22
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	53,914.32	1,48,206.75	1,48,206.75	3,50,327.82
अंतर	(40,916.32)	78,007.86	78,007.86	1,15,099.40

ए आई पी (33AAATN0402F1ZD)

विवरण	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल
इनपुट जीएसटीआर -3बी में लिया गया	1,89,441.13	2,72,467.90	2,72,467.90	7,34,376.93
इनपुट जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित	2,57,495.94	4,09,659.56	4,09,659.56	10,76,815.06
अंतर	(68,054.81)	(1,37,191.66)	(1,37,191.66)	(3,42,438.13)

अनुसूची 'घ'

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 और बहियों के अनुसार आउटपुट कर का मिलान

मुख्यालय (07AAATN0402F1Z8)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	16,84,20,437.53	97,28,133.66	94,42,807.88	94,42,807.88	2,86,13,749.42
बहियों के अनुसार बिक्री	10,66,06,233.00	95,32,425.00	96,17,159.00	96,17,159.00	2,87,66,743.00
अंतर	6,18,14,204.53	1,95,708.66	(1,74,351.12)	(1,74,351.12)	(1,52,993.58)

ए आई पी (33AAATN0402F1ZD)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	3,25,14,524.74	8,48,951.00	24,39,920.00	24,39,920.00	57,28,791.00
बहियों के अनुसार बिक्री	3,26,56,050.00	8,41,002.00	23,66,015.00	23,66,015.00	55,73,032.00
अंतर	(1,41,525.26)	7,949.00	73,905.00	73,905.00	1,55,759.00

कोलकाता (19AAATN0402F1Z3)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	1,29,04,083.00	1,54,095.00	10,51,470.00	10,51,470.00	22,57,035.00
बहियों के अनुसार बिक्री	1,29,45,457.00	1,73,242.26	10,51,470.00	10,51,470.00	22,76,182.26
अंतर	(41,374.00)	(19,147.26)	-	-	(19,147.26)

मुंबई (27AAATN0402F1Z6)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	35,93,984.00	1,76,197.00	2,35,359.90	2,35,359.90	6,46,916.80
बहियों के अनुसार बिक्री	35,93,984.00	1,73,242.26	2,35,360.00	2,35,360.00	6,43,962.26
अंतर	-	2,954.74	(0.10)	(0.10)	2,954.54

चंडीगढ़ (04AAATN0402F1ZE)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	60,31,496.00	5,09,859.00	63,265.05	63,265.05	6,36,389.10
बहियों के अनुसार बिक्री	64,62,496.00	5,61,753.00	58,945.00	58,945.00	6,79,643.00
अंतर	(4,31,000.00)	(51,894.00)	4,320.05	4,320.05	(43,253.90)

गांधीनगर (24AAATN0402F1ZC)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	83,70,827.00	4,36,374.00	4,48,843.00	4,48,843.00	13,34,060.00
बहियों के अनुसार बिक्री	84,80,827.00	4,38,282.00	5,17,808.50	5,17,808.50	14,73,899.00
अंतर	(1,10,000.00)	(1,908.00)	(68,965.50)	(68,965.50)	(1,39,839.00)

जयपुर (08AAATN0402F1Z6)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	1,00,47,035.00	8,12,037.00	2,32,785.00	2,32,785.00	12,77,607.00
बहियों के अनुसार बिक्री	1,00,69,875.00	8,12,037.00	2,32,785.00	2,32,785.00	12,77,607.00
अंतर	(22,840.00)	-	-	-	-

भुवनेश्वर (21AAATN0402F3ZG)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	63,93,783.00	5,09,090.94	2,88,990.00	2,88,990.00	10,87,070.94
बहियों के अनुसार बिक्री	63,36,912.00	4,98,854.00	2,88,990.00	2,88,990.00	10,76,834.00
अंतर	56,871.00	10,236.94	-	-	10,236.94

गुवाहाटी (18AAATN0402F1Z5)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	71,78,285.00	3,67,611.30	4,30,740.00	4,30,740.00	12,29,091.30
बहियों के अनुसार बिक्री	71,78,285.00	3,67,612.00	4,30,740.00	4,30,740.00	12,29,092.00
अंतर	-	(0.70)	-	-	(0.70)

हैदराबाद (36AAATN0402F1Z7)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	76,05,258.00	8,50,389.00	2,44,986.00	2,44,986.00	13,40,361.00
बहियों के अनुसार बिक्री	76,05,258.00	8,50,389.00	2,44,986.00	2,44,986.00	13,40,361.00
अंतर	-	-	-	-	-

बैंगलोर (29AAATN0402F1Z2)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	32,48,088.00	3,23,115.84	1,30,770.00	1,30,770.00	5,84,655.84
बहियों के अनुसार बिक्री	32,48,088.00	3,23,115.84	1,30,770.00	1,30,770.00	5,84,655.84
अंतर	-	-	-	-	-

कानपुर (09AAATN0402F1Z4)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	41,93,224.00	1,32,903.36	3,10,938.48	3,10,938.48	7,54,780.32
बहियों के अनुसार बिक्री	41,93,224.00	1,32,903.36	3,10,938.48	3,10,938.48	7,54,780.32
अंतर	-	-	-	-	-

पटना (10AAATN0402F2ZK)

विवरण	करयोग्य	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	कुल कर
जीएसटीआर-9 के अनुसार बिक्री	45,56,295.00	8,09,607.60	5,262.75	5,262.75	8,20,133.10
बहियों के अनुसार बिक्री	45,56,295.00	8,09,607.60	5,262.75	5,262.75	8,20,133.10
अंतर	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	अनु. संख्या		मार्च 2021 के अनुसार		मार्च 2021 के अनुसार
निधियों का स्रोत					
कैपिटल फंड	1		32,29,06,020		32,46,63,578
विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजना	2		6,28,03,045		4,65,07,252
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	3		31,62,93,140		34,11,19,274
योग			**70,20,02,205**		**71,22,90,103**
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थायी परिसंपत्तियां	4				
सकल ब्लॉक- योजना		33,82,69,105		33,81,43,503	
गैर योजना		5,79,21,038	39,61,90,143	5,16,85,790	38,98,29,293
कमः मूल्य ह्रास					
योजना		26,34,09,740		25,34,82,925	
गैर योजना		3,98,27,714	30,32,37,454	3,54,59,328	28,89,42,253
नेट ब्लॉक			**9,29,52,689**		**10,08,87,040**
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम	5				
i) विविध देनदार		4,51,38,965		2,44,99,460	
ii) रोकड़ एवं जमा राशि		17,60,51,236		11,91,71,167	
iii) सावधि जमा में निवेश		15,44,29,965		12,48,93,894	
iv) ऋण एवं अग्रिम		2,75,26,341		3,11,13,930	
v) आयकर वसूली योग्य		3,84,55,711	44,16,02,219	9,57,14,887	39,53,93,337
आस्थगित राजस्व व्यय			-		6,45,46,582
विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित	2		14,35,271		12,09,096
अधिक आय के बावजूद व्यय आधिक्य	6		16,60,12,024		15,02,54,047
योग			**70,20,02,205**		**71,22,90,103**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियां एवं लेखा की टिप्पणियां	16				

संलग्न तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते हरित कुमार गर्ग एवम एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 014584N

सीए हरित कुमार गर्ग, साझेदार
सदस्य संख्याः 094269

कृते राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

डॉ रजत शर्मा
समूह प्रमुख (वित्त)

नविंदर कुमार चांजी
महानिदेशक

दिनांक : 30 नवंबर, 2021
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएनः

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

विवरण	अनु. संख्या	मार्च 2021 को		मार्च 2021 को	
आय					
सरकार से सहायता अनुदान					
योजना					
वर्ष के दौरान प्राप्त		18,20,000		50,00,000	
बैलेंस बी/एफ (+)		23,15,236		24,99,141	
		41,35,236		74,99,141	
घटा: वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्ति		-		-	
		41,35,236		74,99,141	
घटा: अनुदान की अव्ययित शेष राशि		5,74,710	35,60,526	23,15,236	51,83,905
गैर योजना					
वर्ष के दौरान आरईसी अनुदान			20,33,45,000		26,90,00,000
गतिविधि राजस्व	7		20,95,43,754		19,97,32,464
प्रकाशन से प्राप्तियां	8		1,26,350		1,64,884
अन्य रसीदें	9		3,47,01,667		2,88,73,412
कुल			45,12,77,297		50,29,54,666
व्यय					
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	10		35,21,25,523		33,14,60,152
कार्यालय और प्रशासन व्यय	11		-		16,81,01,897
योजना परियोजना*	12		35,60,526		51,83,905
विविध और अन्य शुल्क	13		1,14,603		5,85,762
ब्याज और वित्त शुल्क	14		3,78,093		6,14,662
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	15		-		1,62,874
मूल्यह्रास	4		1,25,37,651		1,19,68,914
व्यय से अधिक आय			8,25,60,901		-1,51,23,499
कुल			**45,12,77,297**		**50,29,54,666**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं लेखा की टिप्पणियां	16				

सम तिथि की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है

हरित सरिस और एसोसिएट के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 014584N

चार्टर्ड अकाउंट हरित कुमार गर्ग, पार्टनर
सदस्यता संख्या : 094269

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के लिए

डॉ रजत शर्मा
समूह प्रमुख (वित्त)

नविंदर कुमार चांजी
प्रबंध संचालक

दिनांक : 30 नवंबर, 2021
जगह: नई दिल्ली
यूडीआईएन:

अनुसूची -2, 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बिभिन्न एजेंसियो (वर्तमान) द्वारा वित्त पोषित परियोजना

	पिछले वर्ष 2018-19 के लिए आंकड़े			परियोजना का नाम	समूह	1.4.2019 तक प्राप्ति	वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्ति	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार योग	1.4.2019 तक व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय	परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार योग	शेष डेबिट	चालू है /बंद
	डी आर	कारोड												
1	-	75,75,896	एबीजी/सी-डीएपी/2017-18	एबी	1,95,96,800	37,13,200	2,33,10,000	1,20,20,904	9,79,732	-	1,30,00,636	-	1,03,09,364	चालू है
2	-	6,11,610	एबीजी/सीएसआईआर-आईएचबीटी/2017-18	एबी	16,87,500		16,87,500	10,75,890		-	10,75,890	-	6,11,610	चालू है
3	-	7,70,084	एबीजी/सीएसआईआर-आईएचबीटी/डब्ल्यूएम-केडी/2019	एबी	9,61,700		9,61,700	1,91,616		-	1,91,616	-	7,70,084	चालू है
4	87,589		एबीजी/डीएसजई/पी/02/2019-20	एबी	14,52,675	19,75,638	34,28,313	15,40,264	18,88,049	-	34,28,313	-		बंद
5	-	54,33,900	एबीजी/मूल्यांकन/पी/डीओसीए/2019-20	एबी	66,65,820	16,66,455	83,32,275	12,31,920	70,99,420	-	83,31,340	-	935	चालू है
6	4,83,428		एबीजी/एमएमए-डीसी/2017-18	एबी	32,27,064		32,27,064	37,10,492		-	37,10,492	4,83,428		चालू है
7	-	13,81,987	एबीजी/एनजबी-आईसीएआरई/2018-19	एबी	26,92,800	2,99,000	29,91,800	13,10,813	16,80,987	-	29,91,800	-	-	बंद
8	94,392	-	एबीजी/पी/04/2019-20	एबी	-	6,18,792	6,18,792	94,392	1,47,328	-	2,41,720	-	3,77,072	चालू है
9	-	16,01,643	एबीजी/पीएफसी/पी/03/2019-20	एबी	19,82,400	5,66,400	25,48,800	3,80,757	1,09,915	-	4,90,672	-	20,58,128	चालू है
10	1,16,280	-	एबीजी/आरकेवीवाई-एलटीपी/2018-19	एबी	4,97,200	7,45,800	12,43,000	6,13,480	6,29,520	-	12,43,000	-	-	बंद
11	-	-	एबीजी/यूपी-आरकेवीवाई/16-17	एबी	1,99,91,400	50,62,200	2,50,53,600	1,82,34,589	68,19,011	-	2,50,53,600	-	-	बंद
12	-	8,01,903	एबीजी/पी/06/2019-20	एबी	10,02,960	18,65,504	28,68,464	2,01,057	27,70,573	-	29,71,630	1,03,166	-	चालू है
13	-	3,17,251	एबीजी/पी/07/2019-20	एबी	5,30,705	5,30,704	10,61,409	2,13,454	8,47,955	-	10,61,409	-	-	बंद
14	-	30,80,735	एनएमपीबी2016-17 (एबी)	एबी	1,47,34,192	1,01,63,084	2,48,97,276	1,16,53,457	11,42,854	-	1,27,96,311	-	1,21,00,965	चालू है
15	2,50,832	-	एबीजी/पी/01/2020-21	एबी	-	5,89,764	5,89,764	-	1,52,124	-	1,52,124	-	4,37,640	चालू है
16	-	-	एबीजी/पी/02/20-21	एबी	-	44,60,400	44,60,400	-	6,80,400	-	6,80,400	-	37,80,000	चालू है
17	74,354	-	एपीडीपी ईएम	ईएम	-		-	2,50,832		-	2,50,832	2,50,832	-	चालू है
18	-	1,09,695	डिप्लोमेट तथा डेमोस्ट्रेशन औफ नीयु फोर इम्प्रूव्ड फोर ग्लास(फेरोज़ाबाद	ईएम	14,10,381		14,10,381	14,84,735		-	14,84,735	74,354	-	चालू है
19	-	-	आरडीडि/ईएम/पी/01/एमएनआरई/बीपीजीटीपी	ईएम	-	5,42,800	5,42,800	-	3,28,450	-	3,28,450		2,14,350	चालू है
20	-	-	ईस्ट थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ईएम, (पश्चिम बंगाल और सिक्किम)	ईएम	72,80,848		72,80,848	71,71,153		-	71,71,153	-	1,09,695	चालू है
21	-	34,567	आरडीडी/ईएम/पी/01/बॉयलर कार्यशालाएं /2019-20	ईएम	-	22,73,860	22,73,860	-	22,73,860	-	22,73,860	-	-	बंद
22	-	-	वेस्ट थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन-ईएम, (दमन और गुजरात)	ईएम	93,68,588		93,68,588	93,34,021		-	93,34,021	-	34,567	चालू है
23	-	-	ईएस/डीआईपीपी/05/2018-19	ई एस	7,89,420	-	7,89,420	3,58,858	4,30,562	-	7,89,420	-	-	बंद
24	-	-	ईएस/डीआईपीपी/पी/02/2016-17	ई एस	38,80,100	-	38,80,100	15,04,436	23,75,664	-	38,80,100	-	-	बंद
25	-	-	ईएस/एनसीयूआई/06/2017-18	ई एस	4,80,000	-	4,80,000	4,70,616	9,384	-	4,80,000	-	-	बंद
26	-	26,41,099	ईएस/प्रोज/एमओटी/14/2018-19	ई एस	-	29,38,200	29,38,200	-	29,38,200	-	29,38,200	-	-	बंद
27	-	2,09,518	मुख्यालय/ईएस/डीआईपीपी/07/2018-19	ई एस	32,70,096	24,53,102	57,23,198	6,28,997	11,97,714	-	18,26,711	-	38,96,487	चालू है
28	-	3,18,954	मुख्यालय/ईएस/डीओज/एआरएस/05/2019-20	ई एस	3,80,000	7,42,000	11,22,000	1,70,482	9,51,518	-	11,22,000	-	-	बंद
29	-	3,74,480	मुख्यालय/ईएस/एमओसी/09/2019-20	ई एस	4,13,000	1,77,000	5,90,000	94,046	4,95,954	-	5,90,000	-	-	बंद
30	-	4,22,602	मुख्यालय/ईएस/एमओसी/11/2019-20	ई एस	4,57,934	1,96,258	6,54,192	83,454	5,70,738	-	6,54,192	-	-	बंद
31	-	6,53,598	मुख्यालय/ईएस/एमओटी/02/2018-19	ई एस	12,32,168	5,28,832	17,61,000	8,09,566	9,51,434	-	17,61,000	-	-	बंद
32	-	5,40,025	मुख्यालय/ईएस/एमओटी/06/2019-20	ई एस	11,45,544	17,18,316	28,63,860	4,91,946	23,71,914	-	28,63,860	-	-	बंद
33	-	4,93,213	मुख्यालय/ईएस/एमओटी/12/2019-20	ई एस	8,38,744	12,58,116	20,96,860	2,98,719	17,98,141	-	20,96,860	-	-	बंद
34	-	7,07,152	मुख्यालय/ईएस/प्रोज/मोट/07/2019-20	ई एस	7,69,310	11,54,040	19,23,350	2,76,097	16,47,253	-	19,23,350	-	-	बंद
35	-	10,33,024	मुख्यालय/ईएस/प्रोज/मोट/08/2019-20	ई एस	9,27,480	6,95,610	16,23,090	2,20,328	2,36,730	-	4,57,058	-	11,66,032	चालू है
36	-	38,72,675	मुख्यालय/ईएस/प्रोज/मोट/16/2019-20	ई एस	12,19,072	18,29,472	30,48,544	1,86,048	28,62,496	-	30,48,544	-	-	बंद
37	-	-	मुख्यालय/ईएस/डीओज/पी/02/2020-21	ई एस	-	29,37,020	29,37,020	-	29,37,020	-	29,37,020	-	-	बंद
38	-	-	मुख्यालय/ईएस/डीपीआईआईटी/पी1/2020-21	ई एस	-	14,22,000	14,22,000	-	5,03,188	-	5,03,188		9,18,812	चालू है
39	-	-	मुख्यालय/आईई/पी/05/2019-20	अयो ई	49,22,370		49,22,370	10,49,695	4,69,996	-	15,19,691	-	34,02,679	चालू है
40	-	4,82,804	मुख्यालय/आईई/टीआरजी/आईएनटीएल/1/19-20	अयो ई	-	44,25,000	44,25,000	-	44,25,000	-	44,25,000	-	-	बंद
41	-	2,68,908	मुख्यालय/आईई/पी/04/2019-20	अयो ई	8,71,548	20,33,612	29,05,160	3,88,744	25,16,416	-	29,05,160	-	-	बंद
42	-	-	मुख्यालय/आईई/पी/01/2020-21	अयो ई	-	30,55,988	30,55,988	-	10,72,479	-	10,72,479		19,83,509	चालू है
43	-	-	मुख्यालय/आईई/पी/02/2020-21	अयो ई	-	23,60,000	23,60,000	-	10,42,211	-	10,42,211		13,17,789	चालू है
44			मुख्यालय/आईई/पी/03/2020-21	अयो ई	-	15,32,230	15,32,230	-	4,36,134	-	4,36,134		10,96,096	चालू है
45	-	-	मुख्यालय/आईई/पी/04/2020-21	अयो ई	-	14,82,080	14,82,080	-	3,03,129	-	3,03,129		11,78,951	चालू है
46	-	-	एनपीसी/मुख्यालय/आईई/पी/05/2020-21	अयो ई	-	34,00,000	34,00,000	-	5,19,639	-	5,19,639		28,80,361	चालू है
47	1,02,221	-	आरडीडी/एन/सी/04/मामा/18-19	ईएन	21,66,480		21,66,480	18,97,572	1,00,000		19,97,572		1,68,908	चालू है
48	-	27,34,096	आरडीडी/एन/पी/01/डीपीसीसी/19-20	ईएन	1,06,867	8,06,925	9,13,792	2,09,088	2,59,332	-	4,68,420	-	4,45,372	चालू है
49	-	45,100	आरडीडी/एन/पी/04/यूएनईपी/19-20	ईएन	39,10,500	41,63,830	80,74,330	11,76,404	20,17,695	-	31,94,099	-	48,80,231	चालू है
50	-	73,13,162	आरडीडी/एन/पी/05/डीपीसीसी/19-20	ईएन	64,900		64,900	19,800	45,100	-	64,900	-	-	बंद
51	-	-	आरडीडी/एन/पी/05/एमओईएफसीसी/18-19	ईएन	2,04,53,632	72,24,448	2,76,78,080	1,31,40,470	1,45,37,610	-	2,76,78,080	-	-0	बंद
52	-	9,00,000	आरडीडी/एन/पी/07/डीपीआईआईटी/2019-20	ईएन	-	3,44,560	3,44,560	-	3,44,560	-	3,44,560	-	-	बंद
53	-	14,49,571	आरडीडी/एन/पी/01/यूपीपीसीबी/20-21	ईएन	1,73,900		1,73,900	1,62,000	11,900	-	1,73,900	-	-	बंद
54	-	3,28,000	आरडीडी/एन/पी/06/एमओईएफसीसी/19-20	ईएन	33,67,200	60,88,053	94,55,253	19,17,629	13,00,103	-	32,17,732	-	62,37,521	चालू है
55	-	-	आरडीडी/एन/पी/01/डीओई/20-21	ईएन	-	23,89,500	23,89,500	-	19,36,400	-	19,36,400	-	4,53,100	चालू है
56	-	-	आरडीडी/एन/पी/02/यूएनडीपी/20-21	ईएन	-	22,60,870	22,60,870	-	22,60,870	-	22,60,870	-	-	बंद
57	-	-	आरडीडी/एन/पी/03/डीपीआईआईटी/2019-20	ईएन	-	1,57,766	1,57,766	-	3,15,480	-	3,15,480	1,57,714	-	चालू है
58	-	-	आरडीडी/एन/पी/03/यूएनडीपी/2020-21	ईएन	-	16,93,536	16,93,536	-	18,59,388	-	18,59,388	1,65,852	-	चालू है
59	-	-	आरडीडी/एन/पी/11/बीईआईएल/2020-21	ईएन	-	5,60,500	5,60,500	-	5,60,500	-	5,60,500	-	-	बंद
60	-	-	आरडीडी/एन/पी/15/नोएडा/2020-21	ईएन	-	11,94,160	11,94,160	-	13,94,085	-	13,94,085	1,99,925	-	चालू है
61	-	-	आरडीडी/एन/पी/16/डब्ल्यूएचओ/20-21	ईएन	-	13,70,000	13,70,000	-	9,94,600	-	9,94,600	-	3,75,400	चालू है
62	-	-	आरडीडी/एन/पी/17/एमओपीएसडब्ल्यू/20-21	ईएन	-	7,00,000	7,00,000	-	4,23,422	-	4,23,422	-	2,76,578	चालू है
63	-	0	आईडीडी/ईएन/पी/07/एमओपीजयओरई/19-20	ईएन	4,00,000	7,80,000	11,80,000	72,000	11,08,000	-	11,80,000	-	-	बंद
64	-	0	आरडीडी/एन/पी/13/एमईआईटीवाई/20-21	ईएन	-	13,31,040	13,31,040	-	-	-	-		13,31,040	चालू है
65	-	0	आरडीडी/एचआरएम/पी/01/17-18 (सीजीपीडीटीएम)	एचआरएम/आरडी	4,79,50,380		4,79,50,380	4,79,50,380	-	-	4,79,50,380	-	0	बंद
65	-	-	एस आई डी ए	जीडीएनजीआर	68,60,918	-	68,60,918	48,74,389	1,35,939	18,50,590	68,60,918	-0	0	बंद
	12,09,096	4,65,07,252	कुल		20,01,34,596	10,24,67,435	30,26,02,031	14,91,65,590	9,02,18,076	18,50,590	24,12,34,257	14,35,271	6,28,03,045	

अनुसूची संख्या 4 अचल संपत्ति

समोकित-स्थायी परिसम्पत्ति चार्ट

क्र. सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	लागत					मूल्यह्रास				आंकित मूल्य	
		1.4.2020 को कुल योग	प्रथम अर्ध के दौरान जोड़	द्वितीय अर्ध के दौरान जोड़	बिक्री/अंतरण बट्टे खाता/पुनः वर्गीकृत**	31.3.2021 को कुल योग	मूल्यह्रास1.4.2020	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण बट्टे खाता	31.3.2021 को कुल योग	31.3.2021 को अंकित मूल्य	31.3.2020 को अंकित मूल्य
		1	2	3	4	5=(1+2+3-4)	6	7	8	9=(6+7-8)	10=(5-9)	11
	क गैर योजना											
1	भूमि	2,58,786	-	-	-	2,58,786	-	-	-	-	2,58,786	2,58,786
2	भवन	1,10,07,314	-	-	-	1,10,07,314	61,09,500	4,89,781	-	65,99,281	44,08,033	48,97,814
3	संयंत्र एवं मशीनरी	32,90,005	8,13,841	61,827	-	41,65,673	23,15,390	2,72,905	-	25,88,295	15,77,377	9,74,615
4	वैद्युत उपकरण	23,16,464	65,400	16,654	27,290	23,71,228	10,57,166	1,96,139	-	12,53,305	11,17,923	12,59,298
5	कार्यालय उपकरण	44,00,692	83,275	99,230	1,54,976	44,28,221	37,42,511	95,414	-	38,37,925	5,90,295	6,58,181
6	कंप्यूटर	1,20,73,068	41,32,444	3,53,032	702	1,65,57,842	1,01,89,010	24,77,207	-	1,26,66,217	38,91,625	18,84,059
7	फर्नीचर एवं फिक्सचर	68,14,682	1,60,208	6,34,311	5,169	76,04,032	30,21,912	4,26,496	-	34,48,409	41,55,623	37,92,770
8	वाहन	34,15,225	-	-	-	34,15,225	26,45,311	1,15,485	-	27,60,795	6,54,430	7,69,914
9	श्रवण दृश्य उपकरण	43,36,121	-	-	-	43,36,121	27,45,355	2,38,605	-	29,83,959	13,52,162	15,90,767
10	बुक	35,91,831	10,776	360	12,473	35,90,494	35,65,888	9,771	-	35,75,658	14,836	25,943
11	सॉफ्टवेयर	1,81,602	4,500	-	-	1,86,102	67,286	46,582	-	1,13,868	72,234	1,14,316
	योग क (गैर योजना)	5,16,85,790	52,70,444	11,65,414	2,00,610	5,79,21,038	3,54,59,328	43,68,386	-	3,98,27,714	1,80,93,324	1,62,26,462
	ख योजना											
1	भवन	12,23,69,075	-	-	24,289	12,23,44,786	6,65,65,233	55,77,955	-	7,21,43,188	5,02,01,598	5,58,03,842
2	संयंत्र एवं मशीनरी	8,22,44,717	-	-	5,085	8,22,39,632	6,76,30,841	21,91,319	-	6,98,22,160	1,24,17,472	1,46,13,876
3	वैद्युत उपकरण	79,41,455	-	-	-	79,41,455	58,82,924	3,08,780	-	61,91,704	17,49,751	20,58,531
4	कार्यालय उपकरण	2,39,27,726	-	-	-	2,39,27,726	1,57,18,531	12,31,379	-	1,69,49,910	69,77,816	82,09,195
5	कंप्यूटर	7,33,17,957	1,54,976	-	-	7,34,72,933	7,30,52,587	1,68,139	-	7,32,20,725	2,52,208	2,65,370
6	फर्नीचर एवं फिक्सचर	83,69,120	-	-	-	83,69,120	57,14,015	2,65,511	-	59,79,525	23,89,595	26,55,105
7	वाहन	20,02,543	-	-	-	20,02,543	17,82,015	33,079	-	18,15,094	1,87,449	2,20,528
8	श्रवण दृश्य उपकरण	33,38,238	-	-	-	33,38,238	26,91,629	96,991	-	27,88,620	5,49,618	6,46,609
9	प्रयोगशाला उपकरण	8,000	-	-	-	8,000	2,654	802	-	3,447	4,553	5,347
10	पुस्तक	45,66,850	-	-	-	45,66,850	44,68,609	39,296	-	45,07,905	58,945	98,241
12	सॉफ्टवेयर	95,24,634	-	-	-	95,24,634	95,14,812	2,456	-	95,17,268	7,367	9,822
13	मुख्य कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ईपीएबीएक्स प्रणाली	5,33,188	-	-	-	5,33,188	4,59,077	11,117	-	4,70,194	62,994	74,111
	योग ख	33,81,43,503	1,54,976	-	29,374	33,82,69,105	25,34,82,925	99,26,823	-	26,34,09,740	7,48,59,365	8,46,60,578
	(योग (क+ख)	38,98,29,293	54,25,420	11,65,414	2,29,984	39,61,90,143	28,89,42,253	1,42,95,209	-	30,32,37,454	9,29,52,689	10,08,87,040

अनुसूची: 1 पूंजी कोष

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
विगत वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार अथशेष*	32,46,63,578	32,65,64,894
अधिकः वर्ष के दौरान अनुदार निधि से खरीदी गई परिसम्पत्ति	-	1,66,400
कमः जापान द्वारा परिसम्पत्ति पर मूल्य ह्रास**	17,57,558	20,67,716
कुल	**32,29,06,020**	**32,46,63,578**

* पिछले वर्षों में जापान सरकार द्वारा दान की गई संपत्ति शामिल है।
** 01.04.2020 @ 15% के अनुसार डब्लूडीवी पर रु.11717055/- का मूल्यह्रास

अनुसूची: 3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
ए: वर्तमान देयताएं		
विविध लेनदार	1,25,69,675	21,21,985
विविध लेनदार आरडी	15,70,371	47,87,490
अन्य देय-मुख्यालय	4,41,90,485	7,18,09,429
अन्य देय-क्षेत्रीय निदेशालय	1,51,40,683	1,31,01,874
अव्ययित शेष (योजना)	5,74,710	23,15,236
विक्रेता से अग्रिम	73,31,326	65,10,870
उप कुल ए	**8,13,77,251**	**10,06,46,884**
बी: प्रावधान		
नकदीकरण छोड़े		
पिछले खाते के अनुसार	9,44,53,628	-
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	2,74,62,054	9,44,53,628
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान	1,40,99,626	-
समाप्ति के समय बकाया	**10,78,16,056**	**9,44,53,628**
ग्रेच्युटी		
पिछले खाते के अनुसार	14,60,18,762	15,43,29,463
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	65,71,079	1,89,49,359
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान	2,54,90,008	2,72,60,060
समाप्ति के समय बकाया	**12,70,99,833**	**14,60,18,762**
उप कुल बी	**23,49,15,889**	**24,04,72,390**
कुल (ए+बी)	**31,62,93,140**	**34,11,19,274**

अनुसूची : 5 वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
विविध देनदार		
i) अच्छा माना जाता है	4,51,38,965	2,44,99,459
ii) संदिग्ध माना जाता है	1,73,11,052	1,38,94,435
कुल बही ऋण	**6,24,50,017**	**3,83,93,894**
कमः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,73,11,052	1,38,94,435
संदिग्ध ऋणों को छोड़कर कुल बही ऋण	**4,51,38,965**	**2,44,99,459**
रोकड़ एव बही शेष		
i) इंडियन ओवरसीज बेंक सीसी खाता 10700	7,86,82,422	-
ii) नकद राशि- आरडी	-	9,171
iii) इंडियन ओवरसीज बेंक/ आरडी योजना	-	11,966
iv) इंडियन ओवरसीज बेंक/बी-मुख्यालय-योजना	7,88,494	32,63,725
v) नकद डाक-शुल्क सहित एफएम-मुख्यालय	-	-
vi) नकद डाक शुल्क सहित/एफएम- आरडी	12,243	449
vii) इंडियन ओवरसीज बेंक/बी-मुख्यालय	6,64,37,133	10,36,15,117
viii) इंडियन ओवरसीज बेंक सीसी 850-मुख्यालय	1,64,84,952	12,132
ix) इंडियन ओवरसीज बेंक-II आरडी	1,36,45,992	1,22,58,608
कुल	**17,60,51,236**	**11,91,71,167**
ग्रेच्युटी और अन्य निवेश		
i) सावधि जमा (एफडीआर)	15,44,29,965	12,48,93,894
कुल	**15,44,29,965**	**12,48,93,894**
ऋण और अग्रिम		
i) स्टाफ-मुख्यालय को त्योहार अग्रिम	-	-
ii) स्टाफ-आरडी को त्योहारी अग्रिम	-	-
iii) स्टाफ-मुख्यालय से सलाह वसूली	12,08,127	8,31,937
iv) स्टाफ आरडी से सलाह वसूली	4,11,621	21,08,276
v) दूसरों से सलाह वसूली-आरडी	-	1,50,000
vi) अन्य वसूली योग्य	35,99,684	2,06,66,331
vii) सुरक्षा जमा/ई.एम-मुख्यालय	26,57,028	59,14,728
viii) सुरक्षा जमा/ई.एम.-आरडी	17,31,455	13,01,958
ix) अन्य वसूली योग्य मुख्यालय / विविध	1,79,18,427	1,40,700
कुल	**2,75,26,341**	**3,11,13,930**
टी.डी.एस. (वसूली योग्य)		
मुख्यालय	2,24,78,424	5,15,93,600
क्षेत्रीय निदेशालय	1,59,77,287	4,41,21,287
कुल	**3,84,55,711**	**9,57,14,887**
कुल योग	**44,16,02,219**	**39,53,93,337**

अनुसूची: 6 आय से अधिक व्यय

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
प्रारंभिक जमा	15,02,54,047	13,51,30,548
जमा/घटा		
व्यय से अधिक आय	2,30,98,098	1,51,23,499
कुल	**17,33,52,144**	**15,02,54,047**

अनुसूची:7 गतिविधि राजस्व

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम से रसीद	20,14,95,151	15,59,64,996
सेल्फ रन प्रोग्राम	80,31,128	4,32,60,056
आवेदन प्रसंस्करण शुल्क	17,475	5,07,412
कुल	**20,95,43,754**	**19,97,32,464**

अनुसूची-8 प्रकाशन से प्राप्तियां

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	As at March 2020
प्रकाशन से स्वत्व-शुल्क	1,26,350	1,64,884
योग	**1,26,350**	**1,64,884**

अनुसूची-9 अन्य प्राप्तियां

विवरण	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
ब्याज प्राप्ति	1,32,77,678	1,09,57,464
विविध प्राप्ति	1,01,183	1,19,235
किराया प्राप्ति	1,61,71,576	1,29,98,819
सम्मेलन कक्ष प्रभार	20,000	6,69,400
आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	46,73,075	41,28,495
प्रावधान वापस लिखा गया	4,58,155	-
योग	**3,47,01,667**	**2,88,73,412**

अनुसूची संख्या:10 कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ

अनु. सख्या	व्यय की मद	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2021 को कुल योग	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2020 को कुल योग
1	वेतन और भत्ते / वजीफा	8,35,35,612	14,31,59,506	22,66,95,118	10,71,31,908	14,55,03,568	25,26,35,476
2	सीपीएफ (काउंसिल शेयर)	2,16,76,278	-	2,16,76,278	2,49,42,017	-	2,49,42,017
3	ग्रेच्युटी	65,67,605	-	65,67,605	1,89,49,359	-	1,89,49,359
4	कर्मचारी कल्याण और सीजीएचएस	17,53,507	23,07,491	40,60,998	23,47,736	28,56,889	52,04,625
5	अवकाश नकदिकरन	9,20,08,636	-	9,20,08,636	2,85,91,745	-	2,85,91,745
6	कैंटीन और कल्याण	8,09,623	2,67,265	10,76,888	9,38,859	1,58,071	10,96,930
7	अनुकंपा निधि	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
	कुल	**20,63,91,261**	**14,57,34,262**	**35,21,25,523**	**18,29,41,624**	**14,85,18,528**	**33,14,60,152**

* वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6,45,46,582/- रुपये के खर्च के रूप में अवकाश नकदीकरण का आस्थगित राजस्व व्यय

अनुसूची संख्या: 11 कार्यालय और प्रशासनिक व्यय

अनु. सख्या	व्यय की मद	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	22,66,95,118	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	Total As at March 2020
1	एएमसी और रखरखाव	8,62,141	6,96,442	15,58,583	17,73,568	12,92,370	30,65,938
2	लेखा - परिक्षण शुल्क	1,50,000	-	1,50,000	1,50,000	-	1,50,000
3	भवन और हाउसकीपिंग और किराया	92,74,496	82,02,261	1,74,76,757	96,68,551	92,57,915	1,89,26,466
4	व्यावसायिक गतिविधि का विकास	14,82,521	2,39,983	17,22,503	35,99,900	6,10,541	42,10,441
5	विशेषज्ञ शुल्क / वेतन अनुबंध	1,63,40,479	49,24,316	2,12,64,795	1,45,75,640	31,52,330	1,77,27,970
6	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	66,500	36,55,972	37,22,472	1,42,000	11,02,542	12,44,542
7	छपाई और स्टेशनरी	10,54,093	4,07,347	14,61,440	27,87,123	9,66,904	37,54,027
8	कार्यक्रम गतिविधि Exp	1,70,47,759	1,46,82,482	3,17,30,242	1,27,71,302	4,37,12,645	5,64,83,947
9	हिंदी में प्रचार कार्य	5,64,706	2,000	5,66,706	1,03,097	47,455	1,50,552
10	एमएसएमई-एलएमसीएस.Exp	-	-	-	-	1,67,020	1,67,020
11	टेलीफोन और डाक	6,53,483	3,97,881	10,51,364	7,92,938	11,76,791	19,69,729
12	यात्रा भत्ता/एलसी/एलटीसी।	89,57,475	30,40,126	1,19,97,601	78,30,623	74,85,914	1,53,16,536
13	वाहन रखरखाव	3,29,853	-	3,29,853	3,18,102	-	3,18,102
14	दरें और कर	-6,68,901	1,78,246	-4,90,655	7,94,750	33,018	8,27,768
15	पूर्व अवधि समायोजन	16,26,547	77,577	17,04,124	1,61,74,069	36,07,814	1,97,81,883
16	ईएमडी बट्टे खाते में डाला गया	-	-	-	27,550	1,47,178	1,74,728
17	देनदार बट्टे खाते मे डाला गया	-	2,38,305	2,38,305	-	94,929	94,929
18	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	3,88,170	-	3,88,170	1,55,35,797	-	1,55,35,797
19	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34,16,617	-	34,16,617	21,40,561	-	21,40,561
20	उत्पादकता सप्ताह exp	30,000	-	30,000	2,25,000	2,69,562	4,94,562
21	जल शुल्क बकाया	-	-	-	48,68,309	-	48,68,309
22	आईटीसी रिवर्सल (जीएसटी छूट आपूर्ति)	-	-	-	2,40,994	4,57,096	6,98,090
	कुल	**6,15,75,939**	**3,67,42,939**	**9,83,18,878**	**9,45,19,873**	**7,35,82,023**	**16,81,01,897**

अनुसूची संख्या:12 योजना परियोजना व्यय

अनु स.	व्यय की मद	मार्च 2021 को कुल योग	मार्च 2020 को कुल योग
स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित समर्थन			
1	एआइपी का उत्कृष्टता केंद्र में उन्नयन ((स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता - नई योजना 2017-18)	-	25,76,149
2	सीओई फोर आईटी फोर इंडस्ट्री 4.0(2018-2019)	-	11,04,668
3	गुणवत्ता प्रबंधन पर सीओई (सीओई-क्यूएम)	1,19,634	3,92,000
4	सीओई फोर आईटी फोर इंडस्ट्री 4.0(2018-2019)	-	11,11,088
5	सीओई फोर आईटी फोर इंडस्ट्री 4.0(2019-2020)	11,84,670	-
6	सीओई फोर आईटी फोर इंडस्ट्री 4.0(2020-2021)	15,69,708	-
7	गुणवत्ता प्रबंधन पर सीओई	6,86,514	-
		-	
	कुल	**35,60,526**	**51,83,905**

अनुसूची संख्या 13 विविध और अन्य शुल्क

अनु. संख्या	व्यय की मद	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2021 को कुल योग	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2020 को कुल योग
1	विविध व्यय	7,736	36,333	44,070	2,92,842	1,43,840	4,36,682
2	संपत्ति की बिक्री पर नुकसान	-	-	-	8,329	-	8,329
3	जनेल/आर्वधिक की सदस्यता	70,533	-	70,533	1,13,348	27,403	1,40,751
	कुल	**78,269**	**36,333**	**1,14,603**	**4,14,519**	**1,71,243**	**5,85,762**

अनुसूची संख्या:14 ब्याज और वित्त प्रभार

अनु. संख्या	व्यय की मद	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2021 को कुल योग	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2020 को कुल योग
1	बैंक शुल्क	3,50,381	27,712	3,78,093	5,86,227	28,434	6,14,662
	कुल	**3,50,381**	**27,712**	**3,78,093**	**5,86,227**	**28,434**	**6,14,662**

*** बैंक शुल्क में ब्याज शुल्क शामिल है

अनुसूची संख्या: 15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

hba	व्यय की मद	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2021 को कुल योग	मुख्यालय	क्षेत्रीय निदेशालय	मार्च 2020 को कुल योग
1	एपीओ कार्यक्रम	-	-	-	1,13,432	49,442	1,62,874
	कुल	**-**	**-**	**-**	**1,13,432**	**49,442**	**1,62,874**

अनुसूची संख्या 16: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर नोट

क). सामान्य

i) विगत वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहबद्ध किया गया है और इनमें जरूरत के आधार पर फिर से व्यवस्थित किया गया है।

ii) अनुसूची संख्या 1 से 15 तक तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।

ख). तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

i) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति अनुसार विविध देनदार, विविध लेनदार, वसूली योग्य अग्रिम, भुगतान योग्य अग्रिम, सुरक्षा शेषलंबित/ भुगतान सहित/ विभिन्न एजेंसियां/ पार्टियों के बकाए की सभी शेष राशियां पुष्टिकरण और समन्वय के अध्ययधीन हैं।

ii) अनुसूची 2: परियोजना खाता विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं से संबंधित है।.

क) निवल ऋण शेष : प्राप्तियों में से पूंजीगत और राजस्व व्यय को घटाना।

ख) निवल जमा शेष : पूंजीगत और राजस्व व्यय में से प्राप्तियों को घटाना।

iii) इस वर्ष के दौरान ग्रच्युटी के लिए 65,71,079/- रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।(गतवर्ष 1,89,49,359/- रु.)

iv) मुख्यालय में स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर दो भागों अर्थात दिनांक 17-10-2005 से पूर्व एक तथा संशोधित जीआर फार्मेट में 17-10-2005 से पश्चात दूसरा उपलब्ध हैं। कुछेक स्थायी परिसम्पत्तियों का पूर्ववर्ती वर्षों में निपटान कर दिया गया लेकिन बिक्री आगम को बेची गई परिसम्पत्ति की लागत में उसे जोड़ने के बजाय आय एवं व्यय लेखा में प्राप्तियां मानी गई और तथापि उन परिसम्पत्तियों के अंकित शेष को बट्टेखाते में डालने से सकल और निवल ब्लॉकों में थोड़ा अंतर हो सकता है जिसे उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। वर्ष के दौरान इस संबंध में परिषद द्वारा कोई समायोजन नहीं किया गया।

v) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 12 आरडी और मुख्यालयों की स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया।

ग). प्रावधान

i) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी नकदीकरण भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6,45,46,582/- रु. प्रावधान किया गया है।

ii) वित्तवर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में एमएसीपी के कार्यान्वयन के लिए 25,00,000/- रु का प्रावधान किया गया था। (गत वर्ष 25,00,000/- रु.)

iii) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19/3/2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/02/2011-III/ए के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एकबारगी वेतनवृद्धि के बकाए भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 4,46,76,989/-रु. का प्रावधान किया गया था जिसमें से रूपये 2,30,47,408/- का भुगतान चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया और शेष को अग्रेषित कर दिया गया है।

घ). आकस्मिक देयताएं

i) कन्सलटेंसी रोज़गारों के ग्राहकों के पक्ष में 173.32 लाख रु. (विगत वर्ष 206.28 लाख रु.) की बैंक गारंटी जमा कराई गई।

ii) परिषद के नाम पर आयकर विभाग के ऑनलाईन टीडीएस पोर्टल के अनुसार 10,94,420/-रु. के लिए पूर्ववर्ती मूल्यांकन वर्षों के लिए टीडीएस विवरणों में दोषों के संबंध में सीपीसी (टीडीएस) से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका मिलान किया जा रहा है।

iii) परिषद को तेलंगाना स्टेट हाउसिंग बोर्ड से 1,00,37,846/- रु. (68,08,509/- रु. किराए तथा 32,29,336/- रु. ब्याज) के लिए हैदराबाद आरडी के किराए के बकाए के लिए नोटिस मिला है जिसमें से 68,08,509/- रु. का प्रावधान कर दिया गया है तथा 32,29,336/- रु. की ब्याज की राशि छोड़ने के लिए तेलंगाना स्टेट हाउसिंग बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी को एक अनुरोध पत्र भेजा गया है।

ड.) 705, भीकाजी कामा भवन, भीकाजी कामा पेलस, नई दिल्ली एवं मुख्यालय भवन के भू तल और प्रथम तल को लीज़ पर देना

मुख्यालय भवन की पहली मंजिल को रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, एनसीआर, बायोटेक साइंस क्लस्टर, भांकरी, फरीदाबाद को रुपये 1,18,31,216/-, की राशि के लिए पट्टे पर दिया गया था। भूतल के कुछ क्षेत्र को 25,76,760/- रुपये में जीवन विज्ञान संस्थान को पट्टे पर दिया गया था और 705, भीकाजी कामा भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को 17,28,000/- रुपये के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया था। ।

च). अन्य

i) परिषद के विभिन्न आरडी और मुख्यालय में बैंक खाते हैं। इन सभी खातों का उचित रूप से मिलान किया जाता है।

ii) परिषद की 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 84.35 लाख रु. के आयकर रिफंड टीडीएस की वसूली बकाया है। परिषद मूल्यांकन वर्ष 2015-16 एवं पूर्ववर्ती वर्षों की

उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए आशान्वित है जहां आयकर मूल्यांकन पूरा हो गया है। परिषद आयकर विभाग से पुराने रिफंड की वसूली का प्रयास कर रही है।

iii) वर्तमान दायित्वों में डॉ. वी.पी.सभरवाल द्वारा दिए गए एक्यूरियल सर्टिफिकेट के अनुसार दिनांक 31.03.2021 की स्थिति अनुसार 1270.99 लाख रु. की ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष 1460.19 लाख रु.)। इसके अतिरिक्त, परिषद ने आईओबी के पास 621.16 लाख रु. (पिछले वर्ष 575.99 लाख रु.) का एफडीआर उद्दिष्ट किया है।

iv) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति अनुसार 6,24,50,017/-रु.का बुक्स डेबिट बकाया है जिसमें से 1,73,11,052/-रु. का बुक्स डेबिट तीन वर्षों से अधिक पुराना शामिल है। परिषद ने 1,73,11,052/- रु. की सन्देहप्रद डेबिट राशि के लिए प्रावधान किया है।

v) वर्ष के दौरान विभिन्न पार्टियों से परिषद के बचत बैंक खातों में 73.31 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई। पहचान के अभाव में उपर्युक्त राशि को अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत रखा गया। दिनांक 31-03-2021 को परिषद ने जीएसटी रिटर्न में परामर्श आय के रूप में दर्शाया है और पार्टियों की बगैर पहचान/मिलान के अपनी निधि से जीएसटी का भुगतान भी किया है।

vi) लेखा परीक्षा के अन्तर्गत, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, मुख्यालय और आरडी में दिनांक 31-03-2021 को 9,61,628/- रु. के स्त्रोत में काटे गए आयकर के लिए 26एएस में क्रेडिट चूक है जिसका मिलान किया जा रहा है।

vii) वर्तमान दायित्वों में एपीओ अग्रिम के रूप में 2,59,952/- रु. शामिल हैं। इस राशि को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय के उद्देश्य से एशियन उत्पादकता संगठन से प्राप्त किया गया था।

viii) वर्तमान दायित्वों में विगत वर्षों के न्यायालय मामले के 1,42,628/- रु. शामिल हैं। यह राशि विभिन्न सोसाइटियों, जिनके विरुद्ध न्यायालय मामले चल रहे हैं, के भुगतान के लिए थी।

ix) परिषद ने विगत वर्षों में स्वीडिश इन्टरनेशनल ऑथर्टी से 68,60,918/- रु. प्राप्त किए थे जिससे स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय पहले ही कर लिया था।

ग्रुप प्रमुख (वित्त) **महानिदेशक**

विविध लेनदारों का विवरण							
31.3.2021 तक							
		मार्च 2021 को कुल योग			मार्च 2020 को		
क्र.सं.	शीर्ष	मुख्यालय	आरएमपीजी	कुल	मुख्यालय	आर यम पी जी	कुल
क	विविध लेनदार	1,25,69,675	15,70,371	1,41,40,046	21,21,985	47,87,490	69,09,475
		1,25,69,675	**15,70,371**	**1,41,40,046**	**21,21,985**	**47,87,490**	**69,09,475**
ख	अन्य भुगतान योग्य						
1	वेतन देय	26,95,305	-	26,95,305	25,30,522	-	25,30,522
2	देय किराया	-	69,40,453	69,40,453	-	71,77,666	71,77,666
3	सीएफसी	30,297	-	30,297	34,237	-	34,237
4	देय सीपीसी (छठा और सातवां)	2,16,29,581	-	2,16,29,581	4,46,76,989	-	4,46,76,989
5	टीडीएस देय	7,62,166	16,75,203	24,37,369	2,46,600	6,07,329	8,53,929
6	जीएसटी देय	33,27,980	12,97,038	46,25,019	21,86,335	14,79,485	36,65,820
7	प्रतिधारण धन	-	3,00,501	3,00,501	-	11,04,944	11,04,944
8	बयाना राशि / सुरक्षा	56,10,941	8,04,443	64,15,384	50,70,012	-	50,70,012
9	परिषद शेयर देय	8,20,311	-	8,20,311	19,38,174	-	19,38,174
10	वृत्ति कर	-	29,540	29,540	-	1,815	1,815
11	देय व्यय	34,13,033	40,93,505	75,06,538	86,67,891	27,30,635	1,13,98,526
12	एनपीसी टी/सी सोसायटी	5,119	-	5,119	5,31,343	-	5,31,343
13	कोर्ट केस की वसूली	18,30,604	-	18,30,604	18,30,604	-	18,30,604
14	कोर्ट केस कटौती	1,41,928	-	1,41,928	-	-	-
15	अन्य देय	39,23,220	-	39,23,220	40,96,722	-	40,96,722
	कुल	**4,41,90,485**	**1,51,40,683**	**5,93,31,168**	**7,18,09,429**	**1,31,01,874**	**8,49,11,303**

विविध देनदारों का विवरण							
31.3.2021 को							
		मार्च 2020 को कुल योग			मार्च 2020 को कुल योग		
क्र.सं.	शीर्ष	मुख्यालय	आरडि	कूल	मुख्यालय	आरडि	कुल
क	विशेषज्ञ प्रभार	2,47,66,920	3,76,83,096	6,24,50,017	1,47,68,985	2,36,24,909	3,83,93,895
	कुल	2,47,66,920	**3,76,83,096**	6,24,50,017	1,47,68,985	**2,36,24,909**	3,83,93,895
B	अन्य पुनर्प्राप्त करने योग्य						
1	सामूहिक बीमा	-	-	-	715	-	715
2	रिटेंशन बैक ए / सी	-	6,97,744	6,97,744	-	6,97,744	6,97,744
3	कार्यक्रम ए / सी	77,53,775	-	77,53,775	1,05,43,339	-	1,05,43,339
4	अशोक पेट्रोनेट	-	-	-	75,954	-	75,954
5	प्रीपेड खर्च	10,34,388	3,33,177	13,67,565	3,19,300	3,28,994	6,48,294
6	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	90,40,210	-	90,40,210	87,00,286	-	87,00,286
7	विविध देनदार	90,054	7,566	97,620	-	-	-
		1,79,18,427	**10,38,487**	**1,89,56,914**	**1,96,39,593**	**10,26,738**	**2,06,66,331**
	टीडीएस एवाई बकाया						
	टीडीएस एवाई 2006-07	87,774	13,89,437	14,77,211	87,774	13,89,437	14,77,211
	टीडीएस एवाई 2007-08	14,54,888	16,44,615	30,99,503	14,54,888	16,44,615	30,99,503
	टीडीएस एवाई 2010-11	7,41,136	-	7,41,136	7,41,136	-	7,41,136
	टीडीएस एवाई 2011-12	12,78,978	-	12,78,978	12,78,978	-	12,78,978
	टीडीएस एवाई 2012-13	9,43,550	-	9,43,550	9,43,550	-	9,43,550
	टीडीएस एवाई 2013-14	11,296	-	11,296	11,296	-	11,296
	टीडीएस एवाई 2014-15	2,43,631	-	2,43,631	2,43,631	-	2,43,631
	टीडीएस एवाई 2015-16	6,40,051	-	6,40,051	6,40,051	-	6,40,051
	टीडीएस एवाई 2016-17	-	-	-	63,72,631	83,41,628	1,47,14,259
	टीडीएस एवाई 2017-18	-	-	-	89,89,295	77,03,369	1,66,92,664
	टीडीएस एवाई 2018-19	-	-	-	1,09,61,186	79,16,030	1,88,77,216
	टीडीएस एवाई 2019-20	-	-	-	95,70,763	98,63,620	1,94,34,383
	टीडीएस एवाई 2020-21	1,02,98,421	72,68,558	1,75,66,979	1,02,98,421	72,62,588	1,75,61,009
		67,78,699	56,74,677	1,24,53,376	-	-	-
	कुल योग	**2,24,78,424**	**1,59,77,287**	**3,84,55,711**	**5,15,93,600**	**4,41,21,287**	**9,57,14,887**

31 मार्च 2021 को विशेषज्ञता प्रभार बकाये का समेकित विवरण

Name of RDs	कुल		2020-21		2019-20		2018-19		2017-18		2016-17		2015-16	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
एफआईपी	20,73,219	5,88,064	13,03,996	9,80,516	8,62,637	3,21,791	1,77,000	7,41,067	82,975	53,515	1,23,982	2,08,524	5,350	96,513
बेंगलोर	36,37,543	-	26,83,357	9,52,056	9,86,584	26,500	-	-	5,54,600	-	3,91,558	-	-	-
भुवनेश्वर	65,97,896	48,810	29,67,580	9,30,026	26,22,476	98,800	8,98,802	-	2,55,677	-	5,84,560	10,710	-	7,827
चंडीगढ़	1,51,326	70,711	-	58,589	58,589	9,150	1,684	38,484	1,59,022	8,290	-	24,167	-	-
गुवाहाटी	30,37,889	55,720	20,11,829	72,387	10,99,697	7,200	-	43,770	-	6,000	-	-	-	-
गांधीनगर	20,89,576	20,666	15,54,986	17,49,375	12,41,535	71,714	590	-	3,11,250	100	2,58,750	-	-	-
हैदराबाद	50,88,185	4,63,810	20,47,795	4,05,000	14,86,333	9,03,067	13,28,650	8,21,261	1,56,964	-	1,16,806	-	2,71,660	1,60,173
जयपुर	21,50,597	30,244	16,84,237	8,66,620	10,00,031	12,870	-	-	-	-	-	-	-	26,000
कानपुर	9,05,391	70,167	5,70,951	6,22,997	8,19,790	83,500	3,29,900	-	24,070	-	-	-	17,870	-
कोलकाता	53,08,273	2,19,667	21,70,063	17,29,586	33,66,615	9,74,765	10,62,378	2,00,900	6,51,596	35,253	632	-	5,31,358	-
मुंबई	60,41,340	86,241	39,38,067	9,76,055	18,40,655	2,63,340	12,36,501	3,861	-	69,612	-	-	-	7,109
पटना	22,55,961	-	22,65,561	1,15,428	1,15,428	-	-	-	-	-	-	9,600	-	-
कुल आरडी	**3,93,37,196**	**16,54,100**	**2,31,98,422**	**94,58,635**	**1,55,00,370**	**27,72,697**	**50,35,505**	**18,49,343**	**21,96,154**	**1,72,770**	**14,76,288**	**2,53,001**	**8,26,238**	**2,97,622**
मुख्यालय	2,52,72,333	5,05,414	1,43,94,841	35,03,179	55,92,870	6,05,763	4,03,982	39,316	12,20,464	3,79,270	3,96,402	69,859	-	16,968
कुल योग	**6,46,09,529**	**21,59,514**	**3,75,93,263**	**1,29,61,814**	**2,10,93,240**	**33,78,460**	**54,39,487**	**18,88,659**	**34,16,618**	**5,52,040**	**18,72,690**	**3,22,860**	**8,26,238**	**3,14,590**

Name of RDs	2014-15		2013-14		2012-13		2011-12		2010-11		2009-10		2008-09		2007-08		Upto 2006-07	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	x	क्रेडिट
एफआईपी	9,62,140	-	-	-	-	-	-	-	3,29,800	-	5,122	-	15,275	-	41,000	-	-	-
बेंगलोर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भुवनेश्वर	-	6,078	-	-	27,810	-	39,606	-	-	-	2,06,016	-	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुवाहाटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गांधीनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हैदराबाद	-	-	16,074	-	-	-	-	-	3,22,805	-	1,27,848	-	92,156	5,214	85,394	-	4,53,743	-
जयपुर	-	-	3,41,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	2,69,132	-	-	-	2,29,440	-	-	-	-	-	-	-
मुंबई	-	-	1,02,247	-	-	-	-	-	-	-	1,57,606	-	-	-	-	-	-	-
पटना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल आरडी	**9,62,140**	**6,078**	**4,59,896**	-	**27,810**	-	**3,08,738**	-	**6,52,605**	-	**7,26,032**	-	**1,07,431**	**5,214**	**1,26,394**	-	**4,53,743**	-
मुख्यालय	-	-	47,407	-	-	-	1,23,755	-	6,54,097	-	9,62,710	-	24,68,560	-	17,38,497	-	13,75,691	-
कुल योग	**9,62,140**	**6,078**	**5,07,303**	-	**27,810**	-	**4,32,493**	-	**13,06,702**	-	**16,88,742**	-	**25,75,991**	**5,214**	**18,64,891**	-	**18,29,434**	-

ANNUAL REPORT
2020-21

National Productivity Council

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

(Under Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

Table of Content

Chapter 1 - From the Desk of Director General		82
Chapter 2 - About NPC		83
Chapter 3 - Professional Services of NPC		89
Chapter 4 - An Insight into NPC activities during 2020-21		95
4.1	Annual Activities	95
4.2	Performance Highlights	95
4.3	New Initiatives	95
4.4	MoUs with various Organisations andInstitutionsduring FY 2020-21	102
4.5	Summary of some of the large assignments being carried out by NPC are as follows:	106
4.6	NPC 49th GC Meeting under the chairmanship of Hon'ble CIM	114
4.7	Select list of major research & consultancy projects undertaken during 2020-21	116
4.8	Select list of training programs conducted during FY 2020-21	119
Chapter 5 - Annual Accounts 2020-21		121

1

FROM DIRECTOR GENERAL'S DESK

NPC has been relentlessly developing and rendering leading edge consultancy and training services in the spheres of Industrial Engineering, Agri-Business, Economic Services, Quality Management, Human Resources Management, Information Technology, Technology Management, Energy Management, and Environment Management among others to the government and private sector organizations.

Our practices are consistently reviewed to ensure that we are following the most updated best practices, meeting all regulations, and addressing the future needs of the Industry.

We believe in learning system wherein, each individual is encouraged to participate wholeheartedly. We leave no stone unturned to offer multitudes of learning opportunities at pan India level.

We believe in empowering industry professionals in such a manner that they act as representatives of a meaningful and value-based society. Our team display boundless energy and intense commitment to disseminate knowledge and improve productivity. I am very fortunate to work with such dedicated, innovative officers & staff members. I find each day an adventure filled with new experiences, learning for all, and a chance to constantly widen our horizons.

NPC through its services has led to enhancement in the productivity, quality and efficiency of public services in various Union Ministries, State Governments, Central & State PSUs, Government establishments, Autonomous Bodies, Local Bodies and Private organizations etc.

NPC is all set to achieve new heights and boost the productivity of the nation.

I am looking forward to a new era for NPC to serve the nation through its state of the art services

(N.K.Chanji)
Director General

2

ABOUT NPC

NPC is a national level organization to promote productivity culture in India. Established by the Ministry of Industry, Government of India in 1958, it is an autonomous, non-profit organization with equal representation from employers' & workers' organizations and Government, apart from technical & professional institutions and other interests.

The Union Minister for Commerce and Industry is the President of Council, and the Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade is the Chairman of the Governing Body of the Council. Table-1 details about organisation structure of NPC.

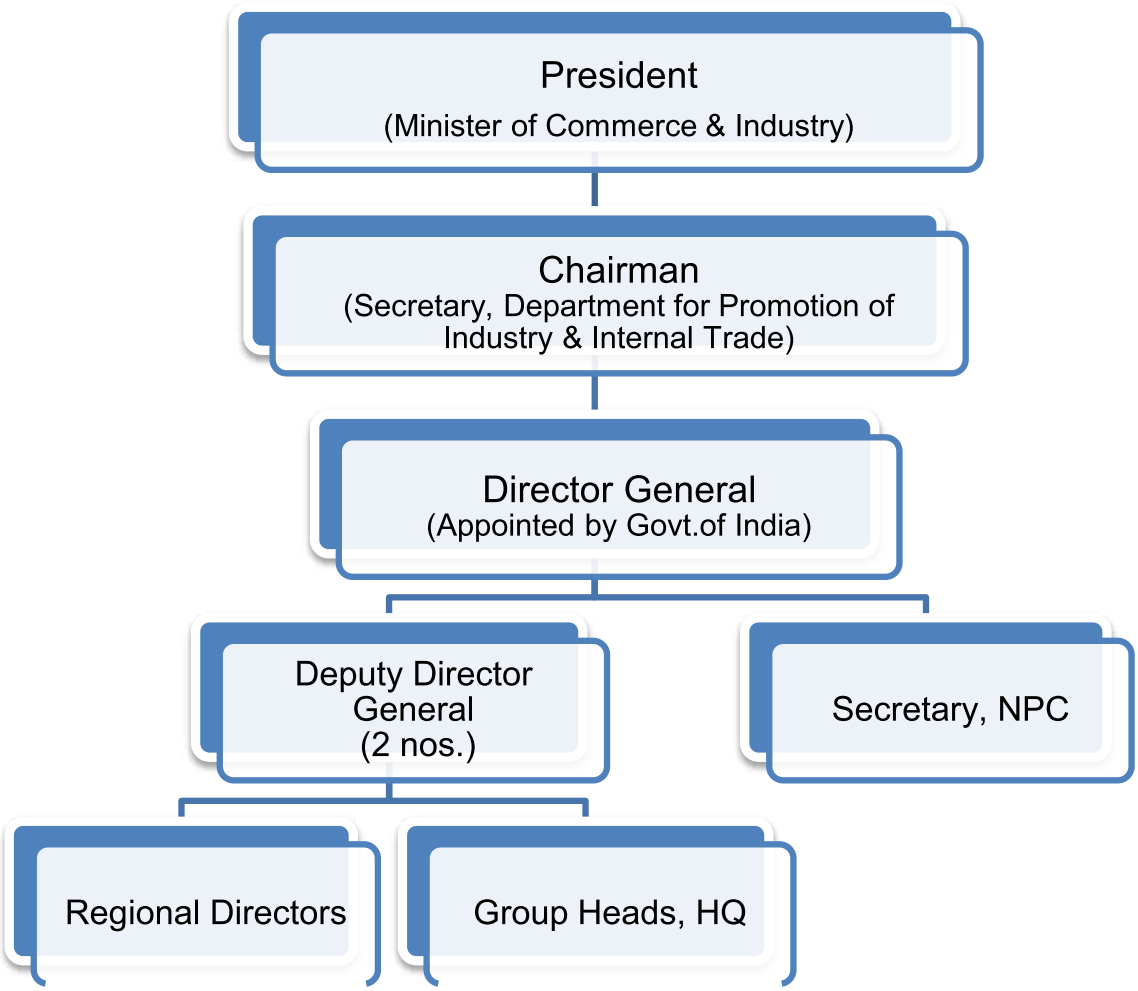

Table-1 Organisational Structure of NPC INDIA

The Director General is the Principal Executing Officer of the Council. NPC has strength of around 124 full time professional/ consultants, additionally services of outside specialists and faculty are also enlisted on project-based requirements. NPC has 12 Regional Offices located in major State Capitals/industrial centre with Headquarter in New Delhi and one Training Institute at Chennai, as shown in Map-1.

The Vision, Mission and Objectives of NPC are given below:

a. Vision:

To be the knowledge leader in productivity to provide state of the art services to the Indian economy to become globally competitive.

b. Mission:

Contribute to the sustainable, inclusive socio-economic development of the country by enhancing productivity.

c. Objectives:

i. To promote innovation - led productivity in a sustained manner in all spheres of national economy through holistic and inclusive approach by addressing the triple bottom line – Economic, Environmental and Social.

ii. To propagate productivity consciousness and culture amongst Govt., Business and Society.

iii. To demonstrate value addition through generation and application of advanced productivity tools and techniques for multiplier effect.

iv. To act as a total solution provider for Industry, Services, and Agriculture

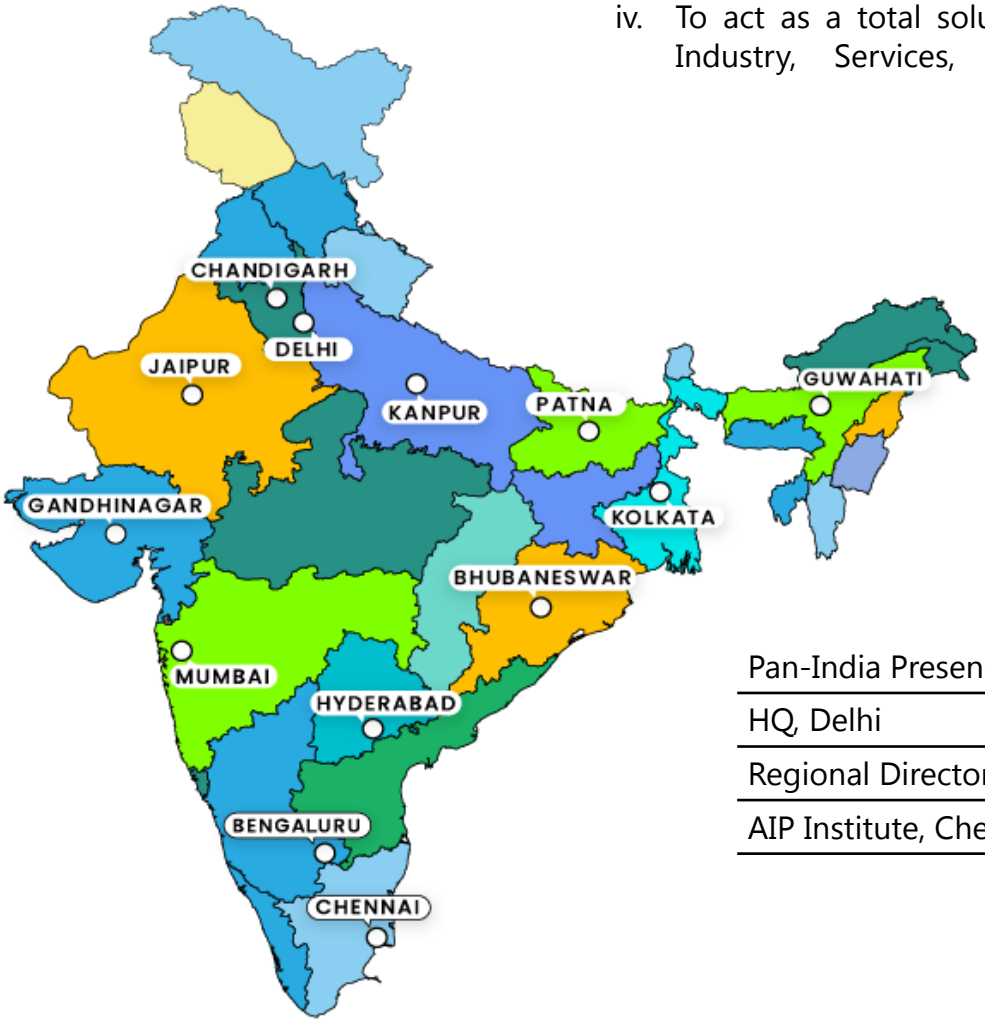

Pan-India Presence	
HQ, Delhi	1
Regional Directorates	12
AIP Institute, Chennai	1

sectors for augmenting productivity through Training, Consultancy and Research wherever needed through alliances and partnerships

v. Act as a catalyst in institution building and developing platforms for collaborative networking to strengthen the productivity movement.

vi. To act as a think tank by providing productivity related evidence-based policy support and advice in while tracking the emerging trends.

vii. To be an independent oversight entity for various national programmes, schemes and interventions.

viii. To recognize productivity champions through awards, affiliations, certifications, accreditations etc.

ix. To enhance international outreach for sharing the gains of productivity on mutual basis.

x. To be repository of productivity and competitiveness data across all sectors at the state and national level.

xi. To devise national productivity standards across all sectors and self-assessment web-based measurement tools for productivity diagnosis.

NPC and Asian Productivity Organisation (APO)

Government of India is the founder member of the Tokyo-based Asian Productivity Organisation (APO), an Inter-Governmental Body, since 1961. NPC represents Government of India in APO and is also the Nodal Agency in charge of organizing Indian participation in the training programmes, workshops and seminars offered by APO to Member Countries on different subjects related to productivity. NPC also hosts APO programmes in India every year for participants of Member Countries.

APO Member Countries

LEADERSHIP & GUIDANCE

President NPC

Shri Piyush Goyal

Ministry of Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles

Hon'ble Shri Piyush Goyal is the Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles, Government of India. Leader of House in Rajya Sabha.

He is a Member of the Upper House of the Parliament of India (Rajya Sabha), and the Leader of House in Rajya Sabha. He was earlier the Minister of Railways and Coal (2017-19). He has also held additional charge of Minister of Finance and Corporate Affairs twice in 2018 and 2019. Earlier he was Minister of State (Independent Charge) for Power, Coal, New & Renewable Energy (2014-2017), and Mines (2016-17). Sh. Goyal's tenure has seen Indian Railways achieve its best ever safety record in 2018-19. This was achieved through holistic measures such as elimination of Unmanned Level Crossings (UMLCs) from the broad-gauge network, production of safer coaches etc. Additionally, Sh. Goyal oversaw the launch of the first indigenous semi-high-speed train Vande Bharat Express between Delhi and Varanasi.

The Power, Coal and New & Renewable Energy ministries led transformational changes in India's power sector including the fast tracking of electrification of the nearly 18,000 unelectrified villages in some of the remotest and inaccessible parts of the country, the roll out of the most comprehensive power sector reform ever (UDAY), the success of the world's largest LED bulb distribution programme (UJALA) for energy efficiency, and massive proliferation of renewable energy through the world's largest renewable energy expansion programme. Other achievements include the elimination of coal shortages to improve the energy security of India and successful conduct of transparent e-auctions of coal blocks. He also received the 4th Annual Carnot Prize in 2018 recognising the pathbreaking transformations in India's energy sector.

Mr Goyal has had a brilliant academic record – all-India second rank holder Chartered Accountant and second rank holder in Law in Mumbai University. He was a well-known investment banker and has advised top corporates on management strategy and growth. He also served on the Board of India's largest commercial bank, the State Bank of India and Bank of Baroda. He was also nominated by the Government of India to the Task Force for Interlinking of Rivers in 2002.

LEADERSHIP & GUIDANCE

Shri Som Parkash, IAS (Retd.)

Minister of State for Commerce and Industry

Hon'ble Shri Som Parkash, an I.A.S. (Retd.) officer of 1972 batch. He had started his career as a research officer in the Punjab State Planning Board in 1972. Thereafter, he became an excise and taxation officer in the Punjab Excise Department.

Shri Som Parkash has served as the deputy commissioner of Faridkot, Hoshiarpur and Jalandhar and has also held posts like the Labour commissioner, Punjab Urban Planning and Development Authority (PUDA) Chief administrator, managing director of the Punjab Financial Corporation and Director of the Social Security Department.He has been also two-time Member Legislative Assembly (MLA) from the Phagwara Assembly constituency, (Punjab). Now he is Member of Parliament from Hoshiarpur Constituency.

LEADERSHIP & GUIDANCE

Chairman NPC

Sh Anurag Jain, IAS

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry

Sh Anurag Jain, IAS (MP 1989), is Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India and ex-officio Chairman of NPC.

Prior to taking over as Secretary, DPIIT, he served as Vice Chairman of Delhi Development Authority (DDA), Ministry of Housing & Urban affairs.

PROFESSIONAL SERVICES OF NPC

3

National Productivity Council (NPC) is a one stop solution for providing consultancy, guidance and mentorship for any kind of productivity related issues.

a. **Productivity Promotion:** The formation of National Productivity Council is being celebrated every year all over the country by commemorating 12th February as Productivity Day and the whole month as Productivity Month. The purpose is to draw the attention of all concerned, towards the concept and encourage implementation of productivity tools and techniques with contemporary relevant themes.This Productivity month, Sixty two training programmes were held throughout the country covering all states.

b. **Consultancy:** Professional consultancy services are provided by NPC for improvement of productivity, quality, profitability, and growth at entire organizational level. NPC is promoting and disseminating productivity skills through consultancy to the private and public corporate sectors, Central and State Governments, industry associations, their members, and other client groups. Over 200 consultancy projects are completed every year.

c. **Research:** NPC conducts activity-based research on project basis, to collect and analyze data and information on productivity-related topics in various sectors of the Indian economy. The topics include the existing challenges and emerging needs of sectors.

d. **Training & Capacity Building:** NPC's major training activities are primarily focused on developing human resources: people who can act as catalysts within the productivity movement of Indian economy. These training courses cover a wide range of productivity management issues in various areas including industry and service, agriculture, energy, environment, and local/regional development. NPC conducts more than 300 capacity building program enhancing the skills of more than 10,000 officials every year.NPC also organizes regional and sectoral conferences to impart knowledge on emerging issues and findings and discuss management strategy for the same. Conducting studies, research surveys, evaluations etc. on matters relating to productivity /quality improvement for enterprises, governments and others.

e. **Monitoring & Evaluation:** NPC has been involved in productivity assessments and directly and indirectly in Monitoring & Evaluation (M&E) studies and Performance Management of various Government funded projects and schemes, as well as private sector initiatives including industrial processes and across supply chains. NPC through its various divisions, namely Economic services, Industrial engineering / Process management, Information technology, Environment management, Agri-business management, Human Resource Management, Energy Management, International Services

etc., has undertaken a vast variety of projects across sectors and sub-sectors for government, international organizations and other agencies. NPC has the tools that are utilized for project management and planning and for undertaking econometric and statistical analysis of data that need to be obtained through suitable sampling technique, besides having GIS software pertaining to GIS based applications. NPC has further developed institutional linkages in order to offer cloud based IT platforms for real time Monitoring & Evaluation of projects, including Government schemes and infrastructure development projects.

f. **Recruitment:** NPC is conducting both Online & Offline examinations for various government and private organisations such as for Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM), Airport Authority of India, BSES, Paradip Port Trust etc. NPC specialises in providing end to end solution for recruitment such as application processing, providing payment gateway, conduct of offline and online examination, Question paper setting, evaluation, conduct of Interviews etc. NPC has been conducting examinations at PAN India level and also conduct trade related skill tests and typing tests.

   NPC aims to provide cost effective, fair and transparent examination procedure and to ensure the completion of the entire examination process in an unbiased, strictly confidential, hassle free manner.

g. **AIP Chennai:** Dr. Ambedkar Institute of Productivity (AIP) is a Training Institute having facilities of classrooms, hostels, and well equipped industrial energy units (acting as Centre of Excellence) at Chennai. CETEE, as mentioned above is a centre of excellence and is well equipped with various industrial equipments for energy efficiency.AIP is equipped with the various Industrial Energy Utility equipment designed to demonstrate practically various aspects of energy efficiency opportunities and Energy conservation technique as applicable in industries. Participants themselves can operate the equipments and change the operating parameters to learn the impact of efficient operation, change to energy saving mode, conduct testing for performance evaluation of systems through:

   - Pump Training Facility
   - Compressor Training Facility
   - Fan Training Facility
   - Boiler Training Facility
   - Steam Trap Training Facility
   - Open Burner Training Facility and
   - Combustion Furnace Training Facility

The Domain Specific Services of NPC

3.1 AGRI BUSINESS SERVICES:

Agri-Business group is engaged in Consultancy & Awareness generation for enhancing productivity in the spheres of Agriculture, Rural Development, Food Processing and allied sectors, both at micro and macro levels for National and International Organizations. The emphasis is to make the establishments and the projects cost-effective, target oriented, responsive to the dynamic socio-economic environment so as to achieve societal aspirations.

NPC's strength in the area of Agri Business lies in the following:

- Evaluation, Monitoring and Impact Assessment of Developmental Schemes

and Programs

- Policy Formulation and Program Management
- Formulation of Energy & Rural Development Plans
- Cooperative Augmentation
- Data Base Development
- Crop Productivity Improvement
- Agribusiness & Post Harvest Management
- Techno Economic Feasibility Studies
- Productivity Measurement & Enhancement in Food Processing, Dairy & Poultry Processing Industries
- Value chain management in food and agri-business
- Conduct of trainings, programs, seminars & conferences
- Conducting Food Safety Audits of FBOs and Warehouses
- Plan to establish one Centre of Excellence (COE) for Smart Agriculture in collaboration with Asian Productivity Organisation

3.2. ECONOMIC SERVICES

Economic Services Group of NPC specializes in macro and sub-macro level productivity and competitiveness studies with the objective of identifying relevant technological, economic and social factors and analysing the performance of the unit, sector and economy.

ES Group has undertaken a number of third party evaluation studies of various Central Government Ministries and Departments. These evaluation studies have substantially contributed towards modifying and making the schemes more useful.

Besides the evaluation studies, ES group has brought 4 special issues of Productivity Journal (Quarterly). NPC also provided partner institute services to IMD Switzerland in the preparation of World Competitiveness Yearbook 2021.

ES group also provided National expert services to Asian Productivity Organisation (APO) Japan in the forthcoming publication of APO Productivity Databook 2021.

The Division has a core team of specialists from Economics, Statistics, Management and Technology.

Core Competencies:

i. Sectoral / Industry / Product Profile Studies.

ii. Market Potential Assessment.

iii. Socio-economic Impact Studies.

iv. Policy Focus / Impact Studies.

v. Productivity Data-Base Development.

vi. Productivity & Competitiveness Studies.

vii. Monitoring & Evaluation of Government Schemes.

viii. Marketing and Product Promotion Studies.

3.3. ENERGY MANAGEMENT

Energy Management (EM) Division of NPC offers Consultancy / Training services since 1964. NPC has core strength of 30 EM professionals which include about 20 BEE certified Energy Auditors. The areas of expert services of this division are enlisted below:

i. Energy Management and Audit in all types of Industries, Commercial buildings & establishment, Power- generating plants, Distribution system.

ii. Demand side Management potential with focus on the industrial sector.

iii. To strengthen policy aspects and increase public awareness of Energy

Conservation issues through modular training programmes for Senior, Middle and Shop floor level executives.

iv. Technological Upgradation and Resource Conservation in SME's through cluster approach.

v. Providing Technical Expertise Services to APO member Countries in Energy Efficiency.

vi. Providing hands on training at Centre Excellence for Training in Energy Efficiency and Indo-Japan project on Regional Energy Efficiency Centre at Dr. Ambedkar Institute of Productivity, Chennai.

3.4. ENVIRONMENT MANAGEMENT

Environment Management Group focuses on waste minimization and pollution prevention in line with productivity improvement. The Environmental services include Monitoring & Analysis, Design of pollution control systems and Resource Conservation. With the assistance of Indo-German Bilateral co-operation initiated in 1985, the Group has developed expertise in diversified fields in Environment Management.

The Group has assisted more than 2500 enterprises including SMEs and large industries, Central/State Pollution Control Boards, Ministry of Environment & Forests at Central/State level and several International organizations. The Group is extending its expert services to Asian Productivity Organisation (APO) and SAARC Member countries. The services offered include:

i. Cleaner Production.
ii. Solid & Hazardous Waste Management.
iii. Biomedical Waste Management.
iv. CIS & Regional Environment Planning.
v. Water & Air Pollution Control.
vi. Green Productivity.
vii. Environmental Audit & Environment Management System.

3.5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The HRM Group focuses on continuous development and growth of Human Resources to enhance competitiveness of the organisations. Consultancy and Training Services are provided in the following areas:

i. Manpower Planning & Rationalisation.
ii. Organization Re-design Studies.
iii. HR Policy and Manual Review study.
iv. Competency / Skills Mapping / Assessment.
v. Training Needs Assessment & Analysis.
vi. Counselling & Re-training for Redeployment.
vii. Job/Employee/Customer Satisfaction Surveys.
viii. Impact Evaluation Studies.
ix. Performance Management System.
x. Complete Offline Recruitment Solutions.
xi. Job Description / Specification Review & Designing.
xii. Team Work & Team Management.
xiii. Transformational Leadership & Self-Motivation.
xiv. Communication & Presentation Skills.
xv. Problem Solving & Decision Making.
xvi. Stress & Time Management.
xvii. Attitudinal Change & Work Culture.
xviii. Knowledge Management.
xix. Effective Office Management.
xx. RTI Act Programmes.
xxi. Programmes on Office Procedures.

3.6. INFORMATION TECHNOLOGY

The key strength of the IT group is the excellent knowledge and skill-base coupled

with the strong system skills to meet the specific needs of the clients. The major business areas are consultancy and training.

NPC, IT Group has been offering services consultancy services for Strategic Policy & Planning matters for e-Governance/ICT Projects/Knowledge Management and web based application development as per sector specific as well as capacity building initiates for skill development of employees in IT-related areas for various organizations.

The consultancy services offered by IT group include:

i. Business Process Re-engineering and Compliance Audit of the ICT initiatives
ii. e-Governance initiatives assessment and promotion
iii. Knowledge Management implementation and assessment
iv. Project Management Services for ICT project implementation
v. Strategic Planning for Organizational ICT policy
vi. Web Based application development
vii. Promotion & Assessment of Innovations in ICT.

NPC, IT Group provides training services in various areas related to application of Information Technology in Management. Apart from general training programmes at regular intervals, NPC also offers customized training services in different areas. The training and capacity building services offered by IT group include:

i. Knowledge & Innovation Management
ii. ICT Strategic Planning
iii. Information Risk Management and ISMS
iv. IT applications for office Management in Govt Sector
v. Advance ICT Tools and Techniques
vi. Enhancing Organisational Performance through ICT

3.7. INDUSTRIAL ENGINEERING

Industrial Engineering Group focuses on Process Improvement initiatives for productivity enhancement. Through Consulting, Workshop & Training it creatively applies its skills and experience to those components that profoundly affect an organization's performance and provide a foundation for growth and success. The services to the organizations are being provided in the following areas:

i. Best Practices Benchmarking.
ii. Process and Productivity Improvement studies.
iii. Organizational restructuring and Manpower Rationalization.
iv. Lean Manufacturing.
v. Productivity linked incentive schemes.
vi. Six Sigma
vii. ISO 9001 : 2015& Quality Management.
viii. Assessment based on EFQM / MBNQA Business Excellence Framework.
ix. Project Management
x. Time & Motion Study

In developing the expertise, the Industrial Engineering Group of NPC has worked closely with the following institutions of prominence:

i. GTZ, Germany
ii. Fraunhofer's Information Centre Benchmarking, Germany
iii. Centre for Interfirm Comparison, U. K.
iv. PIMS, U.K.
v. American Productivity and Quality Centre, USA.
vi. Jarett Thor International, USA
vii. Asian Productivity Organisation, Tokyo.

viii. ILO.

ix. UNDP.

x. NITIE, Mumbai.

3.8. TECHNOLOGY MANAGEMENT

Technology Management Services aim at improving Physical Assets Productivity in all the sectors of economy. Latest hardware and software have been acquired to execute consultancy projects and provide demonstration during the training courses. Consultancy and Training services are offered in the following areas:

i. 5 S Implementation & Certification

ii. Technology Evaluation Studies

iii. Total Productive Maintenance

iv. Safety & Risk Assessment& Audits

v. Maintenance Systems

vi. Condition Monitoring

vii. Maintenance Audit

viii. Third Party Transparency Audit under RTI Act 2005

3.9 Inspection Division

National Productivity Council (NPC) has been granted **accreditation conforming to ISO 17020:2012 by National Accreditation Board for Certification Body** (NABCB) as Type A Inspection Body for undertaking inspection and audit work in the area of Food Safety Audit and Scientific Storage of Agricultural Products. This accreditation is valid for a period of three years starting from 14th October 2020 to 13th October 2023.

Inspection Division (ID) along with NPC Regional Directorates (RDs) and Empanelled Food safety Auditors undertake Independent Third Party Audits of Food Business Operators (FBOs) as per Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018 of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) for Dairy sector, Food Storage/Warehouse/ Cold Storage and Food Transportation and Inspections of Warehouses as per Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) Rules, 2017.

Besides Inspection and Audit activities, Inspection Division also conducts Training in the area of Food Safety, Food Standards, Food Laws, Food Quality, Food Processing, etc. NPC is also a Training Partner of **Food Safety Training and Certification (FoSTaC) for FSSAI.** One important online training programme conducted in March 2021 by the Inspection Division was on the topic **"Leadership Role in Food Safety Management System (FSMS)".** This online Training programme was attended by 78 participants representing Food and Dairy Industry. The training programme was conducted by Ms Jaya Khanduri, a National FoSTaC Trainer of FSSAI and Associate Professor, Institute of Good Manufacturing Practices India.

AN INSIGHT INTO MAJOR NPC ACTIVITIES DURING 2020-21

4

4.1 Annual Activities

Celebration of International Yoga Day 2020

All employees taking oath on Independence Day 2020.

All employees taking oath on National Unity Day 2020

4.2 Performance Highlights

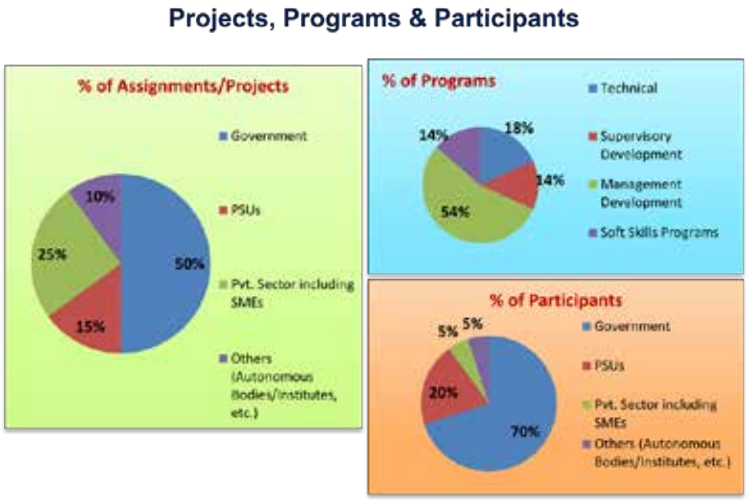

4.3 New Initiatives

I. Digital Services of IT Group

NPC has successfully transformed the training services from Physical mode to digital mode by introducing Online training through webinar mode and development of eLearning modules during the first COVID 19 pandemic period during 2020-21.

NPC's IT Group has successfully developed online training management portal integrating it with the CISCO WebEx platform for online registration and management of the complete online training activities by various Group's and Regional Offices of NPC.

NPC's IT Group also initiated the eLearning content development along with delivery through NPC's NeGD LMS platform.

As the successful outcome result, NPC was able to conduct more than 1200 online training and eLearning programs with total online registration of more than 24000 officials from State and Central Government departments, Public Sector, Financial and Academic Institutions as well as Private sector organizations, while generating online Revenue of Rs 70.25 lakhs approximately during the inception period of digital service delivery of the First COVID19 Pandemic period (FY 2020-21).

i. **e-Learning:** Since April 2019, NPC has taken a new initiative towards digital learning by introducing its own e-Learning platform. Apart from e-Learning courses, NPC also delivered online webinars & training programs with high content quality.

"Select list of e-Learning Module"

1. Balance Score Card
2. Enhancing Writing Skills
3. Office Procedures, Insight to Noting & Drafting
4. e-Learning Course on predictive analytics
5. e-Learning Course on Creating Wealth from Waste
6. e-Learning Course on Industrial Engineering Tools For Productivity Improvement
7. e-Learning Course for Documentation, implementation and certification of Integrated Management System as per ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 and ISO-450001:2018 standard
8. e-Learning Course on TQM implementation for business excellence

9. e-Learning module on Capacity building of Surveyors

ii. WEBINAR / ON-LINE PROGRAMMES

NPC conducted 9 online Training programme and 53 webinars on various topics. Picture showing online Training programme for M/S Power grid Corporation

"Select list of Webinars"

1 Work Study & Ergonomics

2 Digitalization in Manufacturing

3 Role of Analytics in Manufacturing Efficiency

4 Webinar on Developing High Performance Team (HPT)

5 हिंदी राजभाषा : मजबूरियां आवश्यकता

6 Webinar on HR Policy Manual

7 Coping with Failures

8 Industrial Design, Innovation and Entrepreneurship

9 Advanced Analytics Application in Manufacturing Supply Chain

10 "Important Amendments in GFR-2017": Regarding Procurement of Goods And Services

11 Digital & Analytics Interventions in Sales & Marketing

12 Challenges faced by HR (Pre/Post Covid pandemic and emerging challenges

13 Are you considering to launch your Vibrant Startup or MSME?

14 Building Teams in Virtual Times

15 Dispute resolution though Arbitration

16 COVID-19 Pandemic: An eye opening situation for Self Awareness

17 PPP implementation in India, issues/ challenges & way forward for next generation PPP projects

18 Enhancing Workplace Productivity: Psychological Perspective

II. WATER & ENERGY AUDIT

As per the Central Ground Water Authority (CGWA) under Ministry of Jal Shakti, Notification issued via S.O. 3289(E) dated 24th September 2020, it is stated that "Section 4.1 (iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m3/d shall be required to undertake annual water audit. NPC is one the organizations mandated by CGWA to conduct water audits. Based on the implementation of recommendations of water auditor, all such industries are required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means. NPC water audit studies cover sspecific water use and conservation, ccomplete water balance of the facility, water saving opportunities, broad approach for implementing the recommendations, process description and figures, and investment required.

NPC also conducts energy audit studies and has core strength of 30 energy management professionals which includes about 20 BEE certified Energy Auditors. NPC takes up energy management and audits in all types of industries, commercial buildings & establishment, power-generating plants and distribution System.

NPC conducted more than 100 water audit studies and about 20 energy audit studies.

"Select list of industries where water audit was carried out"

1. APM Industries Pvt. Ltd.Bhiwadi, Rajasthan

2. ITC Rajputana, Jaipur, Rajasthan

3. Metso India Pvt. Ltd., Alwar, Rajasthan
4. Dynamic Fine Paper Mill Pvt. Ltd., Kota, Rajasthan
5. Speciality Silica Pvt. Ltd., Alwar, Rajasthan
6. India Cement, Banswara, Rajasthan
7. Ultratech Cement, Chhitorgarh, Rajasthan
8. Ultratech Cement, Pindwara, Rajasthan
9. Mahesh Edible Oile, Kota, Rajasthan
10. Banswara Syntex, Banswara

III. NPC accredited as Inspection Body by NABCB

National Productivity Council (NPC) has been granted accreditation conforming to ISO 17020:2012 by National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) as Type A Inspection Body for undertaking inspection and audit work in the area of Food Safety Audit and Scientific Storage of Agricultural Products. This accreditation is valid for a period of three years starting from 14th October 2020 to 13th October 2023.

IV. In company Capacity Building programme

In company online Capacity Building Training programme conducted: Total 18 no of Incompany Capacity building programme were conducted during the year total 375 employees were trained on different topics of PSUs, Academic Institutions, State and Central Govt. organisation

1. 2 days Capacity Building Prog. On Preventive Vigilance for Goa Shipyard Limited (7 nos.)
2. 6 days Capacity Building Prog. On Enhancing Secretarial Effectiveness for SIDBI
3. 3 days Capacity building prog. On Enhancing Secretarial Effectiveness for Indian Oil Corporation
4. 2 days Capacity Building Programme on Right to Information Act, RTI for Bureau of Energy Efficiency
5. 6 days Capacity Building Prog. On Establishment Rule, Noting & Drafting, Reservation Rules in Service for V.O. Chidambarnar Port Trust (2 nos.)
6. 2 days Capacity Building Prog. On Tendering Process & Contract Management for Inland Waterways Authority of India
7. 3 days Capacity Building Prog. On Developing Managerial Capabilities of Non Teaching Staff for University Institute of Engineering & Technology, UIET, Haryana
8. 2 days Capacity Building Prog. On Electrical Safety aspects & IE rules for GAIL, Jaipur
9. 2 days Capacity Buidling prog. On Public Procurement for IFCI, New Delho
10. 2 days Capacity Building Prog. On Preventive Vigiolance & RTI for UPCL, Dehradun

V. Implementation of Energy Efficient Technologies at MPC

NPC in association with Ministry of MSME, Government of India, United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO), Energy Efficiency Services Limited and various stakeholders has undertaken implementation of energy efficient technologies at Medak Pharma Cluster under Promoting Market Transformation for Energy Efficiency in MSME Project. Five pharma units were visited namely, Pellets Pharma Private Limited, Vega Life Sciences, Sri Chaitanya Chlorides Private Limited, Chromo Laboratories, and Gensynth Laboratories.

NPC has identified four energy efficient technologies in Medak Pharma cluster viz: 1. Online Tube Cleaning of Condenser Tubes, 2. Mist Cooling Systems, 3. Side Stream Filtration System for Cooling Towers and 4. Replacement of Steam Vacuum pumps with Electric Dry Screw Vacuum pumps.

NPC Regional Directorate, Hyderabad conducted a half day workshop on "Implementation of Energy Efficient Technologies at Medak Pharma Cluster" on 5 October 2021 in association with Bulk Drug Manufacturers Association (BDMA), Hyderabad to disseminate knowledge in energy efficient technologies in MSME pharma industry. More than 30 delegates from various pharma industries and technology suppliers attended the half day workshop. Various MoUs were also signed during the workshop.

MoA signing between EESL and Virupaksha Organics Private Limited for implementing energy efficient technologies.

VI. e-Connect

NPC has been publishing its own electronic news-letter (monthly) titled as eConnect. NPC shares eConnect with its stakeholders, clients, other government institutions, participants of its webinars in order to keep them updated about NPC activities and to develop continuous connection with them. One of the important features of eConnect is to invite distinguished and senior officials/executives to present their valuable views/feedback on the first page of the eConnect with regard to productivity issues and challenges. All interested readers can access eConnect at **https://www.npcindia.gov.in/NPC/User/econnect.**

VII. BHARAT 4.0-Digital Readiness Assessment Tool

The Mobile Application for Bharat 4.0-Digital Readiness Tool has been developed by HRM & CoE Group, NPC wherein Readiness Assessment of Industry(s)/ SME(s) in the domain of Industry 4.0 shall be undertaken. The BHARAT 4.0 Mobile App shall be utilized for Maturity assessment in Manufacturing units to gauge the as-is situation of the organizations' processes. This will form the base for detailed intervention w.r.t undertaking Implementation projects. The Tool can be used by the Industry(s)/ SME(s) to assess the current level of digital readiness of the organisation in

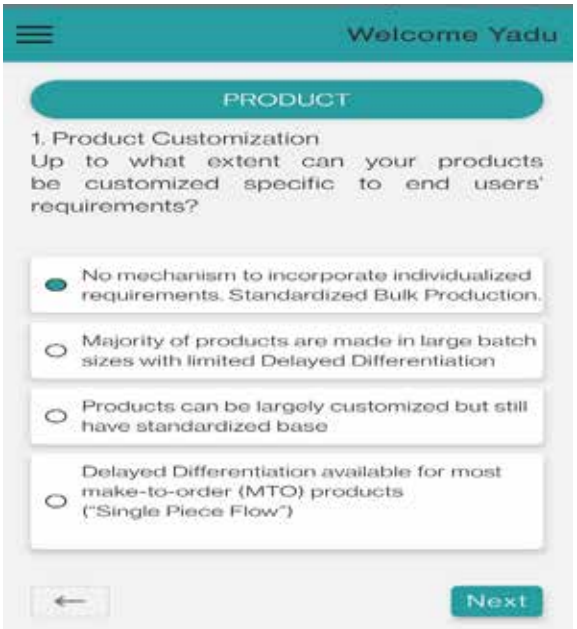

terms of five maturity levels expressed in terms of SMART (Starter, Managed, Adaptive, Realizer, Top-Notch).

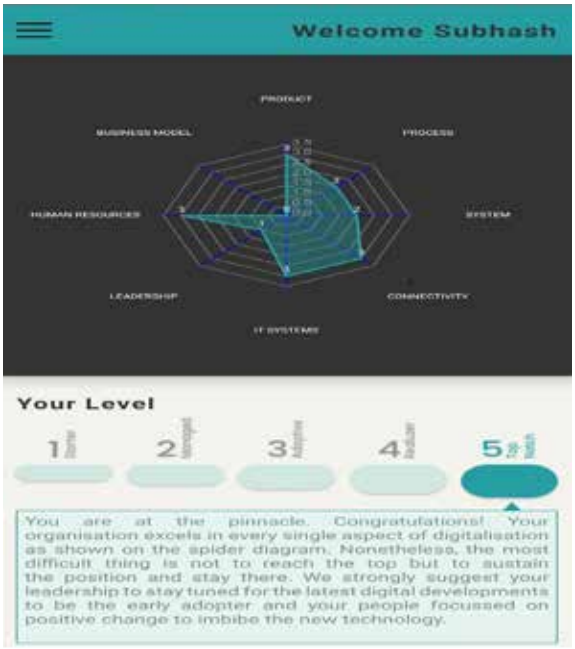

VIII. Experience Zone on Industry 4.0

- HRM & CoE Group, NPC has established the state of the art Experience Zone on Industry 4.0 at its HQ at New Delhi in the form of Studio with digital display of storyboard, use cases etc. on the walls.
- Operational prototypes of IoT/AI/AR-VR/Simulation have also been installed at the Experience Zone. These include Robotic Arm, Ground Clearance Robot, Surveillance Robot, 3D printer, AR based warehouse display unit, Industry Smart Energy Monitor with IoT, AI based Robot, ECG/ Pulse Monitor system with IoT, AI based vehicle detection, Image to text etc.
- The Experience Zone aims to provide a touch and feel environment and to conduct trainings w.r.t key concepts of Industry 4.0 and accompanying technology domains to visitors from Industry / Academia / Universities/ Research Institutions etc. and to provide a platform for imparting technological know-how/ awareness and insights.

IX. BHARAT 4.0-Digital Readiness Assessment Tool (Coffee Table Version)

Bharat 4.0-Digital Readiness Assessment Tool (Coffee Table Version) has been conceptualized and developed by HRM & CoE Group, NPC. The Tool can be used by the Industry(s)/SME(s) to assess the current level of digital readiness of the organisation in terms of five maturity levels expressed in terms of

SMART(Starter, Managed, Adaptive, Realizer, Top-Notch). It also provides an overall assessment indicating the requirements/strategies to be adopted to transform to next level. The Tool is applicable to all companies, regardless of industry, size, profile, and I4.0 Maturity. This tool uses a Digital Questionnaire Form which will be filled by interested user. After submitting the form the User will receive his B4.0-Evaluation Report instantly on his/her email.

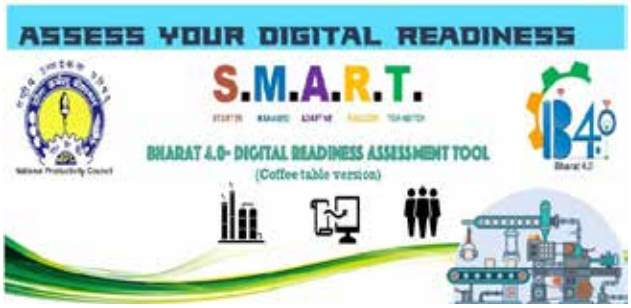

X. SAKSHAM 4.0-Virtual Internship Program on Industry 4.0

HRM & CoE Group, NPC has trained more than 2500 plus interns from various universities/colleges pan India through NPC's Learning Management System (LMS) platform. The LMS platform offers learning videos on key Technical Topics covering following domains:

1 Advanced Manufacturing Systems and its application

2 Achieving Manufacturing Excellence viz. Lean/MFCA etc.

3 Entrepreneurship & Innovation

4 Industrial Processes & Industry 4.0

5 Adapting New Business Models in Post COVID 19 World

4.4 MoUs with various Organisations and Institutionsduring FY 2020-21

In order to spread the culture of productivity at pan India level, NPC collaborated with other organisations/ educational institutions. NPC has signed MoUs with various Organizations to improve its outreach in the field of Consultancy, Training and Research. The details of MoUs signed are listed below:

1. Teerthanker Mahaveer University, U.P. (19.06.2020) –

HRM & CoE Group, NPC has signed MoU with Teerthanker Mahaveer University to perform collaborative programmes to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. The aim is also to create Govt-Academia-Industry Linkage for overall productivity improvement in all sectors.

To perform collaborative programmes to fulfill objectives of Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (CoE:IT for I4.0) in order to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. Apart of awareness program, both organizations will work towards the Academia-Industry Linkage.

It also aims to arrive at an understanding between both the parties to jointly organize and promote certain Training programs / consulting assignments across India on a regular basis.

2. Sharda University (24.06.2020) –

HRM & CoE Group, NPC has signed MoU with Sharda university to perform collaborative programmes to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. The aim is also to create Govt-Academia-Industry Linkage for overall productivity improvement in all sectors.

To perform collaborative programmes to fulfill objectives of Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (CoE:IT for I4.0) in order to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. Apart of awareness program, both organizations will work towards the Academia-Industry Linkage.

It also aims to arrive at an understanding between both the parties to jointly organize and promote certain Training programs / consulting assignments across India on a regular basis.

3. India SME Forum (ISF)(7/1/2020) –

To collaborate and cooperate in the areas of enterpreneurship development and productivity enhancement among MSMEs, startups and aspiring entrepreneurs.

4. Graphic Era Deemed to be University (9/23/2020) –

To identify mutual collaboration opportunities bringing togetherthe strength of both, building skills and education aimed at enhancement of productivity and self & wage - employment opportunities.

5. Indian Rubber Manufacturers Research Association(9/29/2020) –

To co-operate each other for the mutual benefit of organizations through interactions towards restructuring the organizational functioning and process improvement.

6. CSIR Oceangraphy(Jan 2020) –

The aim of this MoU is premarily to develop a long term joint working partnership in the area of the enviroment management, climate resilience in coastal zones and communities, oceanographic data analytics, enviromrntal impact studies and modelling to predict enviromental impact identifiying remedial and mitigation measures and contributing to policy research.

7. All India Council for Robotics & Automation (AICRA)(03.11.2020) –

To perform collaborative programmes to fulfill objectives of Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (CoE:IT for I4.0) in order to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. Apart of awareness program, both organizations will work towards the Academia-Industry Linkage.

It also aims to arrive at an understanding between both the parties to jointly organize and promote certain Training programs/ consulting assignments across India on a regular basis.

8. **Assam Startup - The Nest (09.11.2020) –**

   To perform caollaborative programmes to fulfillcommom objectives of quality upgradation / enhancement ofcompetencies of students / working professional/entrepreneurs / SMEs.

9. **Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) (14.12.2020) –**

   The Aim of this MoU is primarily to agree to work together in a collaborative manner in relation to the R&D programme of CSIR related to the Interated Energy Audit and Management Activity, under the Energy Theme. Main objevtive of this MoU is to assist CSIR in Capicity building and jointly develop and executive various energy efficiency related projects internally for the CSIR as wll as other activities in this domain.

10. **Indian Institute of Plantation Management (16.12.2020) –**

    To provide Value-added management inputs to a wide clientele (e.g., students, professional, business owners, commodity boards and Govt.) in the agribusiness and plantation sector.

11. **National Council for Cement and Building Materials(NCCBM) (15.01.2021) –**

    Both the institutions i.e. NCCBM and NPC shall facilitate sharing of their Infrastructure / laboratories facilities, library, and a materials including proprietary software of the institutions and other in house development components with each other as per mutually agreed terms and condition. The aforesaid sharing shall be subject to terms of the third party contract, if any, and shall be for the research for purpose only.

12. **Hindustan College of Science and Technology (20.01.2021) –**

    To perform collaborative programmes to fulfil objectives of Centre of Excellence on IT for Industry 4.0 (CoE: IT for I4.0) in order to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. Apart of awareness program, both organizations will work towards the Academia-Industry Linkage.

    It also aims to arrive at an understanding between both the parties to jointly organize and promote certain Training programs/consulting assignments across India on a regular basis.

13. **Mangalam College of Engineering (20.01.2021) –**

    To perform collaborative programmes to fulfil objectives of Centre of Excellence on IT for Industry 4.0 (CoE: IT for I4.0) in order to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India. Apart of awareness program, both organizations will work towards the Academia-Industry Linkage.

    It also aims to arrive at an understanding between both the parties to jointly organize and promote certain Training programs/consulting assignments across India on a regular basis.

14. **Market Xcel Data Matrix Pvt. Ltd. (05.02.2021) –**

    The aim of this MoU is primarily to Empane "Market Xcel Data Matrix Pvt. Ltd" Project Management Consultant (PMC) in the service of National Productivity Council (NPC) for the period of 36 months. The PMC will work closely with NPCto help improve Indias's ranking on the WJP rule of Law index.

15. **PTC India Pvt. Ltd. (15.03.2021) –**

    NPC/PTC will be jointly be responsible for overall project management & coordination, resource management, deliverable and Liaison with Industries,

Utilities and all other concerned stakeholder, However for each of the project or activity being undertaken by NPC/PTC, a detailed scope of work including financial implementation and other terms and condition for executing the project will be work out jointly.

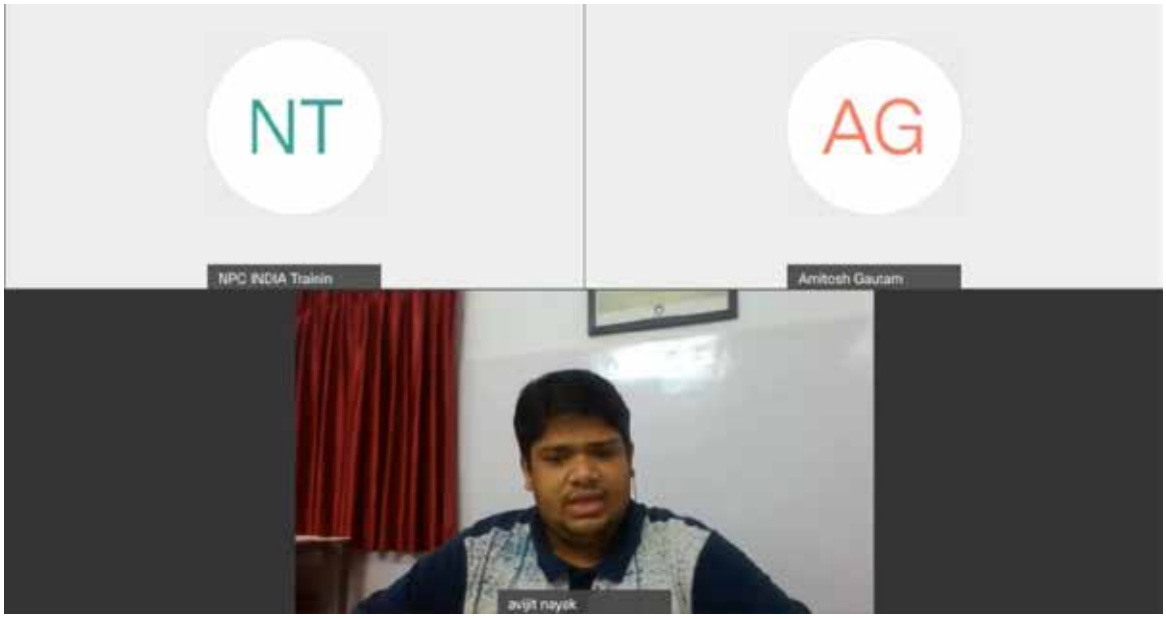

16 NPC, IKON Group sign MoU in presence of Andhra Pradesh Minister of Tourism and Sports

An MoU was signed on 02nd of October, 2021, on the occasion of Gandhi Jayanti and Gandhi Memorial Awards at a mega event at Novotel, Vishakhapatnam between National Productivity Council, Hyderabad, DPIIT, Ministry of Commerce and industry, Government of India and International Knowledge and Opportunities Network (IKON) group for carrying out the projects and training together in the areas of productivity and the MoU was exchanged in the presence of Shri M. Srinivas Rao, Hon. Minister for Tourism and Sports for Andhra Pradesh.

17. MoU signing with Schneider Electric India Ltd.

HRM & CoE Group, NPC has signed MoU with Schneider Electric India Ltd. to create awareness & implementation of Industry 4.0 among manufacturing industries in India with special focus on Energy Efficiency.

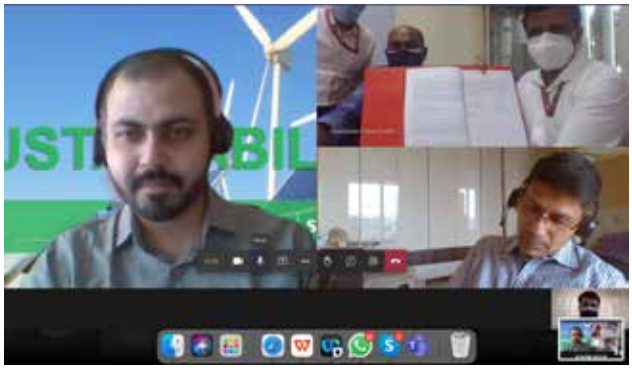

4.5 Summary of some of the large assignments being carried out by NPC are as follows:

1. Recruitment for WBPCB:

The HRM Group conducted Computer Based Test for 55,597 nos. candidates at twelve locations in West Bengal for West Bengal Pollution Control Board. All the test centres were equipped with latest computers, CCTV etc. The test was conducted successfully at all the locations. The value of the assignment was 3.44 crores plus GST.

2. Capacity Building of State/UTs for data on domestic & Foreign Tourist Visits/Visitors, Ministry of Tourism, Govt. of India

Ministry of Tourism has engaged National Productivity Council as a project Management Unit (PMU) for building the capacity of the State/UT tourism departments for estimation of the Domestic & foreign Tourist visitors and visits in their State/UT. For estimation a Standard methodology in line with the UNWTO is being developed.

The data would provide detailed insights on domestic and foreign tourist footfalls on various tourist attractions, State of residence/country wise visitors profile, their age, gender, expenditure made, accommodation preferred etc.

The data might be utilised by Ministry in planning various policies &Infrastructure upgradation at Tourism attractions, showcasing the potential of Indian tourism for attracting Investors and planning Ministry of Tourism's Overseas Marketing campaigns. The data would also be useful for Industry units for extracting market insights and come up with innovative products and packages.

For capturing the data surveys will be

conducted in each district of the country. The data will be captured through mobile app specifically developed for this purpose. Data processing will be automated and output tables/ parameters will be plotted on the Integrated Dashboard.

The dashboard would help in dissemination of data on various Tourism Development Indicators such as district wise Tourist visits, room occupancy, employment, foreign exchange earnings, International Tourist Arrivals, Indian National departures. This is in line with the National Data sharing & Accessibility Policy (NDSAP) of Department of Science & Technology. The dashboard would provide a mechanism to State Tourism departments to monitor the Tourism indicators of their states and plan their policies and initiatives in right direction.

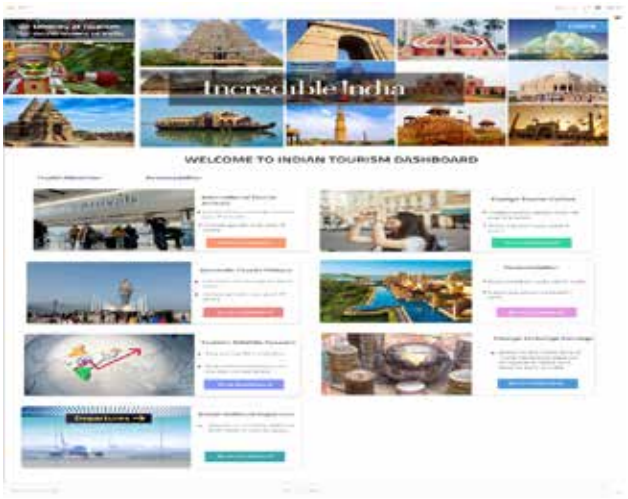

3. Manpower Optimization Study for TANGEDCO

Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited (TANGEDCO) has entrusted Manpower Optimization Study of value Rs. 287.60 Lakhs to AIP Chennai. The Study is being conducted by Industrial Engineering Consultant of NPC at Channai.

4. Organisation Study and Cadre Review for DGQA

NPC has conducted 'Organisation Study and Cadre Review' for Directorate General of Quality Assurance (DGQA), Department of Defence Production (DDP), Ministry of Defence (MoD) valued at around 2 Crores.

The objective of the study is to examine whether the Quality Assurance (QA) policies, procedure and practices in vogue are in tune with the present day needs and whether DGQA is suitably positioned, organised, equipped and staffed to discharge its responsibilities effectively.

5. Study for Central Warehousing Corporation:

Central Warehousing Corporation has entrusted two prestigious assignment namely "Organizational Study of Central Warehousing Corporation" of assignment value of Rs. 89.68 Lakhs and "Review & Re-designing of Productivity Linked Incentive scheme (PLIS) for Group C & D employees" for assignment value of Rs. 33.28 Lakhs.

The Organization Study Assignment encompassed the coverage of study for undertaking a comprehensive

organizational Analysis including Manpower, Organizational Structure, Cadre Review & recommendations, review of Personnel Policies, Competency Mapping and Learning & Development of Central Warehousing Corporation and the report is currently under review by CWC Management.

The PLIS study covered sample site visits to the Warehouses of Foodgrains, EXIM & Bonded Warehouses, etc. and the Report has been well appreciated for implementation by the Management of CWC.

Few Site Visit Photos are placed as under:

Few Site Visit Photos are placed as under:

6. Strengthening of Post Environment Clearance Monitoring & Compliance Framework

All the projects having environmental clearance since EIA Notification 1994 are required to submit six-monthly compliance reports. The EIA notification 2006 includes 39 categories of industries/ projects that require post Environment Clearance monitoring. There are over 8,500 Category A project proponents (PPs) and over 28,000 Category B PPs that have obtained EC requiring Post EC Monitoring.

Keeping in view large number of PPs and NGT orders to strengthen the monitoring & compliance and also assist PPs to improve environmental management and performance, MOEF&CC has engaged NPC to develop a comprehensive 3 Tier framework for post EC monitoring of the projects which comprises of a scheme of Certified Environmental Auditors (CEAs) and Certified Environment Mangers (CEMs) to serve as technically proficient extended arm of the ministry and also assist PPs and all other industries to review, manage and improve their

environment management plan. NPC has partnered with GIZ, NEERI, QCI, other stake holders & subject experts. These certified professionals will also provide knowledge and technical solutions to environmental problems on case to case basis to industries/PPs. This pool of highly proficient technically sound diligent auditors will be identified, selected, oriented/trained and certified through suitable mechanisms.

7. Third Party Evaluation of schemes supported by Department of Consumer Affairs

The Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution has implemented several Schemes including Strengthening of Consumer Fora at State and District level, State Consumer Helpline, CONFONET, Consumer Awareness, Strengthening of National Test Houses (NTHs), Bureau of Indian Standards (BIS) Schemes viz Standardization & Quality Control and Setting up of Gold Hallmarking and Assaying Centres, Strengthening Legal Metrology Infrastructure of States/ UTs and Strengthening of Regional Reference Standards Laboratories (RRSLs) & Indian Institute of Legal Metrology (IILM), Ranchi, Time Dissemination Scheme and Price Monitoring Cells (PMCs). With a view to assess the impact of the above Schemes, the Department of Consumer Affairs has entrusted a study to the National Productivity Council (NPC), New Delhi with the major terms of reference such as proper utilization of funds received, physical achievement vis-à-vis financial achievement, adherence to the timelines and sufficacy of the norms.

District Consumer Forum, North Sikkim

Hallmarking Centre in Dehradun

National test House, Ghaziabad

State Consumer Helpline, Kolkata

Under the study, 12 State Commissions, 36 District Consumer Forums, 48 CONFONETs, 12 State Consumer Helpline, 44 Gold Hallmarking & Assaying Centres, 12 Secondary Standards Labs, 24 Working Standards Labs, 5 RRSLs, IILM Ranchi, 5 Time Dissemination Centres, 6 NTHs and 22 PMCs were covered under the study. The report was submitted to Department and has been accepted along with recommendations

8. Baseline Study for project "Introduction of Pulses Technology in Rice Fallow to improve livelihood and Nutritional Security of the Farmers of Tribal People of Vidarbha region"

A collaborative Pilot Project is being implemented by Government of Maharashtra and ICARDA on "Introduction of Pulses Technology in Rice Fallow to improve livelihood and Nutritional Security of the Farmers of Tribal People of Vidarbha region" for harnessing potential of pulses & spineless cactus for improved livelihoods and nutritional security of farmers of tribal populated Nagpur & Amravati Districts. NPC had conducted Baseline Study with objective to provide an information base to monitor and assess the progress and effectiveness due to implementation of the project after the project activities are completed.

The NPC conducted base line survey in two districts of Vidarbha region viz. Nagpur and Amravati. In Nagpur district, 6 Blocks of i.e. Ramtek, Katol, Umred, Savner, Narkhed and Pashivani and in Amravati 5 Blocks ie Dharni, Chikaldara, Varud, Achalpur and Morsi are covered for the baseline survey. In all 617 farmers are covered in both the districts. The draft report of the study has been submitted to PFC for approval.

9. Preparation of Comprehensive District Agriculture Plan

National Productivity Council had been entrusted with preparation of Comprehensive District Agriculture Plan (CDAP) for 40 districts of Agriculture aims at moving towards projecting the requirements for development of agriculture and allied sectors of the district. These plans present the vision for agriculture and allied sectors within the overall development perspective of the district. CDAP is meant for developing various sub schemes/ projects under RKVY – RAFTAAR. The projects for the C-DAP can be selected from various sectors such as crop development, horticulture, agricultural mechanization, natural resource management, marketing & post-harvest management, animal husbandry, dairy development, fisheries, sericulture, extension etc to be funded under RKVY and shall not be the usual aggregation of existing schemes.

Glimpse of DAPU Meeting in Chitrakoot

Glimpse of DAPU Meeting in Jaunpur

BAPU Meeting at Manikpur Block

VAPU Meeting at Manikpur Block

BAPU Meeting at Badalapur Block

VAPU Meeting at Village: Aara Block: Karanjakala

10. Evaluation of Schemes of Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India

This evaluation study was conducted with an objective to evaluate the extent to which the 7 different schemes of Department of Health Research (DHR) have been implemented and adopted on the field level along with identifying the constraints for achieving the physical and financial targets of the schemes. These schemes were launched with aim to bring modern health technologies to the people through research and innovations related to diagnosis, treatment methods and vaccines for prevention; to translate them into products and processes and, in synergy with concerned organizations, introduce these innovations into public health system.

Holistic approach was adopted to assess the schemes performance based on various parameters along with representative coverage of all the varieties of the schemes and its distribution. Study covered field level data and information collection from various Sample Institutions distributed in 12 different States/UTs that represent all the zone of the country.

Study indicated that the DHR schemes are fulfilling the need of the hour of research and development in the field of Health Sector. To achieve the Output and Outcome of the schemes, it was suggested to emphasis more in the area of research work, development of Real-time monitoring system of establishment work as well as day to day activities of the labs and strengthening of establishment of Regional level and State level labs.

11. Assessment of Performance of Schemes of Powerloom Sector

IE group has successfully completed the evaluation of performance of Powerloom

sector schemes implemented by Commissioner of Textiles, Ministry of Textiles, Govt. of India. The study includes evaluation of 13 nos. of schemes i.e., In-situ upgradation of plain Powerloom, Group Work shed Scheme (GWS), Common Facility Centre (CFC), Grant-in-Aid / Modernization of Powerloom Service Centre (GIA to PSC) and many more. NPC has interacted with more than 6000 numbers of Powerloom beneficiaries and also with other stakeholders of the sector across 16 states and collected information, feedback, suggestions regarding the implementation and impact of those schemes. The analysis is done along with recommendation, suggestions are provided for improving the service delivery, effectiveness of schemes. The study findings provided inputs for the policy makers to amend, implement the suggestions in the existing provisions of the scheme.

12. Upgradation of Existing Government ITIs into Model ITIs

Industrial Engineering (IE) Group has successfully completed evaluation of one of the flagship schemes i.e., "Upgradation of Existing Government ITIs into Model ITIs" sponsored by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Govt. of India. The objective of the study includes performance analysis of the scheme; assess relevance, efficiency, effectiveness, equity & sustainability of the scheme. To ascertain the objectives outlined, interaction was held with various stakeholders/ beneficiaries and data/ information was sought from Trainees (197 nos.), Trainers (87 nos.), Implementing institutes i.e., the Model ITIs (11nos.), State Governments, Nodal Ministry and the Industry partner i.e., Institute Management Committee (IMC) of the ITI. Based on analysis of the primary/ secondary data and information received from the stakeholders; recommendations and suggestions were made to improve the effectiveness in delivery of the scheme.

13. SINGRAULI HR CONFERENCE - SHRAM 2021

Singrauli HR Conference, SHRAM-2021, was successfully organized on 17th-18th November, 2021. The conference was the first of its kind in the Energy Capital of India. The HR heads of organizations like Hindalco, Reliance Power, Essar, NTPC , GAIL, SECL etc. Participated in this mega event with 650 participants. The theme of the conference was Industrial revolution 4.0: Competing through People Matrix.

External Safety Audit at NTPC-Khargone

One Day session on Energy Audit & Management at NALCO Regional Office, Kolkata

The renowned speakers Shri Shiv Khera, Professor, Author, Speaker, Prof. (Dr.) T.V. Rao, Professor, Author, Speaker Management Consultant, Dr. Santosh Bhave, Director (P&IR), Bharat Forge Ltd. Dr. Pramod Sadarjoshi, Managing Partner, Cornerstone International Group, Shri Sanjeeb Lahiri, CHRO, GRP Ltd., Dr. Deepak Deshpande Vice President & Head HR, Tata Business Excellence Group, Shri Niladri Bhattacharjee Partner, KPMG & Dr. B. Hemant Kumar Rao, Regional Director, National Productivity Council.

14. Workshop on theme "Engaging the workforce for the future"

Dr. B. Hemant Kumar Rao, Regional Director, National Productivity Council, enlightened the listeners on the sub-theme 'Engaging the Workforce for the Future - Cultivating a Coaching Culture'. He defined in very simple terms that a coach is a facilitator, how goals should be set and what the role of a coach is. He also elaborated on the point that alignment of vision and mission with coaching culture is extremely necessary. He suggested the GROW model for designing the coaching process which stands for Goals, Reality, options/ obstacles and Wrap up/will.

15. 'Conducting Study on Operation & Maintenance Processes' of Kochi Metro Rail Limited,

Commenced an Assignment titled 'Conducting Study on Operation & Maintenance Processes' of Kochi Metro Rail Limited, located at Kochi, valued at Rs.44 Lakhs + GST. By the end of 2020-21 RD Bangalore had submitted the draft reports for this assignment.

Conducting Study on Operation & Maintenance Processes of Kochi Metro Rail Limited – Field Study Inspection of Duct

4.6 NPC 49th GC Meeting under the chairmanship of Hon'ble CIM

NPC 49th Governing Council meeting held under the chairmanship of Hon'ble Minister of Commerce & Industry Sh. Piyush Goyal on 27th June 2020 through video conferencing. It was attended by 180 participants comprising of Government's Secretaries and Joint Secretaries, captains of Industry Associations, Trade Unions, Heads of SBI, UNILEVER, BCG, FICCI, CII, NASSCOM, FISME, MAHINDRA & MAHINDRA, KPMG HMS, CITU, BMS, INTUC, AITUC and LPCs, etc.

4.7 Select list of major research & consultancy projects undertaken during 2020-21

NPC has been providing value added consultancies to public sector and private sector. The organisation has been able to enhance its productivity with such studies substantially.

1.	State level project on E-Waste Inventorization in Tamilnadu for all districts
2.	21st NCE – BEE
3.	Manpower Optimization Study for TANGEDCO
4.	Technical Policy for Shifting to Renewable Energy for ITEC
5.	Study on Operation & Maintenance Processes of Kochi Metro Rail Limited, located at Kochi
6.	Impact Analysis Study of REC-CSR sponsored Projects in Residential Schools under Karnataka Residential Education Institutions Society (KREIS)
7.	Impact Assessment of the Project –'Establishment of Virtual Class Room to Improve the Quality of Education in 10 Talukas of Karnataka' for Karnataka State Council For Science & Technology (KSCST)
8.	Detailed Energy Audit at Integrated Food Park Limited, Tumkur District
9.	Water Audit Study at Gemini Graphics Private Limited, Bidar
10.	Detailed Energy Audit of Iron Ore, Chromite Ore & Bauxite Ore Mines of Odisha Mining Corporation , Bhubaneshwar
11.	Water Balance study for NTPC – SAIL , Bhilai , Chattisgarh
12.	Implementation of Integrated Management System at Odisha Mining Corporation , Bhubaneshwar
13.	Support services for Sustenance of Integrated Management System at Odisha Mining Corporation , Bhubaneshwar
14.	Implementation of SA 8000 System at Odisha Mining Corporation , Bhubaneshwar
15.	Support services for Sustenance of SA 8000 System at Odisha Mining Corporation , Bhubaneshwar
16.	Third party evaluation study of LESS Scheme of Labour Bureau, Chandigarh
17.	Time study in 8 shops of DMW, Patiala for about 1000 operations in year 2020-21 completed to review and design of incentive scheme
18.	Water Audit of Panipat Cement works
19.	Third Party Evaluation of the Scheme of 'Capacity Building for Service Providers' of the Ministry of Tourism, Govt. of India
20.	Third Party Evaluation of the Scheme on Fast Track Special Courts (FTSCs) for Expeditious Disposal of Cases of Rape and Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act
21.	Evaluation study of upgradation of existing Government ITIs into model ITIs" by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Govt. of India
22.	Evaluation Study of "National Apprenticeship Promotional Scheme (NAPS), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSD), Govt. of India
23.	Evaluation Study on "Functioning of National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) in the state of H.P and Haryana

24.	Impact Evaluation Study of the Aids and Appliances provided by ALIMCO
25.	Inspection of Three Security Printing presses two at Sonipat, and one at Jalandhar
26.	Productivity Improvement Study in Bagging & Logistics areas for Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.
27.	Training Needs Assessment for Bharuch Eco Aqua Infrastructure Ltd, Ankleshwar and its subsidiary units spread across the country
28.	Manpower Optimization & Organization Restructuring Study for Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.
29.	APO Project: RD Gandhinagar undertook APO's 5 days Certified Productivity Practitioners' Course which was attended by 41 participants from 16 APO Member countries.
30.	Restructured Accelerated Power Development and Reform Program (RAPDRP) – This project is sponsored by Power Finance Corporation, Ministry of Power. The program aims at reducing the Technical and Commercial losses of the state distribution companies in Gujarat, Sikkim and west Bengal states.
31.	Energy & Resource mapping study in pharmaceutical sector in Gujarat
32.	Feasibility study and preparation of detailed project report for establishment of MEGA CFC's at Mumbai and Surat
33.	Performance evaluation of air pollution control devices at leading tire manufacturing company
34.	Supervision during construction of secured landfill of a leading copper manufacturing company
35.	Water Audit as per CGWA norms
	a. Water Audit at Calcom Cement India Ltd., Hojai, Assam
	b. Water Audit at Trinity FructaPvt. Ltd., Mangaldai
	c. Water Audit at ITC Ltd., Guwahati
	d. Water Audit at HUL, Tinsukia
	e. Water Audit at NEEPCO Ltd.
	f. Water Audit at Eco Tech Papers, Guwahati
36.	AMDC – assessment of Cost of Coal Extraction projects – Govt of Assam
37.	Implementation of ISO 9001 at Udyog Bhawan Assam
38.	Impact Assessment of the NSKFDC scheme
39.	Impact Evaluation of ALIMCO scheme
40.	Impact Evaluation of Upgradation of Existing ITIs to Modern it is
41.	Impact Evaluation of NAPS scheme
42.	MIIUS scheme monitoring
43.	Impact Fast Track Special Courts – POCSO
44.	Mandatory Energy Audit of Mahan Aluminium, Hindalco Industries Ltd., Madhya Pradesh
45.	Mandatory Energy Audit of Aditya Aluminium, Hindalco Industries Ltd., Sambalpur Orissa

46.	Energy Audit of Himatsingka Linens Limited, Hassan, Karnataka.
47.	Water Audit of Marki Mangli – I Coal Mine, Topworth Urja & Metals Ltd., Yavatmal, Maharashtra.
48.	Energy Audit of South Central Railway, Carriage Workshop, Lallaguda.
49.	PMC work Executed in Medak Pharmaceutical cluster, Telangana.
50.	Energy and Resource mapping of MSME Clusters in India for Pharma Sector
51.	Preamble about the Assignment: Energy Audit and Conservation study at NIIMS.
52.	Water Assessment Study for National Thermal Power Corporation Limited, Anta, Rajasthan.
53.	Water Balance Audit at NTPC Tanda
54.	Study on Technical inputs for upgradation of existing non-operational CETP and its Conveyance system at Jainpur,Industrial Area, Kanpur Dehat, UP.
55.	Three SOR studies were carried out for following subsidiaries of Coal India Ltd.
	• Mahanadi Coalfields Ltd.
	• Central Coalfields Ltd.
	• Northern Coalfields Ltd.
56.	Water Audit Studies
	1. Vishnu Sugar Mills, Gopalganj
	2. Bharat Sugar Mills, Sidhwalia
	3. HIL Limited, Industrial Area, Jasidih, Deoghar
	4. New Swadeshi Sugar mills Narkatiaganj
	5. New Swadeshi Sugar mills Narkatiaganj (Distillary)
	6. Hasanpur Sugar Mill, Hasanpur Road, Samastipur
	7. Mash Agro Food Ltd. Kisanganj
	8. Harinagar Sugar Mills Ltd. (Sugar Unit)
	9. Harinagar Sugar Mills Ltd. (Ethanol Unit)
	10. Al-Sameer Exports Pvt. Ltd. Forbesganj, Bihar
	11. ITC Limited Dairy plant, Munger
	12. Steel Strips Wheels Limited, Hot Rolling Mill, Jharkhand
	13. Reserve Bank of India Patna
57.	Third Party Evaluation of schemes supported by Department of Consumer Affairs
58.	Manpower Assessment, Manpower Planning and Analysis of Organisation Structure for Power Finance Corporation Ltd. (PFC)
59.	Study for project "Introduction of Pulses Technology in Rice Fallow to improve livelihood and Nutritional Security of the Farmers of Tribal People of Vidarbha region" for International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
60.	Preparation of Comprehensive District Agriculture Plan for Directorate of Agriculture, Govt. of Uttar Pradesh
61.	Study on difference between Price of Wholesale and Retail Market for Onion & Tomato for Department of Consumer Affairs, GoI

62.	Evaluation of Pilot Project on Improved Cultivation and Advanced Retting Exercise (ICARE) for National Jute Board
63.	Impact Evaluation of National Programme for Dairy Development (NPDD) in Uttarakhand for Uttarakhand Co-operative Dairy Federation Ltd. (UCDF Ltd.)
64.	Evaluation of Schemes of Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
65.	Capacity Building of State/UTs for data on domestic & Foreign Tourist Visits/Visitors, Ministry of Tourism, Govt. of India
66.	Assessment of Performance of Schemes of Powerloom Sector
67.	Upgradation of Existing Government ITIs into Model it is
68.	Spares Part Study at South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur
69.	5S Audit & Certification for IOCL Lucknow

4.8 Select list of training programs conducted during FY 2020-21

NPC conducted various online/offline training programs during FY2020-21. Some of the major training programs are as follows:

S.No.	
1.	**Technical, Policy Instruments and Frameworks for shifting to Renewable Energy" for international participants which was sponsored by Indian Technical & Economic Cooperation Programme (e-ITEC) of Ministry of External affairs, GoI**
2.	Environmental Monitoring – Sample collection of Effluent, AAQM, Stack and Testing of Various Environmental Parameters like Air, Water and Noise in Laboratory sponsored by Central Pollution Control Board, New Delhi
3.	Seven QC Tools for Productivity was conducted at AIP during 22-23rd February, 2021 for Indian Oil Corporation Limited, Southern Region Pipelines (SRPL)
4.	Online training programs for the Department of Public Enterprises, Government of Karnataka,
	• Lean Manufacturing Awareness for Productivity Improvement
	• Energy Audit and Conservation in Electrical utilities
	• Integrated Management System (ISO 9001-14001-45001) Awareness and Implementation
	• Performance Management
5.	Internal Auditing Based on ISO 9001, ISO 14001,ISO 45001 and ISO 50001
6.	Online In-House training on Failure Mode Effect Analysis(FEMA) for ICF, Chennai
7.	Online In-House Training on Improving Effectiveness of PA/PS for EPFO, Kolkata

S.No.	
8.	3 No's Online In-House Training Programme on Retirement Planning for NPCIL, Mumbai
9.	3 No's Online In-house Training Programme on Energy Managers & Energy Auditors of the State sponsored by EIC & SDA, Bhubaneswar
10.	Online Quiz for Energy Auditors & Energy Professionals of Odisha & EC Day 2020 for EIC-E-Cum-PCEI & SDA(O), Bhubaneswar
11.	Online In-House Training Programme on Adapting & Responding Effectively to Change for PGCIL, Bhubaneswar
12.	5 Days Preparatory Training Course for EIC-E-Cum-PCEI & SDA(O),BBSR &NTPC,Kaniha,Angul
13.	5 Days Preparatory Training Course for NTPC, Sipat, Chhattisgarh
14.	Conflict Resolution and Financial Management
15.	"Train the Trainers" workshop for M/s South Eastern Coal Fields Ltd, Management Development Institute, Bilaspur
16.	State Level Boiler Workshop in association with Chief Inspector of Boilers, Assam at Dibrugarh
17.	Capacity Building Programme on Energy Efficiency for the Employees of Hyderabad Metropolitan Water Supply & Sewerage Board (HMWS&SB) under Municipal Demand Side Management (MuDSM)
18.	Online Webinar Series for Prospective Energy Managers and Energy Auditors – BEE's NCE
19.	TSREDCO Sponsored Energy Conservation Week Celebrations – 2020
20.	E-Certification Course on "Industrial Water Treatment for Professionals"
21.	One Month online Course on Industrial Safety
22.	Online Training Series for Mohali Industries Association under GIZ MSME Inno Project
23.	Online Training on Advanced Excel for E-Cell, TISS Mumbai
24.	5S Training at various locations of IOCL

HARIT SARIS & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Independent Auditor's Report

To The Members of
National Productivity Council
5-6 Institutional Area,
Lodi Road,
New Delhi – 110003

Opinion

We have audited the financial statements of National Productivity Council, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, and the Income and Expenditure Account for the year then ended, including a summary of significant accounting policies.

The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained by the Council.

In our opinion, and to the best of our information and explanations given to us, the said accounts, **subject to the observations given in Annexure-1 and their consequential effect on Income and Expenditure, Assets and Liabilities and read together with accounting policies and notes thereon,** give a true and fair view:

i) In case of the Statement of affairs of the Council as at **31st March 2021**; and

ii) In the case of Income & Expenditure Account of the excess of expenditure over income of the Council for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

M/s. Harit Saris & Associates Chartered Accountants FRN. 014584N New Delhi

Head Off.: B-25, 2nd Floor, Okhla Indl. Area, Ph.-II, New Delhi-110020
Branch : 119, First Floor, Vardhman Market, Ram Nagar, Delhi - 110092
FRN: 014584N, Web : www.hsaca.in
H.O. : 011-41618989, 42638989
BR.O. : 011-47354318
Email : hsa@hsaca.in

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Societies Registration Act, 1860 of India and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the council's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the council's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

For **Harit Saris & Associates**
Chartered Accountant
Firm Registration No: 014584N

Date: 30/11/2021
Place: Delhi
UDIN: 21094269AAAACG5624

CA Harit Kumar Garg
Partner
Membership No.: 094269

Annexure 1 referred to in our report on the accounts of National Productivity Council for the Year ended 31st March 2021

1. ***Fixed Assets:-***

i) Fixed Assets Register at HQ is available in two parts i.e. prior to 17-10-2005 and the subsequent one from 17-10-2005 in revised GRF format. As per the previous Audit reports it was observed that certain fixed assets were disposed of in earlier years but the sale proceeds were treated as receipts in Income & Expenditure Account instead of crediting the same to the cost of assets sold and writing off balance written down value of those assets. It was also reported / explained that this would only make small difference in the gross & net blocks, which may be adjusted through proper procedures. During the year under audit, it was observed that no adjustment was made by the Council in this regard.

ii) During the FY 2020-21 there was no reconciliation of Fixed Asset of headquarter and any of the RDs, between the physical and Book records, consequently the financial impact if any, on account of shortage / discard / non-working of fixed asset is not ascertainable, which may have impact on the profitability & statement of affair of Council as on 31.03.2021.

2. ***Sundry Debtors: -***

i) The management has not obtained debtors balance confirmation for the F.Y 2020-21.

ii) Sundry Debtors amounting to Rs. 624.50 lakhs (PY- Rs.383.94 lakhs) outstanding as on 31-03-2021, include Book Debts of Rs. 173.11 lakhs (PY- Rs. 138.94 lakhs) outstanding for more than 3 years for which Council has created provision for doubtful debts of Rs.173.11 Lakhs as on 31.03.2021.

iii) During the audit, it was observed that unrecognized receipts of Rs 73,31,326.48 stand unadjusted as on 31.03.2021. Out of the above amount Rs 22,03,897.48 pertain to F.Y 2020-21. In the absence of identification, the council has shown the above amount as advance received from debtors in GST return and paid GST @ 18% thereon from its own fund without identifying/reconciling the parties. In our opinion, the above amount might

M/s. Hari Saris & Associates Chartered Accountants FRN 014584N New Delhi

have been received from various unpaid debtors. In the absence of identification, the outstanding debtors as on 31.03.21 might be overstated to that extent.

3. *Projects:-*

i) On the receipt of project money, the council pay applicable GST @ 18% on same and record the same as expenses for project.

ii) The council issues 'Bill for sponsored project' to demand money from Sponsors of projects. GST @ 18% is booked and paid on these bills, although these are only letter of demand. This amount of GST is treated as expenses for project/proposed project. There are many instances where the money requested has not been received at all. This leads to unnecessary payment of GST and increase in project related expenditures. Further, these receipts are shown as B2C sales in GST returns due to uncertainty of related consultancy income.

iii) During the audit we observed that utilization certificate for projects submitted by the council shows gross figures of expense related to the project. Interest income earned on saving account from the project money received has not been disclosed in the utilization certificate issued by the Council.

iv) The council is not taking input tax credit on expenditure incurred for the project. Expenses incurred on the project needs to be reduced to the extent of ITC. This led to overpayment of GST and overbooking of expenditure related to the projects. This results in loss to the Sponsors of the projects.

v) During the year 2020-21, aggregate of Debit balance pending for recovery in project accounts financed by various agencies as on 31-03-2021 is Rs. 14.35 lakhs (PY- Rs. 12.09 lakhs) and aggregate of credit balance in project accounts financed by various agencies as on 31-03-2021 is Rs. 628.03 lakhs (PY- Rs. 465.07 Lakhs). These needs to be reviewed and provided for / adjusted depending upon the chances of recovery / refund.

4. *Loans & Advances*

i) The council have outstanding balance of Rs 10,22,359/- for advance given to employees for expenses which remains unadjusted as on 31.03.2021. The income of

M/s. Hari Saris & Associates Chartered Accountants FRN. 0[illegible]84N New Delhi

the Council is overstated to the extent of unreported expenses of these employees. We are unable to comment that up to what extent these advances are mis-utilized of by the employees.

ii) *The council have outstanding balance of Rs 43,88,483/- for security/earnest money deposits paid to various entities for projects undertaken. In many instances' projects have been completed but the deposits are still not received. The council needs to put up a system for reconciling it properly and maintaining records of security money paid.*

5. Cash and Bank Balances

It is observed that the retention bank account No 091601000037555 maintained with Indian Overseas Bank has not been reconciled by the council. The account balance as per the bank certificate is Rs 99,313/-, however the book balance is Rs 6,97,744/-. Thus, having a difference of Rs 5,98,431/-. This results in overvaluation of assets as well as liabilities.

6. Income Tax Refunds: -

It is observed that Income Tax Refunds pending to be received for more than 4 years from Income Tax department is Rs. 84.35 Lakhs from the F.Y. 2005-06 to F.Y. 2014-15.

7. TDS Non reconciliation

TDS credit of Rs. 9,61,628/- is excess booked in Books of Account as compared to Form 26AS for the Financial Year 2020-21. Also there are TDS amounting to Rs. 9,14,020/- which is not entered in the books of account being unidentifiable.

8. Goods and Service Tax

i) The reconciliation of Output as per Books of accounts and GSTR 1 shows differences.(Attached as Schedule 'A') The council needs to put up a system for reconciling it properly to avoid interest/penalties.

M/s. Hari Saris & Associates
FRN: 014584N
New Delhi
Chartered Accountants

ii) *The reconciliation of Output as per Books of accounts and GSTR 3B shows differences. (Attached as Schedule 'B') The council needs to put up a system for reconciling it properly to avoid interest/penalties.*

iii) *The reconciliation of input tax credit availed and utilized as per GSTR-3B and those reflecting in GSTR-2A shows differences (attached as Schedule 'C'). The council needs to put up a system for reconciling it properly to avoid interest/penalties.*

iv) *It is found that there are some entries in GSTR-2A but not in book of accounts which would result in loss of input tax credit and may attract interest and penalties. The council needs to put up a system for reconciling input as per books of accounts and as per Form GSTR-2A reflecting on Portal.*

v) *GST TDS has not been deducted properly and reconciliation for the same has not been provided by the council. The same has been brought to the notice of the management and liabilities for the same is booked. GSTR-7 for these liabilities needs to be filed by the council.*

vi) *Following GST TDS deducted by the parties and recorded in the books of accounts are not reflecting on GST portal.*

Branch	Debtors	CSGT (TDS)	SGST (TDS)	IGST (TDS)
Chennai	Bureau Of Energy Efficiency	-	-	21,060
Kanpur	Up Rajaya Vidyut Utpadan Nigam Ltd	-	-	6,000
Headquarter	Khadi And Village Industries Commission-It			16,320
Headquarter	Bureau Of Energy Efficiency	7,200	7,200	-
Headquarter	Ministry Of Mines	500	500	

Further following GST TDS reflecting on portal in the current financial year is short recorded/not recorded in current financial year.

Branch	Debtors	CSGT (TDS)	SGST (TDS)	IGST (TDS)

M/s. Harit Saris & Associates FRN: 0[illegible]N New Delhi Chartered Accountants

Chennai	Tamil Nadu Pollution control board.	9,975	9,975	-
Kanpur	Artificial Limbs Manufacturing Co	2,975	2,975	-
Jaipur	WDRA	-	-	6,355.92
Headquarter	Bureau of Energy Efficiency	2,070	2,070	-
Headquarter	Institute of Life Science	-	-	7,078
Headquarter	Directorate of Income Tax HRD	225	225	-

i) During the audit it was observed that the GSTR-9 and 9C filed for the F.Y 2019-20 shows difference in turnover and tax thereon as per books and return (Attached as Schedule 'D'). The council needs to put up a system for reconciling it properly to avoid any ligation.

ii) During the audit it was observed the council has received security services which is under reverse charge mechanism and made payment to service provider including GST on bill and availed ITC for the same. Further council has also paid GST under reverse charge mechanism on such security services and availed input for tax paid under RCM. This leads to unnecessary payment of GST and availment of input tax credit.

9. Default in TDS statements

i) As per online Traces website, there are TDS defaults of Rs 10,94,420/- for the financial years starting from 2007-08 to 2020-21. The said defaults must be rectified by the council to avoid penalties and interest. RD wise closing balance of these defaults are as follows:

S.No.	Branches	Last three years	Prior years
1.	Headquarter & Patna	20,060	5,76,080
2.	Chennai	3,450	65,230
3.	Mumbai	25,930	25,020
4.	Kolkata	2,54,740	37,520
5.	Gandhinagar	8,360	660
6.	Jaipur	2,010	5,550

7.	Bangalore	-	16,570
8.	Kanpur	3,430	2,510
9.	Guwahati	200	-
10.	Bhubaneswar	4,370	33,510
11.	Chandigarh	30	4,620
12.	Hyderabad	4,570	-
	Total	**3,27,150**	**7,67,270**

ii) During the audit, it was observed that there is difference in Salary shown in Form 16 and salary as per books in various branches. Further, during the F.Y 2020-21, arrear of salary being One time increment of Rs 2,30,47,408/- has been paid to various present and past employees of the council. However, TDS is deducted on gross amount of salary (including increment) without giving Relief under section 89 of Income Tax Act, 1961.

10. Gratuity and Leave Encashment:

i) The balance of Rs 6,45,46,582/- being deferred revenue expenditure of leave encashment created in F.Y 2019-20 to be written off equally in 4 years has been wholly written off in current year. Further provision of Rs 2,74,62,054 has been made during the F.Y 2020-21 towards payment of Leave Encashment payable at the time of retirement of employees.

ii) Current liabilities include Provision for Gratuity liabilities of Rs. 1270.99 Lakhs (PY- Rs. 1,460.18 lakhs) as on 31.03.2021 as per Certificate of Actuarial Dr. V. P. Sabharwal dated 01.09.2021. The Council has neither taken any Insurance policy for Gratuity payment nor has created any approved Gratuity Trust, but earmarked FDR for Rs. 621.16 Lakhs (PY-575.99 Lacs) lying with IOB towards gratuity liabilities. In our opinion, the amount equal to the liability on account of gratuity liability should be earmarked and kept invested.

11. Advance from Customers/parties:

There is a balance of Rs 1,15,63,774/- being amount received in advance from various debtors. We are unable to comment on its impact in the absence of any confirmation from debtors, whether these amounts can be adjusted against outstanding balances of various debtors.

M/s Hari Saris & Associates
FRN:
New Delhi
Chartered Accountants

12. Other Current Liabilities:

The council receives security deposits from various parities balances as on 31.03.2021 is as follows. The council has neither maintained any register, nor any reconciliation has been made for the security money received.

S.No.	Particulars	Amounts
1.	Headquarter	56,10,941
2.	Chennai	8,04,443
	Total	64,15,384

13. Internal Audit

During the year under audit, it was observed that there are adequate internal controls of the council. In our opinion the internal audit system, which is an integral part of Internal control needs to be strengthen and strictly followed commensurate to the size of the Council.

14. Confirmation

The balances of Sundry Debtor, Sundry Creditor, advance recoverable, advance payable, security deposits / payable with / to various agencies / parties etc. as on 31.03.2021 are subject to confirmation and reconciliation. Which may have impact on the profitability and state of affair of Council as on 31.03.2021.

For **Harit Saris & Associates**
Chartered Accountant
Firm Registration No: 014584N

M/s. Harit Saris & Associates
FRN: 014584N
New Delhi
Chartered Accountants

CA Harit Kumar Garg
Partner
Membership No.: 094269

Date: 30/11/2021
Place: Delhi
UDIN: 21094269AAAACG5624

Schedule 'A'

Reconciliation of Output Tax as per GSTR 1 and books

HQ (07AAATN0402F1Z8)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	165,358,043.31	8,304,816.67	10,308,579.75	10,308,579.75	28,921,976.17
Less: Sales for F.Y 2019-20	654,095.00	117,737.10			117,737.10
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	164,703,948.31	8,187,079.57	10,308,579.75	10,308,579.75	28,804,239.07
Sales as per Books	124,829,121.71	6,070,803.18	4,145,433.13	4,145,433.13	14,361,669.44
Difference	39,874,826.60	2,116,276.39	6,163,146.62	6,163,146.62	14,442,569.63

AIP (33AAATN0402F1ZD)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	19,169,107.00	2,125,983.10	660,158.36	660,158.36	3,446,299.82
Sales as per Books	19,151,931.00	2,122,385.00	660,396.50	660,396.50	3,443,178.00
Difference	17,176.00	3,598.10	(238.14)	(238.14)	3,121.82

Guwahati (18AAATN0402F1Z5)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	4,574,550.50	168,480.90	327,469.10	327,469.10	823,419.10
Less: Sales for F.Y 2019-20	45,455.00	8,181.90			8,181.90
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	4,529,095.50	160,299.00	327,469.10	327,469.10	815,237.20
Sales as per Books	4,549,666.50	160,299.00	329,321.80	329,321.80	818,942.60
Difference	(20,571.00)	-	(1,852.70)	(1,852.70)	(3,705.40)

Kolkata (19AAATN0402F1Z3)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	6,777,580.95	804,324.42	207,820.08	207,820.08	1,219,964.58
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	6,777,580.95	804,324.42	207,820.08	207,820.08	1,219,964.58
Sales as per Books	7,137,289.24	869,073.60	207,820.08	207,820.08	1,284,713.76
Difference	(359,708.29)	(64,749.18)	-	-	(64,749.18)

MUMBAI(27AAATN0402F1Z6)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	11,514,639.00	175,500.00	948,567.53	948,567.53	2,072,635.06
Less: Sales for F.Y 2019-20	471,610.00		42,444.90	42,444.90	84,889.80
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	11,043,029.00	175,500.00	906,122.63	906,122.63	1,987,745.26
Sales as per Books	11,035,528.60	175,500.00	905,449.50	905,449.50	1,986,399.00
Difference	7,500.40	-	673.13	673.13	1,346.26

Chandigarh (04AAATN0402F1ZE)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	5,188,724.00	436,531.68	240,079.32	240,079.32	916,690.32
Less: Sales for F.Y 20:9-20	754,651.00	135,837.18			135,837.18
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	4,434,073.00	300,694.50	240,079.32	240,079.32	780,853.14
Sales as per Books	4,209,326.00	300,695.00	240,160.50	240,160.50	781,016.00
Difference	224,747.00	(0.50)	(81.18)	(81.18)	(162.86)

Gandhinagar (24AAATN0402F1ZC)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	14,704,751.50	468,039.15	1,089,408.06	1,089,408.06	2,646,855.27
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	14,704,751.50	468,039.15	1,089,408.06	1,089,408.06	2,646,855.27
Sales as per Books	14,725,164.14	447,158.50	1,101,684.00	1,101,684.00	2,650,526.50
Difference	(20,412.64)	20,880.65	(12,275.94)	(12,275.94)	(3,671.23)

M/s. Hari Saris & Associates ★ Chartered Accountants ★ FRN-014584N New Delhi

Jaipur (08AAATN0402F1Z6)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	5,035,413.67	447,131.31	218,992.76	218,992.76	885,116.83
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	5,035,413.67	447,131.31	218,992.76	218,992.76	885,116.83
Sales as per Books	5,049,112.83	447,131.18	220,225.68	220,225.68	887,582.54
Difference	(13,699.16)	0.13	(1,232.92)	(1,232.92)	(2,465.71)

HYDERABAD (36AAATN0402F1Z7)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	8,100,554.06	648,723.08	396,275.30	396,275.30	1,441,273.68
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	8,100,554.06	648,723.08	396,275.30	396,275.30	1,441,273.68
Sales as per Books	8,100,554.06	648,724.60	396,278.52	396,278.52	1,441,281.64
Difference	-	(1.52)	(3.22)	(3.22)	(7.96)

Bhubneshwar (21AAATN0402F3ZG)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	11,154,557.69	637,845.42	682,750.62	682,750.62	2,003,346.66
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	11,154,557.69	637,845.42	682,750.62	682,750.62	2,003,346.66
Sales as per Books	10,984,506.00	607,262.00	682,770.00	682,770.00	1,972,802.00
Difference	170,051.69	30,583.42	(19.38)	(19.38)	30,544.66

Bangalore (29AAATN0402F1Z2)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	3,269,899.15	398,617.17	94,982.34	94,982.34	588,581.85
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	3,269,899.15	398,617.17	94,982.34	94,982.34	588,581.85
Sales as per Books	3,270,499.15	398,617.18	95,036.33	95,036.33	588,689.84
Difference	(600.00)	(0.01)	(53.99)	(53.99)	(107.99)

Kanpur (09AAATN0402F1Z4)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	5,119,653.00	183,985.83	368,775.86	368,775.86	921,537.55
Less: Sales for F.Y 2019-20	-	-	-	-	-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	5,119,653.00	183,985.83	368,775.86	368,775.86	921,537.55
Sales as per Books	5,087,902.08	183,985.84	365,918.23	365,918.23	915,822.30
Sales of fixed assets as per books	33,815.00	-	3,043.35	3,043.35	6,086.70
Difference	(2,064.08)	(0.01)	(185.72)	(185.72)	(371.45)

Patna (10AAATN0402F2ZK)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-1	7,785,751.57	954,754.74	223,340.27	223,340.27	1,401,435.28
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-1 for F.Y 2020-21	7,785,751.57	954,754.74	223,340.27	223,340.27	1,401,435.28
Sales as per Books	7,785,556.57	955,390.86	223,004.66	223,004.66	1,401,400.18
Sales of fixed assets as per books	3,729.00		335.61	335.61	671.22
Difference	(3,534.00)	(636.12)	(0.00)	(0.00)	(636.12)

Schedule 'B'

Reconciliation of Output Tax as per GSTR 3B and books

HQ (07AAATN0402F1Z8)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	156,178,577.00	8,262,047.38	9,503,813.00	9,503,813.00	27,269,673.38
Sales as per Books	124,829,121.71	6,070,803.18	4,145,433.13	4,145,433.13	14,361,669.44
Difference	31,349,455.29	2,191,244.20	5,358,379.87	5,358,379.87	12,908,003.94

AIP (33AAATN0402F1ZD)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	19,169,107.00	2,125,983.60	660,158.36	660,158.36	3,446,300.32
Sales as per Books	19,151,931.00	2,122,385.00	660,396.50	660,396.50	3,443,178.00
Difference	17,176.00	3,598.60	(238.14)	(238.14)	3,122.32

Guwahati (18AAATN0402F1Z5)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	4,574,550.50	168,481.00	327,468.99	327,468.99	823,418.98
Less: Sales for F.Y 2019-20	45,455.00	8,182.00			8,182.00
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2019-20	4,529,095.50	160,299.00	327,468.99	327,468.99	815,236.98
Sales as per Books	4,549,666.50	160,299.00	329,321.80	329,321.80	818,942.60
Difference	(20,571.00)	-	(1,852.81)	(1,852.81)	(3,705.62)

Kolkata (19AAATN0402F1Z3)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	6,777,580.95	804,324.06	207,820.08	207,820.08	1,219,964.22
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2019-20	6,777,580.95	804,324.06	207,820.08	207,820.08	1,219,964.22
Sales as per Books	7,137,289.24	869,073.60	207,820.08	207,820.08	1,284,713.76
Difference	(359,708.29)	(64,749.54)	-	-	(64,749.54)

MUMBAI(27AAATN0402F1Z6)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	11,036,068.60	175,500.00	905,449.17	905,449.17	1,986,398.34
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	11,036,068.60	175,500.00	905,449.17	905,449.17	1,986,398.34
Sales as per Books	11,035,528.60	175,500.00	905,449.50	905,449.50	1,986,399.00
Difference	540.00	-	(0.33)	(0.33)	(0.66)

Chandigarh (04AAATN0402F1ZE)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	5,188,724.00	436,532.00	240,079.32	240,079.32	916,690.64
Less: Sales for F.Y 2019-20	754,651.00	135,837.18			135,837.18
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	4,434,073.00	300,694.82	240,079.32	240,079.32	780,853.46
Sales as per Books	4,209,326.00	300,695.00	240,160.50	240,160.50	781,016.00
Difference	224,747.00	(0.18)	(81.18)	(81.18)	(162.54)

Gandhinagar (24AAATN0402F1ZC)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	14,704,751.50	447,159.15	1,099,848.06	1,099,848.06	2,646,855.27
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	14,704,751.50	447,159.15	1,099,848.06	1,099,848.06	2,646,855.27
Sales as per Books	14,725,164.14	447,158.50	1,101,684.00	1,101,684.00	2,650,526.50
Difference	(20,412.64)	0.65	(1,835.94)	(1,835.94)	(3,671.23)

M/s. Hari Saris & Associates Chartered Accountants FRN-01...84N New Delhi

Jaipur (08AAATN0402F1Z6)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	5,035,413.67	447,131.18	218,992.76	218,992.76	885,116.70
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	5,035,413.67	447,131.18	218,992.76	218,992.76	885,116.70
Sales as per Books	5,049,112.83	447,131.18	220,225.68	220,225.68	887,582.54
Difference	(13,699.16)	-	(1,232.92)	(1,232.92)	(2,465.84)

HYDERABAD (36AAATN0402F1Z7)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	8,100,554.06	648,724.60	396,278.52	396,278.52	1,441,281.64
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	8,100,554.06	648,724.60	396,278.52	396,278.52	1,441,281.64
Sales as per Books	8,100,554.06	648724.6	396,278.52	396,278.52	1,441,281.64
Difference	-	-	-	-	-

Bhubneshwar (21AAATN0402F3ZG)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	10,984,456.00	607,262.00	682,770.00	682,770.00	1,972,802.00
Less: Sales for F.Y 2018-19					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	10,984,456.00	607,262.00	682,770.00	682,770.00	1,972,802.00
Sales as per Books	10,984,506.00	607,262.00	682,770.00	682,770.00	1,972,802.00
Difference	(50.00)	-	-	-	-

Bangalore (29AAATN0402F1Z2)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	3,269,899.15	398,617.66	94,982.80	94,982.80	588,583.26
Less: Sales for F.Y 2019-20					-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	3,269,899.15	398,617.66	94,982.80	94,982.80	588,583.26
Sales as per Books	3,270,499.15	398,617.18	95,036.33	95,036.33	588,689.84
Difference	(600.00)	0.48	(53.53)	(53.53)	(106.58)

Kanpur (09AAATN0402F1Z4)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	5,119,653.00	183,986.18	368,775.80	368,775.80	921,537.78
Less: Sales for F.Y 2019-20	-	-	-	-	-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	5,119,653.00	183,986.18	368,775.80	368,775.80	921,537.78
Sales as per Books	5,121,717.08	183,985.84	368,961.58	368,961.58	921,909.00
Difference	(2,064.08)	0.34	(185.78)	(185.78)	(371.22)

Patna (10AAATN0402F2ZK)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-3B	7,785,751.57	954,754.74	223,340.27	223,340.27	1,401,435.28
Less: Sales for F.Y 2019-20	-	-	-	-	-
Total sales as per GSTR-3B for F.Y 2020-21	7,785,751.57	954,754.74	223,340.27	223,340.27	1,401,435.28
Sales as per Books	7,789,285.57	955,390.86	223,340.27	223,340.27	1,402,071.40
Difference	(3,534.00)	(636.12)	-	-	(636.12)

Schedule C

Reconciliation of Input tax credit as per GSTR-3B and GSTR-2A

Patna (10AAATN0402F2ZK)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	112,485.98	26,045.71	26,045.71	164,577.40
Input reflecting in GSTR-2A	113,287.45	36,491.27	36,491.27	186,269.99
Difference	(801.47)	(10,445.56)	(10,445.56)	(21,692.59)

Chandigarh (04AAATN0402F1ZE)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	10,556.00	92,547.34	92,547.34	195,650.68
Input reflecting in GSTR-2A	2,994.76	80,083.95	80,083.95	163,162.66
Difference	7,561.24	12,463.39	12,463.39	32,488.02

HYDERABAD (36AAATN0402F1Z7)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	161,863.00	181,839.00	181,839.00	525,541.00
Input reflecting in GSTR-2A	250,265.94	189,033.93	189,033.93	628,333.80
Difference	(88,402.94)	(7,194.93)	(7,194.93)	(102,792.80)

HQ (07AAATN0402F1Z8)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	585,419.00	1,599,993.00	1,599,993.00	3,785,405.00
Input reflecting in GSTR-2A	1,813,356.23	1,711,175.66	1,711,175.66	5,235,707.55
Difference	(1,227,937.23)	(111,182.66)	(111,182.66)	(1,450,302.55)

Bangalore (29AAATN0402F1Z2)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	14,280.00	129,129.46	124,774.50	268,183.96
Input reflecting in GSTR-2A	18,997.15	112,553.81	112,553.81	244,104.77
Difference	(4,717.15)	16,575.65	12,220.69	24,079.19

Jaipur (08AAATN0402F1Z6)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	35,757.00	15,138.86	15,138.86	66,034.72
Input reflecting in GSTR-2A	70,065.00	16,142.76	16,142.76	102,350.52
Difference	(34,308.00)	(1,003.90)	(1,003.90)	(36,315.80)

Kanpur (09AAATN0402F1Z4)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	22,744.08	38,650.22	38,650.22	100,044.52
Input reflecting in GSTR-2A	56,619.95	48,760.99	48,760.99	154,141.93
Difference	(33,875.87)	(10,110.77)	(10,110.77)	(54,097.41)

Kolkata (19AAATN0402F1Z3)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B		12,740.09	12,740.09	25,480.18
Input reflecting in GSTR-2A	-	16,288.73	16,288.73	32,577.46
Difference	-	(3,548.64)	(3,548.64)	(7,097.28)

MUMBAI(27AAATN0402F1Z6)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	137,470.00	55,127.47	55,127.47	247,724.94
Input reflecting in GSTR-2A	137,470.98	58,622.18	58,622.18	254,715.34
Difference	(0.98)	(3,494.71)	(3,494.71)	(6,990.40)

Bhubneshwar (21AAATN0402F3ZG)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	165,742.84	48,888.61	48,888.61	263,520.06
Input reflecting in GSTR-2A	318,104.32	32,480.24	32,480.24	383,064.80
Difference	(152,361.48)	16,408.37	16,408.37	(119,544.74)

Guwahati (18AAATN0402F1Z5)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	15,628.00	1,028.00	1,028.00	17,684.00
Input reflecting in GSTR-2A	28,674.43	18,902.91	18,902.91	66,480.25
Difference	(13,046.43)	(17,874.91)	(17,874.91)	(48,796.25)

Gandhinagar (24AAATN0402F1ZC)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	12,998.00	226,214.61	226,214.61	465,427.22
Input reflecting in GSTR-2A	53,914.32	148,206.75	148,206.75	350,327.82
Difference	(40,916.32)	78,007.86	78,007.86	115,099.40

AIP (33AAATN0402F1ZD)

Particulars	IGST	CGST	SGST	Total
Input availed in GSTR-3B	189,441.13	272,467.90	272,467.90	734,376.93
Input reflecting in GSTR-2A	257,495.94	409,659.56	409,659.56	1,076,815.06
Difference	(68,054.81)	(137,191.66)	(137,191.66)	(342,438.13)

Schedule 'D'

Reconciliation of Output Tax as per GSTR 9 and books for the F.Y 2019-20

HQ (07AAATN0402F1Z8)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	168,420,437.53	9,728,133.66	9,442,807.88	9,442,807.88	28,613,749.42
Sales as per Books	106,606,233.00	9,532,425.00	9,617,159.00	9,617,159.00	28,766,743.00
Difference	61,814,204.53	195,708.66	(174,351.12)	(174,351.12)	(152,993.58)

AIP (33AAATN0402F1ZD)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	32,514,524.74	848,951.00	2,439,920.00	2,439,920.00	5,728,791.00
Sales as per Books	32,656,050.00	841,002.00	2,366,015.00	2,366,015.00	5,573,032.00
Difference	(141,525.26)	7,949.00	73,905.00	73,905.00	155,759.00

Kolkata (19AAATN0402F1Z3)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	12,904,083.00	154,095.00	1,051,470.00	1,051,470.00	2,257,035.00
Sales as per Books	12,945,457.00	173,242.26	1,051,470.00	1,051,470.00	2,276,182.26
Difference	(41,374.00)	(19,147.26)	-	-	(19,147.26)

MUMBAI(27AAATN0402F1Z6)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	3,593,984.00	176,197.00	235,359.90	235,359.90	646,916.80
Sales as per Books	3,593,984.00	173,242.26	235,360.00	235,360.00	643,962.26
Difference	-	2,954.74	(0.10)	(0.10)	2,954.54

Chandigarh (04AAATN0402F1ZE)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	6,031,496.00	509,859.00	63,265.05	63,265.05	636,389.10
Sales as per Books	6,462,496.00	561,753.00	58,945.00	58,945.00	679,643.00
Difference	(431,000.00)	(51,894.00)	4,320.05	4,320.05	(43,253.90)

Gandhinagar (24AAATN0402F1ZC)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	8,370,827.00	436,374.00	448,843.00	448,843.00	1,334,060.00
Sales as per Books	8,480,827.00	438,282.00	517,808.50	517,808.50	1,473,899.00
Difference	(110,000.00)	(1,908.00)	(68,965.50)	(68,965.50)	(139,839.00)

Jaipur (08AAATN0402F1Z6)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	10,047,035.00	812,037.00	232,785.00	232,785.00	1,277,607.00
Sales as per Books	10,069,875.00	812,037.00	232,785.00	232,785.00	1,277,607.00
Difference	(22,840.00)	-	-	-	-

Bhubneshwar (21AAATN0402F3ZG)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	6,393,783.00	509,090.94	288,990.00	288,990.00	1,087,070.94
Sales as per Books	6,336,912.00	498,854.00	288,990.00	288,990.00	1,076,834.00
Difference	56,871.00	10,236.94	-	-	10,236.94

Guwahati (18AAATN0402F1Z5)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	7,178,285.00	367,611.30	430,740.00	430,740.00	1,229,091.30
Sales as per Books	7,178,285.00	367,612.00	430,740.00	430,740.00	1,229,092.00
Difference	-	(0.70)	-	-	(0.70)

HYDERABAD (36AAATN0402F1Z7)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	7,605,258.00	850,389.00	244,986.00	244,986.00	1,340,361.00
Sales as per Books	7,605,258.00	850,389.00	244,986.00	244,986.00	1,340,361.00
Difference	-	-	-	-	-

Bangalore (29AAATN0402F1Z2)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	3,248,088.00	323,115.84	130,770.00	130,770.00	584,655.84
Sales as per Books	3,248,088.00	323,115.84	130,770.00	130,770.00	584,655.84
Difference	-	-	-	-	-

Kanpur (09AAATN0402F1Z4)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	4,193,224.00	132,903.36	310,938.48	310,938.48	754,780.32
Sales as per Books	4,193,224.00	132,903.36	310,938.48	310,938.48	754,780.32
Difference	-	-	-	-	-

Patna (10AAATN0402F2ZK)

Particulars	Taxable	IGST	CGST	SGST	Total Tax
Sales as per GSTR-9	4,556,295.00	809,607.60	5,262.75	5,262.75	820,133.10
Sales as per Books	4,556,295.00	809,607.60	5,262.75	5,262.75	820,133.10
Difference	-	-	-	-	-

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2021

Particulars	Sch. No		As at March 2021		As at March 2020
SOURCES OF FUNDS					
Capital Fund	1		32,29,06,020		32,46,63,578
Project Financed by Various Agencies	2		6,28,03,045		4,65,07,252
Current Liabilities & Provisions	3		31,62,93,140		34,11,19,274
TOTAL			70,20,02,205		71,22,90,103
APPLICATION OF FUNDS					
Fixed Assets	4				
Gross Block-Plan		33,82,69,105		33,81,43,503	
Gross Block-Non Plan		5,79,21,038	39,61,90,143	5,16,85,790	38,98,29,293
Less :Depreciation					
Plan		26,34,09,740		25,34,82,925	
Non Plan		3,98,27,714	30,32,37,454	3,54,59,328	28,89,42,253
Net Block			**9,29,52,689**		**10,08,87,040**
Current Assets, Loans and Advances	5				
Sundry Debtors		4,51,38,965		2,44,99,460	
Cash & Bank Balance		17,60,51,236		11,91,71,167	
Investments in Fixed Deposit		15,44,29,965		12,48,93,894	
Loans & Advances		2,75,26,341		3,11,13,930	
Income Tax Recoverable		3,84,55,711	44,16,02,219	9,57,14,887	39,53,93,337
Deferred Revenue Expenditure			-		6,45,46,582
Proj. financed by various agencies.	2		14,35,271		12,09,096
Excess of expenditure over income	6		16,60,12,024		15,02,54,047
TOTAL			70,20,02,205		71,22,90,103
Significant accounting Policies and Notes of the Accounts	16				

As per our separate report of even date attached

For Harit Saris & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 014584N

CA Harit Kumar Garg, Partner
Membership Number : 094269

M/s. Harit Saris & Associates
FRN. 014584N
New Delhi
Chartered Accountants

For National Productivity Council

Dr Rajat Sharma
Group Head (Finance)

Navindra Kumar Chanji
Director General

डा. रजत शर्मा / Dr. Rajat Sharma
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अर्न्तगत)
(Under Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)
लोधी रोड, नई दिल्ली / Lodhi Road, New Delhi-110003

N. K. CHANJI
Director General
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
Department for Promotion of Industry & Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry
Government of India, New Delhi

Date : November 30, 2021
Place : New Delhi
UDIN :

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
Lodi Road, New Delhi

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

Particulars	Sch. No.		As at March 2021		As at March 2020
INCOME					
Grant-in-aid from Govt.					
PLAN					
Recd. during the year		18,20,000		50,00,000	
Balance b/f (+)		23,15,236		24,99,141	
		41,35,236		74,99,141	
Less: Assets purchased during year		-		-	
		41,35,236		74,99,141	
Less: Unspent Balance of Grant		5,74,710	35,60,526	23,15,236	51,83,905
NON PLAN					
Recd. Grant during the Year			20,33,45,000		26,90,00,000
Activity Revenue	7		20,95,43,754		19,97,32,464
Receipts from publication	8		1,26,350		1,64,884
Other Receipts	9		3,47,01,667		2,88,73,412
TOTAL			45,12,77,297		50,29,54,666
EXPENDITURE					
Employees Remuneration & Benefits	10		35,21,25,523		33,14,60,152
Office & Admn. Expenses	11		9,83,18,878		16,81,01,897
Plan Project*	12		35,60,526		51,83,905
Misc.& other charges	13		1,14,603		5,85,762
Interest & Finance charges	14		3,78,093		6,14,662
International Cooperation	15		-		1,62,874
Depreciation	4		1,25,37,651		1,19,68,914
Excess of income over expenditure			-1,57,57,977		-1,51,23,499
TOTAL			45,12,77,297		50,29,54,666
Significant accounting Policies and Notes of the Accounts	16				

As per our separate report of even date attached

For Harit Saris & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 014584N

CA Harit Kumar Garg, Partner
Membership Number : 094269

Date : November 30, 2021
Place : New Delhi
UDIN :

For National Productivity Council

Dr Rajat Sharma
Group Head (Finance)

Navindra Kumar Chanji
Director General

डा. रजत शर्मा / Dr. Rajat Sharma
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ)
(Under Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)
लोधी रोड, नई दिल्ली / Lodhi Road, New Delhi-110003

N. K. CHANJI
Director General
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
Department for Promotion of Industry & Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry
Government of India, New Delhi

SCHEDULE -2, PROJECT FINANCED BY VARIOUS AGENCIES (ALIVE) AS ON 31/03/2021

S.NO.	Figures for the previous year 2019-20 Dr.	Figures for the previous year 2019-20 Cr.	Name of the Project	Group	Receipt upto 1.4.2020	Reciept During the year 2020-21	Total as on 31/03/21	Exp upto 1.4.2020	Expen. During the year 2020-21	Written down value of assets	Total as on 31/03/2021	Balance DR.	Balance CR.	Ongoing /Closed
1	-	73,75,896	ABG/C DAP/2017-18	AB	1,95,96,800	37,13,200	2,33,10,000	1,20,20,984	9,79,732	-	1,30,00,636	-	1,03,09,364	Ongoing
2	-	6,11,610	ABG/CSIR-IHBT/2017-18	AB	16,87,500		16,87,500	10,75,890		-	10,75,890	-	6,11,610	Ongoing
3	-	7,70,084	ABG/CSIR-IHBT/WM-KTD/2019	AB	9,61,700		9,61,700	1,91,616		-	1,91,616	-	7,70,084	Ongoing
4	87,589		ABG/DSIIE/P/02/2019-20	AB	14,52,675	19,75,638	34,28,313	15,40,264	18,88,049	-	34,28,313	-		Closed
5	-	54,33,900	ABG/Evaluation/P/DOCA/2019-20	AB	66,65,820	16,66,455	83,32,275	12,31,920	70,99,420	-	83,31,340	-	935	Ongoing
6	4,83,438		ABG/MMA-DOS/2017-18	AB	32,27,064		32,27,064	37,10,492		-	37,10,492	4,83,428		Ongoing
7	-	13,83,987	ABG/NJB-ICARE/2018-19	AB	26,92,800	2,99,000	29,91,800	13,10,813	16,80,987	-	29,91,800	-	-	Closed
8	94,392	-	ABG/P/04/2019-20	AB	-	6,18,792	6,18,792	94,392	1,47,328	-	2,41,720	-	3,77,072	Ongoing
9	-	16,01,643	ABG/PFC/P/03/2019-20	AB	19,82,400	5,66,400	25,48,800	3,80,757	1,09,915	-	4,90,672	-	20,58,128	Ongoing
10	1,16,280	-	ABG/RKVY-LTP/2018-19	AB	4,97,200	7,45,800	12,43,000	6,13,480	6,29,520	-	12,43,000	-	-	Closed
11	-	-	ABG/UP-RKVY/16-17	AB	1,99,91,400	50,62,200	2,50,53,600	1,82,34,589	68,19,011	-	2,50,53,600	-	-	Closed
12	-	8,01,903	ABG/P/06/2019-20	AB	10,02,960	18,65,504	28,68,464	2,01,057	27,70,573	-	29,71,630	1,03,166	-	Ongoing
13	-	3,17,251	ABG/P/07/2019-20	AB	5,30,705	5,30,704	10,61,409	2,13,454	8,47,955	-	10,61,409	-	-	Closed
14	-	20,80,735	NMPB2016-17(AB)	AB	1,47,34,192	1,01,63,084	2,48,97,276	1,06,53,457	11,42,854	-	1,27,96,311	-	1,21,00,965	Ongoing
15	2,50,832	-	ABG/P/01/2020-21	AB	-	5,89,764	5,89,764	-	1,52,124	-	1,52,124	-	4,37,640	Ongoing
16	-	-	ABG/P/02/20-21	AB	-	44,60,400	44,60,400	-	6,80,400	-	6,80,400	-	37,80,000	Ongoing
17	74,354	-	APDP EM	EM	-		-	2,50,832		-	2,50,832	2,50,832	-	Ongoing
18	-	1,09,635	Diplomat & Demonstration Of New For Improved For Glass Ferozabad	EM	14,10,381		14,10,381	14,84,735		-	14,84,735	74,354	-	Ongoing
19	-	-	RDD/EM/P/01/MNRE/IIPGTP	EM	-	5,42,800	5,42,800	-	3,28,450	-	3,28,450		2,14,350	Ongoing
20	-	-	East Third Party Independent Evaluation-Em, (West Bengal & Sikim)	EM	72,80,848		72,80,848	71,71,153		-	71,71,153	-	1,09,695	Ongoing
21	-	34,567	RDD/EM/P/01/Boiler Workshops /2019-20	EM	-	22,73,860	22,73,860	-	22,73,860	-	22,73,860	-	-	Closed
22	-	-	West Third Party Independent Evaluation-Em. (Daman & Gujrat)	EM	93,68,588		93,68,588	93,34,021		-	93,34,021	-	34,567	Ongoing
23	-	-	ES/DIPP/05/2018-19	ES	7,89,420	-	7,89,420	3,58,858	4,30,562	-	7,89,420	-	-	Closed
24	-	-	ES/DIPP/P/02/2016-17	ES	38,80,100	-	38,80,100	15,04,436	23,75,664	-	38,80,100	-	-	Closed
25	-	-	ES/NCUI/06/2017-18	ES	4,80,000	-	4,80,000	4,70,616	9,384	-	4,80,000	-	-	Closed
26	-	26,41,079	ES/PROJ/MOT/14/2018-19	ES	-	29,38,200	29,38,200	-	29,38,200	-	29,38,200	-	-	Closed
27	-	2,09,518	HQ/ES/DIPP/07/2018-19	ES	32,70,096	24,53,102	57,23,198	6,28,997	11,97,714	-	18,26,711	-	38,96,487	Ongoing
28	-	3,18,954	HQ/ES/DOJ/ARS/05/2019-20	ES	3,80,000	7,42,000	11,22,000	1,70,482	9,51,518	-	11,22,000	-	-	Closed
29	-	3,74,480	HQ/ES/MOC/09/2019-20	ES	4,13,000	1,77,000	5,90,000	94,046	4,95,954	-	5,90,000	-	-	Closed
30	-	4,22,602	HQ/ES/MOC/11/2019-20	ES	4,57,934	1,96,258	6,54,192	83,454	5,70,738	-	6,54,192	-	-	Closed
31	-	6,53,508	HQ/ES/MOT/02/2018-19	ES	12,32,168	5,28,832	17,61,000	8,09,566	9,51,434	-	17,61,000	-	-	Closed
32	-	5,40,075	HQ/ES/MOT/06/2019-20	ES	11,45,544	17,18,316	28,63,860	4,91,946	23,71,914	-	28,63,860	-	-	Closed
33	-	4,53,713	HQ/ES/MOT/12/2019-20	ES	8,38,744	12,58,116	20,96,860	2,98,719	17,98,141	-	20,96,860	-	-	Closed
34	-	7,07,152	HQ/ES/PROJ/MOT/07/2019-20	ES	7,69,310	11,54,040	19,23,350	2,76,097	16,47,253	-	19,23,350	-	-	Closed
35	-	10,33,024	HQ/ES/PROJ/MOT/08/2019-20	ES	9,27,480	6,95,610	16,23,090	2,20,328	2,36,750	-	4,57,058	-	11,66,032	Ongoing
36	-	38,77,675	HQ/ES/PROJ/MOT/16/2019-20	ES	12,19,072	18,29,472	30,48,544	1,86,048	28,62,496	-	30,48,544	-	-	Closed
37	-	-	HQ/ES/DOJ/P/02/2020-21	ES	-	29,37,020	29,37,020	-	29,37,020	-	29,37,020	-	-	Closed
38	-	-	HQ/ES/DPIIT/P1/2020-21	ES	-	14,22,000	14,22,000	-	5,03,188	-	5,03,188		9,18,812	Ongoing
39	-	-	HQ/IE/P/05/2019-20	IE	49,22,370		49,22,370	10,49,695	4,69,996	-	15,19,691	-	34,02,679	Ongoing
40	-	4,82,804	HQ/IE/TRG/INTL/1/19-20	IE	-	44,25,000	44,25,000	-	44,25,000	-	44,25,000	-	-	Closed
41	-	2,68,908	HQ/IE/P/01/2019-20	IE	8,71,548	20,33,612	29,05,160	3,88,744	25,16,416	-	29,05,160	-	-	Closed
42	-	-	HQ/IE/P/01/2020-21	IE	-	30,55,988	30,55,988	-	10,72,479	-	10,72,479		19,83,509	Ongoing
43	-	-	HQ/IE/P/02/2020-21	IE	-	23,60,000	23,60,000	-	10,42,211	-	10,42,211		13,17,789	Ongoing
44			HQ/IE/P/03/2020-21	IE	-	15,32,230	15,32,230	-	4,36,134	-	4,36,134		10,96,096	Ongoing
45	-	-	HQ/IE/P/04/2020-21	IE	-	14,82,080	14,82,080	-	3,03,129	-	3,03,129		11,78,951	Ongoing
46	-	-	NPC/HQ/IE/P/06/2020-21	IE	-	34,00,000	34,00,000	-	5,19,639	-	5,19,639		28,80,361	Ongoing
47	1,02,221	-	RDD/EN/C/04/MOMA/18-19	EN	21,66,480		21,66,480	18,97,572	1,00,000		19,97,572		1,68,908	Ongoing
48	-	27,34,096	RDD/EN/P/01/DPCC/19-20	EN	1,06,867	8,06,925	9,13,792	2,09,088	2,59,332	-	4,68,420	-	4,45,372	Ongoing
49	-	45,300	RDD/EN/P/04/UNEP/19-20	EN	39,10,500	41,53,600	80,64,100	11,76,404	20,17,695	-	31,94,099	-	48,70,001	Ongoing
50	-	73,13,367	RDD/EN/P/05/DPCC/19-20	EN	64,900		64,900	19,800	45,100	-	64,900	-	-	Closed
51	-	-	RDD/EN/P/05/MOEFCC/18-19	EN	2,04,53,632	72,24,448	2,76,78,080	1,31,40,470	1,45,37,610	-	2,76,78,080	-	-0	Closed
52	-	9,00,000	RDD/EN/P/07/DPIIT/2019-20	EN	-	3,44,560	3,44,560	-	3,44,560	-	3,44,560	-	-	Closed
53	-	14,49,571	RDD/EN/P/01/UPPCB/20-21	EN	1,73,900		1,73,900	1,62,000	11,900	-	1,73,900	-	-	Closed
54	-	3,29,000	RDD/EN/P/06/MoEFCC/19-20	EN	33,67,200	60,88,053	94,55,253	19,17,629	13,00,103	-	32,17,732	-	62,37,521	Ongoing
55	-	-	RDD/EN/P/01/DOE/20-21	EN	-	23,89,500	23,89,500	-	19,36,400	-	19,36,400	-	4,53,100	Ongoing
56	-	-	RDD/EN/P/02/UNDP/20-21	EN	-	22,60,870	22,60,870	-	22,60,870	-	22,60,870	-	-	Closed
57	-	-	RDD/EN/P/03/DPIIT/2019-20	EN	-	1,57,766	1,57,766	-	3,15,480	-	3,15,480	1,57,714	-	Ongoing
58	-	-	RDD/EN/P/03/UNDP/2020-21	EN	-	16,93,536	16,93,536	-	18,59,388	-	18,59,388	1,65,852	-	Ongoing
59	-	-	RDD/EN/P/11/BEIL/2020-21	EN	-	5,60,500	5,60,500	-	5,60,500	-	5,60,500	-	-	Closed
60	-	-	RDD/EN/P/15/NOIDA/2020-21	EN	-	11,94,160	11,94,160	-	13,94,085	-	13,94,085	1,99,925	-	Ongoing
61	-	-	RDD/EN/P/16/WHO/20-21	EN	-	13,70,000	13,70,000	-	9,94,600	-	9,94,600	-	3,75,400	Ongoing
62	-	-	RDD/EN/P/17/MOPSW/20-21	EN	-	7,00,000	7,00,000	-	4,23,422	-	4,23,422	-	2,76,578	Ongoing
63	-	0	RDD/EN/P/02/MoSJ&E/19-20	EN	4,00,000	7,80,000	11,80,000	72,000	11,08,000	-	11,80,000	-	-	Closed
64	-	0	RDD/EN/P/13/MEITY/20-21	EN	-	13,31,040	13,31,040	-	-	-	-		13,31,040	Ongoing
[illegible]	-	0	RDD/HRM/P/01/17-18(CGPIYTM)	HRM/RD	4,79,50,380		4,79,50,380	4,79,50,380	-	-	4,79,50,380	-	0	Closed
[illegible]	-	-	Sda	GDNGR	68,60,918	-	68,60,918	48,74,389	1,35,939	18,50,590	68,60,918	-0	0	Closed
	12,09,096	4,63,07,232	Total		20,01,34,596	[illegible]	30,26,02,031	14,98,15,390	9,02,18,836	18,50,590	24,12,34,257	14,35,271	6,28,03,045	

Schedule No. 4 Fixed Assets

Consolidated-Fixed Assets Chart

S. No.	Description of Asset	COST					DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE	
		As on 1.4.2020	Addition during 1st Half	Addition during 2nd Half	Sale/Tr. Written off/CWIP into FA during the	Total as on 31.3.2021	Depreciation as on 1.4.2020	Depreciation duirng the year	Sale/Tr. Written off during the year	Total upto 31.3.2021	Written Down Value as on 31.3.2021	Written Down Value as on 31.3.2020
		1	2	3	4	5=(1+2+3-4)	6	7	8	9=(6+7-8)	10=(5-9)	11
A	NON PLAN											
1	Land	2,58,786	-	-	-	2,58,786	-	-	-	-	2,58,786	2,58,786
2	Building	1,10,07,314	-	-	-	1,10,07,314	61,09,500	4,89,781	-	65,99,281	44,08,033	48,97,814
3	Plant & Machinery	32,90,005	8,13,841	61,827	-	41,65,673	23,15,390	2,72,905	-	25,88,295	15,77,377	9,74,615
4	Electrical Equipments	23,16,464	65,400	16,654	27,290	23,71,228	10,57,166	1,96,139	-	12,53,305	11,17,923	12,59,298
5	Office Equipments	44,00,692	83,275	99,230	1,54,976	44,28,221	37,42,511	95,414	-	38,37,925	5,90,295	6,58,181
6	Computer	1,20,73,068	41,32,444	3,53,032	702	1,65,57,842	1,01,89,010	24,77,207	-	1,26,66,217	38,91,625	18,84,059
7	Furniture & Fixtures	68,14,682	1,60,208	6,34,311	5,169	76,04,032	30,21,912	4,26,496	-	34,48,409	41,55,623	37,92,770
8	Vehicles	34,15,225	-	-	-	34,15,225	26,45,311	1,15,485	-	27,60,795	6,54,430	7,69,914
9	Audiovisual Equipments	43,36,121	-	-	-	43,36,121	27,45,355	2,38,605	-	29,83,959	13,52,162	15,90,767
10	Books	35,91,831	10,776	360	12,473	35,90,494	35,65,888	9,771	-	35,75,658	14,836	25,943
11	Software	1,81,602	4,500	-	-	1,86,102	67,286	46,582	-	1,13,868	72,234	1,14,316
	TOTAL A (Non Plan)	5,16,85,790	52,70,444	11,65,414	2,00,610	5,79,21,038	3,54,59,328	43,68,386	-	3,98,27,714	1,80,93,324	1,62,26,462
B	PLAN											
1	Building	12,23,69,075	-	-	24,289	12,23,44,786	6,65,65,233	55,77,955	-	7,21,43,188	5,02,01,598	5,58,03,842
2	Plant & Machinery	8,22,44,717	-	-	5,085	8,22,39,632	6,76,30,841	21,91,319	-	6,98,22,160	1,24,17,472	1,46,13,876
3	Electrical Equipments	79,41,455	-	-	-	79,41,455	58,82,924	3,08,780	-	61,91,704	17,49,751	20,58,531
4	Office Equipments	2,39,27,726	-	-	-	2,39,27,726	1,57,18,531	12,31,379	-	1,69,49,910	69,77,816	82,09,195
5	Computer	7,33,17,957	1,54,976	-	-	7,34,72,933	7,30,52,587	1,68,139	-	7,32,20,725	2,52,208	2,65,370
6	Furniture & Fixtures	83,69,120	-	-	-	83,69,120	57,14,015	2,65,511	-	59,79,525	23,89,595	26,55,105
7	Vehicles	20,02,543	-	-	-	20,02,543	17,82,015	33,079	-	18,15,094	1,87,449	2,20,528
8	Audiovisual Equipments	33,38,238	-	-	-	33,38,238	26,91,629	96,991	-	27,88,620	5,49,618	6,46,609
9	Laboratory Equipments	8,000	-	-	-	8,000	2,654	802	-	3,447	4,553	5,347
10	Books	45,66,850	-	-	-	45,66,850	44,68,609	39,296	-	45,07,905	58,945	98,241
12	Software	95,24,634	-	-	-	95,24,634	95,14,812	2,456	-	95,17,268	7,367	9,822
13	Capital Work in progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	EPABX System	5,33,188	-	-	-	5,33,188	4,59,077	11,117	-	4,70,194	62,994	74,111
	TOTAL B	33,81,43,503	1,54,976	-	29,374	33,82,69,105	25,34,82,925	99,26,823	-	26,34,09,740	7,48,59,365	8,46,60,578
	(Total (A+B)	38,98,29,293	54,25,420	11,65,414	2,29,984	39,61,90,143	28,89,42,253	1,42,95,209	-	30,32,37,454	9,29,52,689	10,08,87,040

Schedule: 1 Capital Fund

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
Opening Balance as per Last Year Audited Balance Sheet*	32,46,63,578	32,65,64,894
Add : Asset Purchased from Grant Fund during the Year	-	1,66,400
Less : Depreciation on Asset donated by Japan**	17,57,558	20,67,716
Total	**32,29,06,020**	**32,46,63,578**

* Included asset donated by Japan Government in earlier years.
** Deprecation on WDV of Rs.11717055/- as on 01.04.2020 @ 15%

Schedule: 3 Current Liabilities & Provisions

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
A:Current Liabilities		
Sundry Creditors HQ	1,25,69,675	21,21,985
Sundry Creditors RDs	15,70,371	47,87,490
Others Payable-HQ	4,41,90,485	7,18,09,429
Others Payable-RDs	1,51,40,683	1,31,01,874
Unspent balance (Plan)	5,74,710	23,15,236
Advance from Vendor	73,31,326	65,10,870
Sub Total A	**8,13,77,251**	**10,06,46,884**
B:Provisions		
Leave Encashment		
As per last Account	9,44,53,628	-
Add : Provision during the year	2,74,62,054	9,44,53,628
Less: Payments during the year	1,40,99,626	-
Closing Balance	**10,78,16,056**	**9,44,53,628**
Gratuity		
As per last Account	14,60,18,762	15,43,29,463
Add : Provision during the year	65,71,079	1,89,49,359
Less: Payments during the year	2,54,90,008	2,72,60,060
Closing Balance	**12,70,99,833**	**14,60,18,762**
Sub Total B	**23,49,15,889**	**24,04,72,390**
Total (A+B)	**31,62,93,140**	**34,11,19,274**

Schedule : 5 Current Assets, Loans & Advances

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
Sundry Debtors		
I)Considered Good	4,51,38,965	2,44,99,459
ii)Considered Doubtful	1,73,11,052	1,38,94,435
Total Book Debts	**6,24,50,017**	**3,83,93,894**
Less: Provision for doubtful debts	1,73,11,052	1,38,94,435
Total Book Debts excluding Doubtfull Debts	**4,51,38,965**	**2,44,99,459**
Cash & Bank Balances		
i) SBI Bank	7,86,82,422	-
ii) Cash in Hand-RDs	-	9,171
iii) Indian Overseas Bank -RD PLAN	-	11,966
iv) Indian Overseas Bank /B-HQ-plan	7,88,494	32,63,725
v) Postage in Hand incl.F.M-HQ	-	-
vi) Postage in Hand incl.F.M.-RDs	12,243	449
vii) Indian Overseas Bank/B-HQ	6,64,37,133	10,36,15,117
viii) Indian Overseas Bank CC 850-HQ	1,64,84,952	12,132
ix) Indian Overseas Bank-II-RDs	1,36,45,992	1,22,58,608
Total	**17,60,51,236**	**11,91,71,167**
Gratuity & Other Investments		
i) Term Deposit (FDR)	15,44,29,965	12,48,93,894
Total	**15,44,29,965**	**12,48,93,894**
Loans & Advances		
i) Festival Advances to Staff-HQ	-	-
ii) Festival Advances to Staff-RDs	-	-
iii) Adv.Recov from Staff-HQ	12,08,127	8,31,937
iv) Adv.Recov. from Staff-RDs	4,11,621	21,08,276
v) Adv. Recov.from Others-RDs	-	1,50,000
vi) Others Recoverable	35,99,684	2,06,66,331
vii) Security Deposit/E.M-HQ	26,57,028	59,14,728
viii) Security Deposit/E.M.-RDs	17,31,455	13,01,958
ix) Others Recoverable H.Q./Misc	1,79,18,427	1,40,700
Total	**2,75,26,341**	**3,11,13,930**
T.D.S. (Recoverable)		
HQ	2,24,78,424	5,15,93,600
RDs	1,59,77,287	4,41,21,287
Total	**3,84,55,711**	**9,57,14,887**
Grand Total	**44,16,02,219**	**39,53,93,337**

Schedule: 6 Excess of Expenditure over Income

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
Opening Balance	15,02,54,047	13,51,30,548
LESS/ ADD		
Excess of income over Expenditure	1,57,57,977	1,51,23,499
Total	**16,60,12,024**	**15,02,54,047**

Schedule:7 Activity Revenue

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
Receipt from Consultancy & Training Programme	20,14,95,151	15,59,64,996
Self Run Programmes	80,31,128	4,32,60,056
Application Processing Fees	17,475	5,07,412
Total	**20,95,43,754**	**19,97,32,464**

Schedule:8 Receipts from Publication

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
Royalty from Publication	1,26,350	1,64,884
Total	**1,26,350**	**1,64,884**

Schedule:9 Other Receipts

Particulars	As at March 2021	As at March 2020
Interest receipt	1,32,77,678	1,09,57,464
Miscellaneous receipt	1,01,183	1,19,235
Rent receipt	1,61,71,576	1,29,98,819
Conference Hall charges	20,000	6,69,400
Interest Received on Income Tax Refund	46,73,075	41,28,495
Provision Written Back	4,58,155	-
Total	**3,47,01,667**	**2,88,73,412**

Schedule No:10 Employees Remuneration & Benefits

S.no	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2021	HQ	RDs	Total As at March 2020
1	Salary & Allowances/ Stipend	8,35,35,612	14,31,59,506	22,66,95,118	10,71,31,908	14,55,03,568	25,26,35,476
2	CPF (Council share)	2,16,76,278	-	2,16,76,278	2,49,42,017	-	2,49,42,017
3	Gratuity	65,67,605	-	65,67,605	1,89,49,359	-	1,89,49,359
4	Employee's Welfare & CGHS	17,53,507	23,07,491	40,60,998	23,47,736	28,56,889	52,04,625
5	Leave Encashment*	9,20,08,636	-	9,20,08,636	2,85,91,745	-	2,85,91,745
6	Canteen & Welfare	8,09,623	2,67,265	10,76,888	9,38,859	1,58,071	10,96,930
7	Compassionate Fund	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
	TOTAL	20,63,91,261	14,57,34,262	35,21,25,523	18,29,41,624	14,85,18,528	33,14,60,152

* During current FY 2020-21 Deferred Revenue Expenditure of Leave Encashment was expensed for Rs 6,45,46,582/-

Schedule No:11 Office & Administrative Expenses

S.no	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2021	HQ	RDs	Total As at March 2020
1	AMC & Maintainence	8,62,141	6,96,442	15,58,583	17,73,568	12,92,370	30,65,938
2	Audit Fees	1,50,000	-	1,50,000	1,50,000	-	1,50,000
3	Bldg.&House Keeping & rent	92,74,496	82,02,261	1,74,76,757	96,68,551	92,57,915	1,89,26,466
4	Development of Business Activity	14,82,521	2,39,983	17,22,503	35,99,900	6,10,541	42,10,441
5	Expert Fees/salary contract	1,63,40,479	49,24,316	2,12,64,795	1,45,75,640	31,52,330	1,77,27,970
6	Legal & Professional Charges	66,500	36,55,972	37,22,472	1,42,000	11,02,542	12,44,542
7	Printing & Stationery	10,54,093	4,07,347	14,61,440	27,87,123	9,66,904	37,54,027
8	Programme Activity Exp.	1,70,47,759	1,46,82,482	3,17,30,242	1,27,71,302	4,37,12,645	5,64,83,947
9	Promotional work in Hindi	5,64,706	2,000	5,66,706	1,03,097	47,455	1,50,552
10	MSME-LMCS Exp.	-	-	-	-	1,67,020	1,67,020
11	Telephone & Postage	6,53,483	3,97,881	10,51,364	7,92,938	11,76,791	19,69,729
12	Travelling Allowance/L.C./LTC.	89,57,475	30,40,126	1,19,97,601	78,30,623	74,85,914	1,53,16,536
13	Vehicle Maintenance	3,29,853	-	3,29,853	3,18,102	-	3,18,102
14	Rates and Taxes	-6,68,901	1,78,246	-4,90,655	7,94,750	33,018	8,27,768
15	Prior Period Adjustment	16,26,547	77,577	17,04,124	1,61,74,069	36,07,814	1,97,81,883
16	EMD Written off	-	-	-	27,550	1,47,178	1,74,728
17	Debtor Written Off	-	2,38,305	2,38,305	-	94,929	94,929
18	Swachchta Action Plan (SAP)	3,88,170	-	3,88,170	1,55,35,797	-	1,55,35,797
19	Provision for Doubtful Debts	34,16,617	-	34,16,617	21,40,561	-	21,40,561
20	Productivity Week Exp.	30,000	-	30,000	2,25,000	2,69,562	4,94,562
21	Water Charges arrears	-	-	-	48,68,309	-	48,68,309
22	ITC Reversal (GST Exempt Supply)	-	-	-	2,40,994	4,57,096	6,98,090
	TOTAL	6,15,75,939	3,67,42,939	9,83,18,878	9,45,19,873	7,35,82,023	16,81,01,897

Schedule No:12 PLAN PROJECTS EXPENDITURE

S. No	Item of Expenditure	As at March 2021	As at March 2020
PROJECT BASED SUPPORT TO AUTONOMUOUS INSTITUTIONS			
1	Upgration Of Aip Into Centre Of Exc ((Project Based Support To Autonomous Institutions - New Scheme 2017-18)	-	25,76,149
2	COE For It For Industry 4.0(2018-2019)	-	11,04,668
3	COE On Quality Management (Coe-Qm)	1,19,634	3,92,000
4	COE For It For Industry 4.0(2018-2019)	-	11,11,088
5	COE For It For Industry 4.0(2019-2020)	11,84,670	-
6	COE For It For Industry 4.0(2020-2021)	15,69,708	-
7	COE On Quality Management	6,86,514	-
		-	
	TOTAL	35,60,526	51,83,905

Schedule No 13 Miscellaneous & Other Charges

S. No	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2021	HQ	RDs	Total As at March 2020
1	Misc.Expenses	7,736	36,333	44,070	2,92,842	1,43,840	4,36,682
2	Loss on sale of assets	-	-	-	8,329	-	8,329
3	Subscription to Journal/Periodical	70,533	-	70,533	1,13,348	27,403	1,40,751
	TOTAL	78,269	36,333	1,14,603	4,14,519	1,71,243	5,85,762

Schedule No:14 Interest & Finance Charges

S.no	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2021	HQ	RDs	Total As at March 2020
1	Bank charges	3,50,381	27,712	3,78,093	5,86,227	28,434	6,14,662
	TOTAL	3,50,381	27,712	3,78,093	5,86,227	28,434	6,14,662

*** Bank charges includes Interest charges

Schedule No:15 International Cooperation

hba	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2021	HQ	RDs	Total As at March 2020
1	APO Programme	-	-	-	1,13,432	49,442	1,62,874
	TOTAL	-	-	-	1,13,432	49,442	1,62,874

Schedule No 16: Notes to the Accounts for the year ending on 31st March 2021

A. GENERAL

i) Previous year figures have been regrouped and rearranged to the extent required.
ii) Schedule No 1 to15 forms integral part of accounts.

B. BALANCE SHEET

i) All the balance of Sundry Debtor, Sundry Creditor, advance recoverable, advance payable, security balance lying / payable with / to various agencies / parties outstanding as on 31.03.2021 are subject to confirmation from Parties and reconciliation.
ii) Schedule 2: Project account relates to projects sponsored by various agencies.
   a) Net Credit Balances : Receipts minus Capital and Revenue Expenditure.
   b) Net Debit Balances : Capital and Revenue Expenditure minus Receipts.
iii) Provision for Gratuity have been made during the year amounting to Rs. 65,71,079/- (Previous Year 1,89,49,359/-)
iv) Fixed Assets Register at HQ is available in two parts i.e. prior to 17-10-2005 and the subsequent one from 17-10-2005 in revised GRF format. Certain fixed assets were disposed off in earlier years but the sale proceeds were treated as receipts in Income & Expenditure Account instead of crediting the same to the cost of assets sold and writing off balance written down value of those assets, however may have small difference in the gross & net blocks, which could be adjusted through proper procedures. During the year, no adjustment was made by the Council in this regard.
v) During the FY 2020-21 physical verification of Fixed Assets at 12 RDs &HQhas been conducted.

C. PROVISIONS

i) During current FY 2020-21 balance of Deferred Revenue Expenditure of Leave Encashment was treated as an expense amounting to Rs. 6,45,46,582/-
ii) Provision for implementation of MACP in NPC amounting to Rs. 25,00,000/-was made during 2015-16. (Previous Year 25,00,000/-)
iii) Provision of Rs.4,46,76,989/- has been made during the FY 2018-19 towards payment of arrears one time increment arrears consequent upon implementation by Ministry of Finance, Dep't of Expenditure OM No.10/02/2011-III/A dated 19/3/2102 out of which 2,30,47,408/- was paid during the current FY 2020-21 and balance is carried forwarded .

D. CONTINGENT LIABILITIES

i) Bank Guarantee of Rs 173.32 Lakhs (Previous Year Rs206.28 Lakh)furnished in favour of clients against consultancy jobs.

ii) There is a CPC (TDS) communication regarding defaults in TDS statements for the earlier Assessment Years amounting to Rs. 10,94,420/- as per online TDS portal of Income Tax Department in the name of the Council which is under reconciliation.

iii) The Council has received a notice from Telengana State Housing board for arrears of rent of Hyderabad RD for Rs 1,00,37,846/- (Consisting of Rent 68,08,509/- and Interest 32,29,336/-) out of which provision has been made for Rs 68,08,509/- during the FY 2019-2020 and for interest a request has been sent to the competent authority of Telengana State housing board for waiving of above interest amounting to Rs. 32,29,336/-.

E. LEASING OUT OF GROUND &FIRST FLOOR OF HQ BUILDINGAND AT 705, BHIKAJI CAMA BHAVAN, BIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI.

i) First floor of HQ building was leased out to Regional Centre for Biotechnology, NCR, Biotech Science Cluster, Bhankri, Faridabad for amount of Rs. 1,18,31,216/-, Some area of ground floor was leased out to Institute Of Life Sciences for Rs 25,76,760/- and 705, Bhikaji Cama Bhavan, Bhikaji Cama Place, New Delhi was leased out to United India Insurance Company Limited for Rs.17,28,000/- duringthe FY 2020-21.

F. OTHERS

i) The Council has bank accounts in various RDs and HQ. All these accounts are duly reconciled.

ii) The Council has outstanding recovery of Income Tax Refundable (TDS) of Rs. 84.35Lakhsas on 31/03/2021. The Council is hopefull for recovery of above amount pertaining to AY 2015-16 and earlier years where income tax assessments have been completed. The Council is trying to recover these old refunds from income tax department.

iii) Current liabilities include provision for gratuity of Rs. 1270.99 Lakhs as on 31.03.2021(Previous Year Rs. 1460.19 lakhs) as per Certificate of Actuarial Dr. V. P. Sabharwal. Moreover, the Council has earmarked FDR for Rs. 621.16Lakhs (Rs.575.99 lakhs) lying with IOB.

iv) The Books Debts amounting to Rs. 6,24,50,017/- outstanding as on 31.03.2021 include book debts amounting to Rs. 1,73,11,052/- older than three year. The Council has created the provision for doubtful debts amounting to Rs. 1,73,11,052/- till current financial year.

v) During the year, a sum of Rs. 73.31 Lakhs was received in Saving Bank account of Council from various parties. In the absence of identification, the above amount was kept under the head advance- as on 31.03.2021 the Council has shown it as consultancy income in GST Returns & also paid GST thereon from its own fund without identifying / reconciling the parties.

vi) During the Financial Year 2020-21 under Audit, in HQ & RDs there is a missing credit in 26AS towards Income Tax Deducted at source of Rs. 9,61,628/- as on 31.03.2021 which is under reconciliation.

vii) Current liabilities include Rs 2,59,952/- as APO advance. This amount received from Asian Productivity Organisation for expenditure purpose during the FY 2019-20.

viii) Current liabilities include Rs 1,42,928/- for past years due to court case. This amount was payable to various societies against which court cases are going on.

ix) The Council had received Rs 68,60,918/- from Swedish International Authority in past years against which fixed assets were already purchased.

Group Head (Finance)

डा. रजत शर्मा / Dr. Rajat Sharma
निदेशक (प्र.प्र. एवं प्रशिक्षण) / Director (T.M. & Training)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत)
(Under Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)
लोधी रोड, नई दिल्ली / Lodhi Road, New Delhi-110003

Director General

N. K. CHANJI
Director General
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
Department for Promotion of Industry & Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry
Government of India, New Delhi

DETAIL OF SUNDRY CREDITORS							
AS AT 31.3.2021							
		As at March 2021			As at March 2020		
S.No.	Head	HQ	RMPG	Total	HQ	RMPG	Total
A	Sundry Creditor	1,25,69,675	15,70,371	1,41,40,046	21,21,985	47,87,490	69,09,475
		1,25,69,675	**15,70,371**	**1,41,40,046**	**21,21,985**	**47,87,490**	**69,09,475**
B	OTHERS PAYABLE						
1	Salary Payable	26,95,305	-	26,95,305	25,30,522	-	25,30,522
2	Rent Payable	-	69,40,453	69,40,453	-	71,77,666	71,77,666
3	CFC	30,297	-	30,297	34,237	-	34,237
4	CPC Payable (6th & 7th)	2,16,29,581	-	2,16,29,581	4,46,76,989	-	4,46,76,989
5	TDS Payable	7,62,166	16,75,203	24,37,369	2,46,600	6,07,329	8,53,929
6	GST Payable	33,27,980	12,97,038	46,25,019	21,86,335	14,79,485	36,65,820
7	Retention Money	-	3,00,501	3,00,501	-	11,04,944	11,04,944
8	Earnest Money / Security	56,10,941	8,04,443	64,15,384	50,70,012	-	50,70,012
9	Council Share Payable	8,20,311	-	8,20,311	19,38,174	-	19,38,174
10	Professional Tax	-	29,540	29,540	-	1,815	1,815
11	Expense Payable	34,13,033	40,93,505	75,06,538	86,67,891	27,30,635	1,13,98,526
12	NPC T/C Society	5,119	-	5,119	5,31,343	-	5,31,343
13	Court Case Recoveries	18,30,604	-	18,30,604	18,30,604	-	18,30,604
14	Court Case Deduction	1,41,928	-	1,41,928	-	-	-
15	Other Payable	39,23,220	-	39,23,220	40,96,722	-	40,96,722
	TOTAL	**4,41,90,485**	**1,51,40,683**	**5,93,31,168**	**7,18,09,429**	**1,31,01,874**	**8,49,11,303**

DETAIL OF SUNDRY DEBTORS							
AS AT 31.3.2021							
		As at March 2020			As at March 2020		
S.No.	Head	HQ	RD	Total	HQ	RD	Total
A	Specialist Charges	2,47,66,920	3,76,83,096	6,24,50,017	1,47,68,985	2,36,24,909	3,83,93,895
	TOTAL	2,47,66,920	**3,76,83,096**	6,24,50,017	1,47,68,985	**2,36,24,909**	3,83,93,895
B	OTHERS RECOVERABLE						
1	Group Insurance	-	-	-	715	-	715
2	Retention Bank a/c	-	6,97,744	6,97,744	-	6,97,744	6,97,744
3	Programme A/c	77,53,775	-	77,53,775	1,05,43,339	-	1,05,43,339
4	Ashok Petronet	-	-	-	75,954	-	75,954
5	Prepaid Expenses	10,34,388	3,33,177	13,67,565	3,19,300	3,28,994	6,48,294
6	Interest Accrued on Fixed Deposits	90,40,210	-	90,40,210	87,00,286	-	87,00,286
7	Misc debtor	90,054	7,566	97,620	-	-	-
		1,79,18,427	**10,38,487**	**1,89,56,914**	**1,96,39,593**	**10,26,738**	**2,06,66,331**
	TDS AY OUTSTANDING						
	TDS AY 2006-07	87,774	13,89,437	14,77,211	87,774	13,89,437	14,77,211
	TDS AY 2007-08	14,54,888	16,44,615	30,99,503	14,54,888	16,44,615	30,99,503
	TDS AY 2010-11	7,41,136	-	7,41,136	7,41,136	-	7,41,136
	TDS AY 2011-12	12,78,978	-	12,78,978	12,78,978	-	12,78,978
	TDS AY 2012-13	9,43,550	-	9,43,550	9,43,550	-	9,43,550
	TDS AY 2013-14	11,296	-	11,296	11,296	-	11,296
	TDS AY 2014-15	2,43,631	-	2,43,631	2,43,631	-	2,43,631
	TDS AY 2015-16	6,40,051	-	6,40,051	6,40,051	-	6,40,051
	TDS AY 2016-17	-	-	-	63,72,631	83,41,628	1,47,14,259
	TDS AY 2017-18	-	-	-	89,89,295	77,03,369	1,66,92,664
	TDS AY 2018-19	-	-	-	1,09,61,186	79,16,030	1,88,77,216
	TDS AY 2019-20	-	-	-	95,70,763	98,63,620	1,94,34,383
	TDS AY 2020-21	1,02,98,421	72,68,558	1,75,66,979	1,02,98,421	72,62,588	1,75,61,009
	TDS AY 2021-22	67,78,699	56,74,677	1,24,53,376	-	-	-
	TOTAL	**2,24,78,424**	**1,59,77,287**	**3,84,55,711**	**5,15,93,600**	**4,41,21,287**	**9,57,14,887**

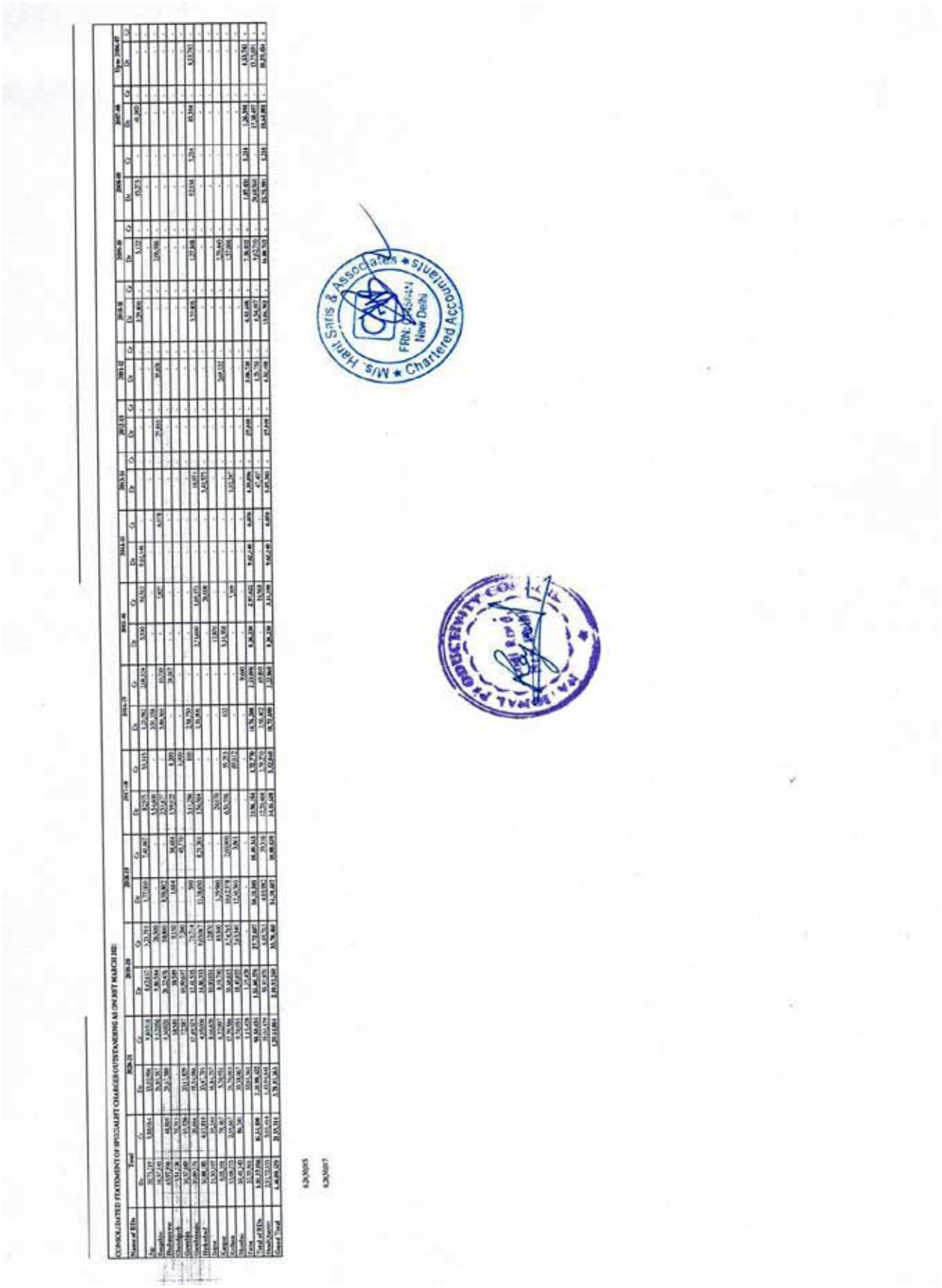

NPC HQ and Regional Offices' Address

NPC HEADQUARTER

National Productivity Council,
Utpadakta Bhavan, 5-6 Institutional Area
Lodhi Road, New Delhi – 110003
Email: npcinfo@npcindia.gov.in
Tel: 011-24690331

NPC REGIONAL DIRECTORATES

National Productivity Council,
2nd Floor, Abhaya Complex
KSDB Building, 55, Risaldar Street
Seshadripuram, Bangalore 560 020
Email: bangalore@npcindia.gov.in
Tel: 080-23467294

National Productivity Council,
RajgarhRoad, P.B. No. 32, Ulubari P.O.
Guwahati, Assam – 781 007
Email: guwahati@npcindia.gov.in;
Tel: 0361-2453396

National Productivity Council,
A/7, Surya Nagar,
Bhubaneswar – 751003, Odisha
Email: bhubaneshwar@npcindia.gov.in;
Tel: 0674-2397381

National Productivity Council,
10th Floor, Eastern Wing
GaganVihar Complex, M.J. Road, Nampally
Hyderabad, Andhra Pradesh -500001
Email: hyderabad@npcindia.gov.in;
Tel: 040-24733473

National Productivity Council,
SCO 40 (1st Floor), Sector-7 C
MadhyMarg, Chandigarh – 160019
Email: chandigarh@npcindia.gov.in
Tel: 0172-2794108

National Productivity Council,
SB-96, JawaharLal Nehru Marg, Bapu Nagar,
Jaipur – 302 004
Email: jaipur@npcindia.gov.in;
Tel:0141-2702935

Dr.Ambedkar Institute of Productivity, Chennai
No. 6, SIDCO Indl. Estate Amabattur
Chennai, Tamil Nadu – 600098
Email: aip@npcindia.gov.in;
Tel: 044-26255216

National Productivity Council,
4th Floor, KabirBhavan,
(U.P.H.C. Ltd.'s building,
Directorate of Industries (U.P.) Campus)
G.T. Road Kanpur – 208 002
Email: kanpur@npcindia.gov.in;
Tel: 0512-2224176

National Productivity Council,
9, Syed Amir Ali Avenue, Park Circus, Kolkata,
West Bengal – 700017
Email: kolkata@npcindia.gov.in;
Tel: 033-22876069

National Productivity Council,
Novelty Chambers, 7th Floor, Grant Road
Mumbai, Maharashtra – 400007
Email: mumbai@npcindia.gov.in;
Tel: 022-23002924

National Productivity Council,
2nd Floor, SudamaBhawan
Boring Road Crossing, Patna, Bihar – 800001
Email: patna@npcindia.gov.in;
Tel: 0612-2558311

National Productivity Council,
UtpadaktaBhavan, 5-6 Institutional Area
Lodhi Road, New Delhi – 110003
Email: delhi@npcindia.gov.in
Tel: 011-24607343

National Productivity Council,
Gandhi Nagar, Gujarat – 382028
Email: gandhinagar@npcindia.gov.in
Tel: 079-23287344